C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. VIII, Third Session, 2020/1941 (Saka)
No. 21, Thursday, March 19, 2020/Phalguna 29, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 361 to 367, 369 and 380	11-71
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 368 and 370 to 379	72-108
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	109-669

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 671-676

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 677

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

316th Report 677

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Resuming of service of Budh-Purnima Express (14224/14223) and demand for 100 per cent refund of cancellation fee 686-687, 692

MATTERS UNDER RULE 377 698-709

(i) Need to declare Manjhi Garh and Karah Garh in Saran district, Bihar as heritage sites and develop them as tourist places

Shri Janardan Singh Sigriwal 698

(ii) Need to establish a Central Agriculture University in Santhal Pargana region of Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 698-699

(iii) Regarding establishing a Nepali Language Council

Shri Raju Bista 699

(iv) Need to resume the construction of bypass road in Gumla city in Jharkhand

Shri Sudarshan Bhagat 700

(v) Need to expedite construction of Ramganj Mandi - Bhopal railway line

Shri Dushyant Singh 701

(vi) Need to run a superfast train from Guna Parliamentary Constituency to Delhi

Dr. Krishnapalsingh Yadav 701

(vii) Need to conduct a fresh survey to include all eligible people under Ayushman Bharat Yojana

Shri Jugal Kishore Sharma 702

(viii) Regarding water related problems being faced by farmers

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil 702

(ix) Need to include more hospitals in Surat, Gujarat in the panel of hospitals under Pradhan Mantri Relief Fund

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 702-703

(x) Need to include certain castes of Chhattisgarh in the list of Schedule Castes

Shri Mohan Mandavi 703

(xi) Need to construct roads in villages under Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 703-704

(xii) Need to develop Ganga river front in Farrukhabad, Uttar Pradesh

Shri Mukesh Rajput 704

(xiii) Need for appointment of computer teachers in schools

Shri Ram Kripal Yadav 704-705

(xiv) Need to take adequate measures in hospitals to tackle Corona virus menace in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ramdas Tadas 705

(xv) Need to conserve our environment, water and wildlife

Shri Jasbir Singh Gill 706

(xvi) Regarding testing facilities in National Institute of Virology, Alappuzha and Institute of Advance Virology, Thiruvananthapuram

Shri K. Muraleedharan 706

(xvii) Raised a matter regarding MSP for Pulses and Millets

Shri Pocha Brahmananda Reddy 707

(xviii) Regarding redevelopment of old and dilapidated buildings in Mumbai

Shri Arvind Sawant 707

(xix) Need to take adequate measures to prevent outbreak of Corona virus in Gaya Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Vijay Kumar 708

(xx) Regarding need to bring back Indian medical students stranded in Philippines

Shri Hanuman Beniwal 708

(xxi) Regarding establishing a Kendriya Vidyalaya in Mettupalayam area of Coimbatore district

Shri A. Raja 709

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA BILL, 2020 710-791

Motion to Consider 710-791

Shri Shripad Naik 710-711, 779-782

Dr. Shashi Tharoor 712-720

Shrimati Poonamben Maadam 721-725

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 726-728

Shrimati Pratima Mondal 729-731

Shri Raghu Rama Krishna Raju 732-733

Shri Vinayak Bhaurao Raut 734-735

Shri Kotha Prabhakar Reddy 736

Shri Vijay Kumar 737

Shri Ramesh Chandra Majhi 738

Shri Ram Shiromani 739

Dr. Bharatiben D. Shiyal 740-741

Dr. Amol Ramsing Kolhe 742-743

Adv. Ajay Bhatt 744-745

Shri E.T. Mohammed Basheer 746-747

Dr. Pritam Gopinathrao Munde 748-749

Shri Anto Antony 750-751

Dr. Sujay Vikhe Patil 752

Shri P. Raveendranath Kumar	753-754
Shri N.K. Premachandran	755-756
Dr. Satyapal Singh	757-759
Shri M. Selvaraj	760-761
Shri Thol Thirumaavalavan	762-763
Shri Sumedhanand Saraswati	764-765
Shri Thomas Chazhikadan	766
Shri Ramcharan Bohra	767
Shri M.K. Raghavan	768
Shrimati Sunita Duggal	769
Shri Bhartruhari Mahtab	770
Dr. Dhal Singh Bisen	771-772
Shri Kodikunnil Suresh	773
Shri Tapir Gao	774
Shri Bhagwant Mann	775
Shri DNV Senthilkumar S.	776
Sushri S. Jothimani	778
Clauses 2 to 31 and 1	785-791
Motion to Pass	791

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

15th Report	807

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 826

Member-wise Index to Unstarred Questions 827-832

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 833

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 834

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, March 19, 2020/Phalguna 29, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 361, श्री सुमेधानन्द सरस्वती।

(Q. 361)

माननीय अध्यक्ष : आज बड़ा खुशमिजाज माहौल है, आज सबको एलाऊ किया जाएगा।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मैं विशेष तौर से यह पूछना चाहूंगा कि खास तौर से जो गोबर गैस के प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो गोबर से और अवशिष्ट से चलते हैं, वे पुरानी तकनीक से बनते हैं। वे प्राय: ईंट और सीमेन्ट से बनते हैं। उसमें मिट्टी और गोबर नीचे में जम जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वे खराब हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा किसान उसे नहीं लगाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि इसके संदर्भ में क्या कोई नई तकनीक खोजी गई है, जिससे वे प्लांट्स खराब न हों और किसान व दूसरे लोग उसका लगातार उपयोग करते रहें? क्या इसके संदर्भ में कोई विशेष सहयोग देने का भी प्रावधान है?

श्री आर. के. सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारे मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दो-तीन तरह के मॉडल्स स्वीकृत किए गए हैं। एक है, फिक्स्ड डोम गैस होल्डर बायोगैस प्लांट। दीनबंधु - फिक्स्ड डोम विथ ब्रिक बेसनरी कंस्ट्रक्शन, इसके तीन-चार वैरिएंट्स हैं, जैसे प्री-फैब्रिकेटेड आर.सी.सी. डोम मॉडल, सॉलिड स्टेट दीनबंधु – फिक्स्ड डोम। फिर फ्लोटिंग डोम के भी कुछ डिजाइंस, जो कि के.वी.आई.सी. के द्वारा तैयार किए गए हैं, उन्हें भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है, जैसे के.वी.आई.सी. फ्लोटिंग स्टील मेटल गैस होल्डर विथ ब्रिक मैसनरी डाइजेस्टर, के.वी.आई.सी. फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप विथ फेरो सीमेन्ट डाइजेस्टर, के.वी.आई.सी. डिजाइन बायोगैस प्लांट विथ फाइबर ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, प्रगति मॉडल बायोगैस प्लांट्स,

के.वी.आई.सी. डिजाइन टाइप डाइजेस्टर विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर मेड-अप ऑफ एच.पी.डी.पी.ई., पी.वी.सी., एफ.आर., आर.ए.सी.। उसके बाद फिर प्रिफैब्रिकेटेड मॉडल बायोगैस प्लांट्स को भी हम लोगों ने मंजूरी दी है, प्रिफैब्रिकेटेड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डाइजेस्टर्स विथ फ्लोटिंग ड्रम गैस होल्डर्स होते हैं। एक नया बैग-टाइप बायोगैस प्लांट निकला है। उसे फ्लेक्सी मॉडल कहते हैं। उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह प्रावधान रखा है कि अगर और भी कोई नया टाइप आएगा तो उसको भी हम लोग स्वीकृति देंगे।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाह रहा था कि जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने आठ लाख गरीब परिवारों को 'उज्ज्वला' योजना के माध्यम से नि:शुल्क गैस कनेकशंस दिए थे, तो क्या सरकार की कोई योजना है कि बायोगैस प्लांट को भी इसी तरह से एक अभियान के रूप में लिया जाए और उसका एक विशेष प्रावधान किया जाए क्योंकि इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और देश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा।

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग इसके लिए जो सब्सिडी देते हैं, वह करीब 41 प्रतिशत के आस-पास है। हम लोग जो टारगेट देते हैं, वह राज्य सरकारों से बातचीत करके ही देते हैं और राज्य सरकार की मांग के अनुसार ही देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद हम राज्य सरकार से वार्ता करके जितना टारगेट देते हैं, उतना भी अचीव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसे एक नई स्फूर्ति देने के लिए हमें राज्य सरकार के साथ विमर्श करना होगा और इसे एक नई स्फूर्ति देने की आवश्यकता है।

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में Scheme to Support Promotion of Biomass-Based Cogeneration in Sugar Mills की बात की है। इंडिया में जितने भी शुगर मिल्स हैं, वे अभी पूरी तरह से मुश्किल में है। उसके बायोमास को शुगर मिल्स के साथ, अगर मान लीजिए पावर प्लांट को भी कनेक्ट कर दें, क्योंकि यह फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री है। फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री की वजह से उसकी प्रॉपर पॉलिसी लेकर आना चाहिए। जिस शुगर मिल का

पावर प्लांट रहेगा, उस पावर प्लांट को लाँग टर्म पी.पी.ए. जिस तरह बाकी लोगों को दे रहा है, उसी तरह से उसमें पी.पी.ए. दे देने से वह शुगर प्लांट बचा रहेगा। इसकी वजह से फार्मर्स को भी जरूर कुछ बेनिफिट मिलेगा। आज के दिन इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर फार्मर्स पूरी तरह से सफरर हो रहे हैं।

मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो भी स्कीम है, वह स्कीम इम्प्लिमेंटेशन में नहीं है। उसको बड़े दिल से फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए, एक अच्छा स्कीम बना दीजिए, जिसे सभी स्टेट्स इम्प्लिमेंट करें।

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की योजना है। हम लोग बायोगैस को-जेनरेशन के लिए सब्सिडी देते हैं। उसके अंतर्गत हमारी अचीवमेंट भी है। अभी तक बायोगैस कोजेनरेशन बायोमास पावर मिलाकर 9,186 मेगावाट की कैपेसिटी की हमने स्थापना की है। इसके अंतर्गत हमारी योजना भी चल रही है। इस साल भी करीब 20 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 9 की हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है। यह हमारा कार्यक्रम है और यह अच्छी तरह से चल रहा है। इसको हम लोग और आगे चलाएंगे। We have an ongoing programme for this and that programme is doing very well.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संघमित्रा मौर्या- उपस्थित नहीं।

(Q. 362, 369 and 380)

श्री छतरसिंह दरबार: अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। माननीय मंत्री जी ने अपने दिए गए उत्तर में स्वच्छ ऊर्जा के लिए उठाए गए सभी कदमों का विस्तार से उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में माननीय मंत्री द्वारा किए गए विकासपरक प्रयासों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पाद हेतु ग्रामीण तथा किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु, क्या इसमें आने वाले व्यय का कम से कम 80 प्रतिशत वित्त पोषक करने का इरादा रखती है? जिससे स्वच्छ ऊर्जा हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे इस महत्वाकांक्षी प्रयासों को और लोकप्रिय बनाया जा सके।

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आ रहे हैं। उसके अंतर्गत किसान अपने बंजर भूमि पर सोलर पैनल्स लगा सकेंगे और जो बिजली पैदा होगी, उसे हम खरीद लेंगे। इससे किसानों की इनकम में बहुत बढ़ोत्तरी होगी। प्रति एकड़, प्रति वर्ष कम से कम 60,000 रुपये महीना किसान को इनकम होगी, सिर्फ उनकी जमीन की उपलब्धता के कारण।

इसके अतिरिक्त, हम लोग 'कुसुम' के अंतर्गत सोलर पंप की स्कीम लेकर आए हैं। उसके अंतर्गत 80 प्रतिशत तो नहीं, 60 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था है। 30 परसेंट हम देंगे और 30 परसेंट राज्य सरकार देगी। बाकी जो 40 परसेंट है, उसमें 30 परसेंट हम लोन दिलवा देंगे। किसान का सिर्फ 10 प्रतिशत लगेगा। यह स्कीम बहुत पॉपुलर होने वाली है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब लोग आपस में बातचीत न करें।

सुरेश जी, सदन में प्रश्न काल के समय इतनी आवाज नहीं आनी चाहिए।

श्री छतरसिंह दरबार: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेन्ट्री है कि मेरा संसदीय क्षेत्र धार, मध्य प्रदेश 100 परसेंट आदिवासी, ग्रामीण आदिवासी, साथ ही 70 प्रतिशत पहाड़ी तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। क्या सरकार गरीब किसानों, गरीब आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को उपरोक्त सौर ऊर्जा की नि:शुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त योजना तैयार कर रही है?

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क ऊर्जा प्रदान करने की हमारी अभी कोई योजना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अगर आपकी सहमति हो तो प्रश्न संख्या 369 और 380 को भी इस प्रश्न के साथ क्लब कर दिया जाए?

श्री आर. के. सिंह: सर, ठीक है।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खेती की सिंचाई हेतु सरकार की स्वच्छ ऊर्जा के लिए चलित पंप लगाए जाने की योजना है। पंपों पर होने वाले खर्च के बारे में आपने बताया कि कुछ प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी और कुछ प्रतिशत राज्य सरकार और बाकी खर्चे किसान लाभार्थी वहन करेंगे। लेकिन, जहां पर्वतीय क्षेत्र है, फॉरेस्ट विलेजेज हैं, वहां किसानों की हालत और आम जनता की हालत बहुत दयनीय है। वहां बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है और बिजली के बिना विकास संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे एरिया में किसानों को सिंचाई हेतु

और आम जनता के जल आपूर्ति हेतु मिनिमम चार्ज लेकर क्या सरकार सौर ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की कोई योजना बना रही है?

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर पॉजिटिव है। एक तो जैसा हमने कहा कि अभी किसान को मात्र 10 प्रतिशत देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की एक ग्रिड कनेक्टेड योजना है, जिसमें किसान का जो 10 प्रतिशत है, उसके अंतर्गत उस राशि को भी हम लोन से दिलवा सकते हैं। किसान जो अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को सप्लाई करेगा, उससे उस ऋण की भरपाई हो जाएगी। यह व्यवस्था कुछ प्रान्तों ने प्रारंभ कर दी है। जैसे हरियाणा और गुजरात ने प्रारंभ कर दिया है तो वहां भी संभव हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 369, श्रीमती केसरी देवी पटेल – उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 380, डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती – उपस्थित नहीं।

श्री मनीष तिवारी जी।

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Speaker, Sir, my Supplementary pertains to Question No. 362. The classical trajectory or the energy mix is hydrocarbons, intermediates and renewables. I would like to know from the hon. Minister, over the past five and a half years from 2014 to 2020, how much has this mix changed in the case of India? In other words, how much have hydrocarbons or intermediates gone down and how much have renewables gone up as a per centage of the total energy which is produced and consumed in the country?

श्री आर. के. सिंह: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वर्ष में रिन्यूएबल एनर्जी का जो अंश है, जिसको हम ग्रिड में दे रहे हैं, वह 9.89 परसेंट है। ये गत वर्ष 9.21 परसेंट था। उसके पहले इससे भी कम था। पिछले पांच वर्षों में हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है। अगर हम हाइड्रो को छोड़ दें

तो हम लोगों ने लगभग 50,000 मेगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पिछले पांच वर्षों में जोड़ी है। हम चेंज कर रहे हैं। हाइड्रो पावर में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है। अब हमारी उत्पान क्षमता 40,000 मेगावाट्स से 45600 मेगावाट हो गई है और हम करीब 12,973 मेगावाट उत्पादन क्षमता हाइड्रो में और जोड़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी उत्पादन क्षमता 86,000 मेगावाट हो गई है। इसके अतिरिक्त करीब 35,000 मेगावाट अभी निर्माणाधीन है। हमारा क्लीन एनर्जी का जो एडिशन है, वह हाइड्रो, विंड एंड सोलर दोनों में चल रहा है और अच्छी तरीके से चल रहा है।

(Q.363)

SHRI A. GANESHAMURTHI : Thank you, hon. Speaker, Sir.

The Ministry of Youth Affairs and Sports is giving cash awards to individual sportspersons, after winning gold medal, silver medal, and so on, in various sports events like Olympic Games, Asian Games, and Commonwealth Games but many talented youths are hailing from rural areas and they do not have enough money to buy requisite sports materials like sports shoes and such other things. So, I would like to ask the Minister, through you, whether necessary action will be taken to give cash incentives to those talented sportspersons who play at the school level, the district level, and the State level.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, the hon. Member has rightly stated that we give focus to the rural areas. Under the Khelo India Scheme, when we identify young players at a very young age and they are selected and admitted in any of the SAI sports training centres, we provide them stipend. We not only take care of their accommodation and other needs but we also provide facilities like coaching and training; and on top of that, a stipend is provided to all the young athletes who are identified and selected for the training camps.

In the last few months, we have taken many important decisions where the young talents are being properly monitored and we are trying to increase

the base so that we can sufficiently have talented young players in our training centres.

SHRI A. GANESHAMURTHI: My second supplementary is this. At present only very few recognised national sports federations are functioning in Tamil Nadu. There is no Sports Authority of India training centre in the southern parts of Tamil Nadu. Further, there is only one Kabaddi Federation functioning in Jaipur. So, I request the hon. Minister of Youth Affairs and Sports to set up a Kabaddi Federation in Tamil Nadu, particularly at Erode district for the benefit and convenience of the kabaddi players from the entire south Indian region and also Sports Authority of India training centre in the southern part of Tamil Nadu, that is, at Tirunelveli to enable more youths from rural areas to excel in sports activities.

SHRI KIREN RIJIJU: I have visited Tamil Nadu twice. Traditionally, Tamil Nadu has a great sporting culture. I have visited some of the centres where our Ministry is giving funds. There are traditional sports also in Tamil Nadu, as the hon. Member has mentioned. We are promoting indigenous sports also. In the hill region of Tamil Nadu, there is a high altitude training centre. We are planning to support that also. It is not that we are not supporting. There are various other activities going on in Tamil Nadu. Tamil Nadu is known as a very active State in terms of promoting sports. We will give further support to Tamil Nadu.

SHRI T. R. BAALU: His specific question is about Erode. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.आर. बालू जी, मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.आर. बालू जी, आप बोलिए।

SHRI T. R. BAALU: Sir, he has not answered the question properly. The hon. Member is a new-comer. …(*Interruptions*) The Minister has to answer properly. Kabaddi is traditionally a Tamil Nadu-specific sport. What are you doing for promoting it? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: इनका प्रश्न कबड्डी खेल के बारे में है।

SHRI KIREN RIJIJU: Kabaddi comes under indigenous sports. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए।

SHRI T. R. BAALU : All right, let him answer. …(*Interruptions*)

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, kabaddi is a part of the indigenous sports. That is why I said that we are promoting all indigenous sports including kabaddi. Kabaddi is one of the indigenous sports where our Ministry has given recognition. So, we will promote kabaddi and, in the future, we will take kabaddi to the Olympic Games also. …(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : He has asked a specific question about Tamil Nadu. Are you interested in doing something for Tamil Nadu or not? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यगण खेल के प्रति अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस विषय पर हाफ-एन-ऑवर चर्चा करने के लिए एलाऊ किया है, इसको चर्चा में लिया जाएगा।

श्री श्याम सिंह यादव जी, आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री श्याम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में लिखा है कि खेलो इंडिया स्कीम के घटक, प्रतिभा, पहचान और विकास के अंतर्गत खेल प्रतिभा का पता लगाने के लिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जवाब मत पढ़िए, केवल प्रश्न पूछिए।

श्री श्याम सिंह यादव: महोदय, प्रतिभावान खिलाड़ियों के सिलैक्शन का एक प्रोसेस होता है। मेरी जानकारी के हिसाब से सभी खेल संघों के पास सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है और जिनका सिलेक्शन का प्रोसेस है, वह बहुत लचर है। उसमें बहुत बेईमानी होती है। जिन खिलाड़ियों को बेईमानी के कारण निकाल दिया जाता है, वे भविष्य में दोबारा इस नुकसान से बचने के लिए मंत्री जी के पास शिकायत करने के लिए नहीं जा पाते हैं और खेल संघ को भी शिकायत नहीं कर पाते हैं।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि सभी खेल संघों का चयन प्रोसेस है, तो उसे सभा पटल पर रखने की कृपा करें। वे कुछ समय निकाल कर देखें कि चयन प्रोसेस में क्या लकूना है?

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त करें। माननीय मंत्री जी खेलों के लिए पूरा समय देते हैं।

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष जी, युवाओं को मौका देना और उन्हें सपोर्ट करने में सही चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों का सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। सरकार सिलेक्शन प्रोसेस में हस्तक्षेप नहीं करती है और फेडरेशन वालों को चयन की पूरी अथॉरिटी दी गई है। उन्हें लिखित रूप से कहा गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस, चाहे ओलम्पिक खेलों के लिए प्लेयर्स सिलेक्शन हो, एशियन गेम्स के लिए

प्लेयर्स की सिलेक्शन हो, काई भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो या नेशनल लेवल की गेम्स हों, इन सभी में प्लेयर्स का सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम उसमें दखलंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन यदि शिकायत आती है, तो हम जरूर इंटरवेंशन करते हैं।

(Q. 364)

SHRI T. R. BAALU : The National Council of Applied Economic Research in its report has stated that every Rs.1 lakh investment in residential housing creates 2.69 new jobs in the economy. Out of 2.69 jobs created, 2.65 jobs will be in the informal sector and 0.04 jobs will be in the formal sector.

Another NGO, financed by the European Union, has got a survey done and has reported that there are 4,382 homeless people in 15 cities, including Coimbatore, Chennai and Madurai. The report says that three out of five persons are homeless. It means that 60 per cent of the Indians are homeless.

In this scenario, what is the future plan of action of the Ministry? Is it possible to provide home to all the homeless by 2022, as is envisaged by the Government?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member has raised two important but separate issues. One is, whether the Prime Minister's flagship programme of Pradhan Mantri Awas Yojana can achieve the target of a home for every Indian citizen, wherever he or she might live, by the target year 2022. That is one question, and I will answer that.

The hon. Member has cited one Study in terms of the job creating effects of construction of homes. Sir, the Study that the hon. Member has cited has actually relied on the employment data, where there was a methodological flaw in terms of what constitutes employment. Sometimes, if

you are in a construction job, it no doubt creates employment but whether the employment is for 20 days or for 300 days is different. So, the Study that we rely on is a Study which was conducted in the year 2019. The first Study, which we have conducted, is by NCAER, which has been mentioned in the written reply also, which shows that the jobs created in the field of construction are as follow.

This is a National Institute of Public Finance and Policy, 2019. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बातचीत नहीं करें। मैं पहले इशारों में कह रहा हूं, फिर नाम लेकर बोलूंगा। सदन में प्रश्नकाल के समय कोई बातचीत नहीं करेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: It says that every investment of Rs. 1 lakh in housing sector, creates direct employment of 54 person-days and indirect employment of 108 person-days.

Now, if you look at the overall Pradhan Mantri Awas Yojana, the scheme was introduced in June 2015. At that time, as per the demand assessment -- which was done -- we would have to build one crore houses by the year 2022. Subsequently, when the scheme was implemented, that figure was revised upward to eleven crores and three lakh or so. By the month of December, we had already sanctioned ten crores and three lakh *pakka* houses under four verticals. The target has already been met to that extent.

The operative thrust of the question, however, is on a property-less and whether there is a correlation between owning property and poverty. I must submit to the august House that the data on ownership of property and issues of poverty are not maintained by us. I do not even know that about the State Governments. What I can share with the hon. Member is that under two of the flagship programmes of the Central Government -- I have already shared information regarding the Pradhan Mantri Awas Yojana -- the earlier target of ten crores has now been revised to eleven crores and three lakh houses. We have already sanctioned ten crores and three lakh houses in that. About 62 lakh houses have been grounded and are being implemented. About 32 lakh houses have already been handed over. So, we are well towards achieving our objective. I correct myself. It is 10 million. It is 1.2 crore and not ten crore. We have already sanctioned at the bulk of that. In the last meeting of the Committee for Monitoring and Sanctioning of Projects, held in the month of December, they have approved 6.7 lakh houses in that. We have had no meeting since then, but by the time we have the next meeting, either towards the end of March or April, the entire quota would have been sanctioned. I am also confident that well before 2022 all the houses will be given to the beneficiaries.

Now, clearly, under two of the verticals, beneficiary-led construction and Credit Linked Subsidy Scheme, it is direct because a beneficiary either already has a house which needs renovation or the beneficiary goes to a housing bank

to get a loan as he has already acquired a property. But even under the Affordable Housing in Partnership, I think, this will be completed within the next year plus well before 2022.

SHRI T. R. BAALU: The Government is relying on the 2011 Census. That is why, the figures are not updated. First of all, the Government should update it. How many homeless are there throughout India?

I want to ask one specific question. The Government has targeted to provide homes for 3.98 crore homeless. So far, for the past four years, they have provided 91.86 lakh houses in rural areas and 32 lakh in urban areas. The gap is 2.74 crore. Only two years are left. Within two years, is it possible to see that 2.74 crore houses are constructed and handed over to them? It is all depended on the 2011 Census. They are not updating the figures. How are you going to fill up this gap?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The figures that I have provided to the hon. Member relate to the urban sector. Insofar as the rural sector is concerned, the figures are much larger and the construction of homes is also much larger. My senior colleague, Shri Narendra Singh Tomar, will provide the answer. As far as I am concerned -- the homeless in terms of beneficiaries -- the demand assessment here was done by the UTs and the States themselves. It was not based on the 2011 Census. Even today, this is a scheme operating under cooperative federalism. It is the State Governments which have to do it.

This data is not available with the Central Government. If the State Government tells us that they need more, I would be very happy to give. Take for instance, the Tamil Nadu figure in terms of urban sector which are the latest figures which I have got. Under CLSS, the total is 42,113 and *in situ* slum rehabilitation – 4,880, affordable housing in partnership – 1,50,423, BLCS – 5,75,798. So Tamil Nadu's total is 7,73,000.

Now if the Tamil Nadu Government tells us that their demand assessment needs to be revised, we would react to that. But today we are operating on a revised demand assessment which is not based on 2011 Census but is based on figures provided by the States and the Union Territories to us.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, the Minister has mentioned a few numbers in his answer but as regards one number, he did say that his Ministry does not keep track of poverty numbers. But the fact is that we all know that the total wealth of 63 Indian billionaires exceeds the entire budget of the Government of India. So, the fact is that we are in a situation where 73 per cent of the wealth generated in our country went to the richest one per cent of our population, whereas 67 crore Indians who are bottom half of our population collectively accounted for one per cent of the national GDP.

In these circumstances, it is very clear that the inequality gap between the rich and the poor in our country can only be addressed by specific "inequality busting" policies. My senior colleague, Mr. Baalu, asked about

homelessness. This question is actually totally relevant because the argument is that unless you equip the poor with the tools to break through inequality, the kind of figures that I have given, whether its crores or millions, will remain an issue. Your Ministry used to be called Urban Poverty Alleviation, the name has been changed, but the question still is, to what extent are you going to do poverty alleviation through your housing schemes.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to share some information with the hon. Minister. Apart from the history of this Ministry which started as housing and construction …(*Interruptions*). That is a slip of tongue. He used to be a Minister. He was a colleague of mine in the University. Let me not get into that.

This Ministry started as housing and construction in Shri Mehar Chand Khanna Ji's time. It went on. Poverty alleviation was one of the issues and poverty alleviation continues to remain one of the focal areas. We have the National Urban Livelihood Mission as part of this.

If we are to draw a co-relationship between different policies which we are following and what was done earlier, let me give you a few statistics. In 10 years of the Congress led UPA Government between 2004 and 2014, the entire expenditure on the urban space, which is the value of the urban missions of the Congress led UPA Government, was Rs.1,57,000 crore. In the five years of the Narendra Modi led NDA Government, the figure is six times higher. It is over Rs.10 lakh crore already. So, let us not get into that.

Insofar as inequality busting policies are concerned, I can give you the figures. Under NULM, 43.7 lakh woman in 4.5 lakh Self-Help Groups have been helped in skilling and employment; 3.4 lakh Self-Help Groups have received a revolving fund; and 10.6 lakh candidates got skill training. But I want to go from those individual schemes to the overall -- what is happening and whether it is Swachhta Mission or Pradhan Mantri Awas Yojana. The idea is to reach the benefits of development to the poorest of the poor. Therefore, when you provide housing to the Economically Weaker Sections or the lower income group or the medium income group and you provide a total of 1.12 crore home, I think that is an inequality busting policy.

Over and above, what we need to do is this. Yes, the State is doing it in a number of ways and inequality is being addressed. But the thrust of this question is on property ownership. The measurements of property ownership and poverty are done by the State Governments and not by the Central Government.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

The core of the question is housing project for the property-less. The basic issue which we are facing is that though there are so many Centrally-sponsored and State-sponsored schemes, yet for the housing schemes, most of the people do not have the property to construct a house.

Sir, I would like to ask a specific question to the hon. Minister. In the State of Kerala, we are having a Life Mission project by which construction of multi-storied buildings are being constructed which are being provided to the property-less poor people. I would like to know whether the Government of India will launch a housing scheme for those people who do not have the property.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, data on ownership of property or lack of property is not available with the Central Government. What we are doing under the Pradhan Mantri Awas Yojana is to take the figures provided by the State Governments and try and meet the demands of the State Governments.

Sir, let me share the figures with the hon. Member. In the State of Kerala, under the CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) there are 13,443 beneficiaries; under *in situ* Slum Rehabilitation, the beneficiaries are 2118; in respect of Affordable Housing and Partnership, the number of beneficiaries are 488; in case of Beneficiary-led construction, the number is 1,14,529 and the total number of beneficiaries for the State of Kerala is 1,30,578.

Sir, my understanding is that these figures which have come and which are the implemented figures for the State of Kerala, Kerala is slightly different from the other States because Kerala does not have the kind of demand, I suspect, under Economically Weaker Sections as some of the other States. Therefore, this Private Public Partnership projects which the hon. Member is mentioning …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is a Government programme.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Yes, it is a Government programme and they are free to apply for either a Credit Linked Subsidy Scheme, that is, interest subvention scheme, they can go to a housing bank, get the loan, or if they have traditional homes of their own, they can ask for a grant under beneficiary-led construction.

Over and above this, if there is a new scheme which the Government of Kerala wishes to propose, they can always do that.

(Q. 365)

माननीय अध्यक्ष: मैं आज के बाद रोज 20 प्रश्नों को पूरा करूंगा। इन 20 प्रश्नों में जिसकी लॉटरी खुली है, उसको तो अधिकार होना चाहिए।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P.: Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to part (d) of the Question. This is with regard to recently passed Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2019 in which it has been mentioned that many initiatives have been undertaken to focus on road safety which *inter-alia* includes penalties for traffic violation, electronic monitoring and juvenile driving systems. I am very happy with such provisions.

Sir, but there are certain places in India, especially from the place that I represent, there is no such enforcement agency in place to look after such traffic rule violations. In Lakshadweep there is no traffic police and juvenile driving is increasing day by day. There is only a Vehicle Inspector's office. There is no proper monitoring happening and road accidents are increasing in Lakshadweep. Roads are very narrow. Will the Government come up with some sort of a solution by establishing a law enforcing agency so that traffic violations can be controlled in future and the mortality rate can be brought down?

श्री नितिन जयराम गडकरी: आदरणीय स्पीकर महोदय, पांच महीने पहले जब मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ, उसके बाद काफी अच्छे परिणाम मिले हैं और सदन ने जो सहयोग किया, मैं

उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में वर्ष 2016 में 1 लाख 50 हजार 785 मौतें रोड एक्सीडेंट में हुई थीं, वर्ष 2017 में 1 लाख 47 हजार 913 मौतें हुई थीं और 2018 में 1 लाख 51 हजार 417 मौतें हुई थीं।

इस एक्ट पास होने के बाद जो प्रयास राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से किए गए, उनसे गुजरात में करीब 14 परसेंट डेथ कम हुई हैं, ऐक्सीडेंट्स कम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 13 परसेंट, मणिपुर में 4 परसेंट, जम्मू कश्मीर में 15 परसेंट, आन्ध्र प्रदेश में 7 परसेंट और चण्डीगढ़ में 15 परसेंट डेथ और ऐक्सीडेंट कम हुए हैं। केवल केरल और असम दो ऐसे स्टेट्स हैं, जहां डेथ और ऐक्सीडेंट बढ़े हैं।

केरल में 4.9 प्रतिशत और असम में 7.2 प्रतिशत बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 6 प्रतिशत कम हुए, छत्तीसगढ़ में 5 प्रतिशत कम हुए हैं, हरियाणा में 1 प्रतिशत कम हुए हैं और दिल्ली में 2 प्रतिशत कम हुए हैं। अगर हिसाब किया जाए तो लगभग 10 प्रतिशत एक्सिडेंट्स एवरेज कम हुए हैं। यह एक्ट पास होकर कम से कम 15 हजार लोगों की जानें बचाई गई हैं, यह मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं। अगर ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो वर्ल्ड में हमारा एक्सिडेंट्स के मामले में जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, उसमें कमी आएगी।

महोदय, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने चार अन्य बातों पर भी काम किया है। एजुकेशन, रोड इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एण्ड इमरजेंसी। इनमें भी काफी काम हुआ है और अच्छे परिणाम आए हैं। मैं एक और बात माननीय सदस्य और आप सबको कहना चाहूंगा कि हमने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि जिस जिले का जो सांसद है, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनेगी और उस समिति के सेक्रेट्री कलैक्टर होंगे। मैंने इसे जब स्वयं अपने क्षेत्र में किया तो पाया कि 587 मौतें हुई थीं। हमने एसपी और अन्य लोगों को लेकर ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करने का काम शुरू किया है। एक और अच्छी बात है कि आप सब लोग तुरंत अपने जिले में इस जिम्मेदारी को लें और इस काम की शुरुआत करें। स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल

कॉरपोरेशन, नैशनल हाईवे, डीडीए, जो कोई भी होगा, उनकी रोड का आप इन्स्पेक्शन करें। हम एक योजना शुरू कर रहे हैं कि हर जिले के जो इंजीनियर कॉलेजेस, जैसे आईआईटी, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनको मिनिमम 50 किलोमीटर और कैपेसिटी देखते हुए 1000 किलोमीटर रोड सेफ्टी ऑडिट करने का काम हम उनको देंगे। जो भी यंग लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, वह उसका अध्ययन करेंगे। उसके लिए हम उनको ग्रांट भी देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर एजेंसी कार्रवाई करेगी और हमारे पास इसका डाटा इकट्ठा होगा।

मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि अगर आपको इसमें कोई भी अड़चन आए, तो कृपया मुझे बताइए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मुझे आज तक मौका नहीं मिला। …(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: अधीर रंजन जी, मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने ऑर्डर निकालकर पहले आरटीओ के प्रमुख को समिति का सचिव बनाया था। बाद में ध्यान में आया कि कलैक्टर, एसपी आदि को बुलाने में उनको अड़चन आएगी, तो हमने बाद में कलैक्टर को बनाया। मैंने अपने क्षेत्र में खुद इनीशिएटिव लेकर कलैक्टर को बोलकर कमेटी तैयार की। उसमें एनजीओ को जोड़ा और चूंकि मुझे समय कम मिलता है, इसलिए मैंने विकास पुरुष, पद्मश्री, जो राज्य सभा के सदस्य भी हैं, उनको कार्याध्यक्ष बनाया है। हर पन्द्रह दिन में मीटिंग हो रही है और वह काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आपके क्षेत्र में, आपके जिले के कलैक्टर को भारत सरकार का ऑर्डर गया है। शायद राज्य सरकार का कलैक्टर आपकी बात सुन नहीं रहा होगा, इसलिए उनको आप तुरंत बताइए। मैं अपनी तरफ से भी उनको इस बारे में सूचना भेजूंगा।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मंत्री जी, दिल्ली में मुझे जमींदार लगता है और बंगाल में ... *लगता है।

श्री नितिन जयराम गडकरी: स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं अपनी तरफ से पुन: कलैक्टर को इसका रिमाइन्डर भेजकर इस काम के लिए कहूंगा। आप भी अपनी तरफ से आग्रह करिए।

माननीय अध्यक्ष: आप निश्चित रहें। आपके आदेश का शत-प्रतिशत पालन होगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी: मोटर व्हीकल एक्ट पास होने के बाद सबके सहयोग से जो अलग-अलग प्रकार के प्रयास किए गए हैं, उससे एक्सिडेंट्स काफी कम हो रहे हैं। अभी स्वीडन में रोड सेफ्टी पर जो कॉंफ्रेंस हुई थी, उसमें हाईएस्ट एक्सिडेंट्स और हाईएस्ट डेथ्स इंडिया में पाई गईं। सबने चिंता भी व्यक्त की। इसके लिए कमिटमेंट का एक विजेन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पांच सालों के भीतर हम ट्रक से होने वाले 50 एक्सिडेंट्स और 50 मौतें कम करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम यह टारगेट पूरा करेंगे। जहां तक लक्षद्वीप की बात है, यह यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अंडर में वहां के सभी प्रकार के लॉ एण्ड ऑर्डर आते हैं। जो बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं अपनी तरफ से गृह मंत्री जी को इसकी सूचना दूंगा और वहां इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री भगवंत मान: सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश में रोड एक्सीडेंट्स से जहां सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, उनमें पंजाब स्टेट का नाम शुमार है। बहुत फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी की जब एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो पंजाब सरकार ने 138 ब्लैक स्पॉट्स, जिन्हें किलर स्पॉट्स कहते हैं, ऐसे एस-मोड़, यू-मोड़ को स्पॉट किया था, लेकिन उनकी सिर्फ गिनती करके उन्हें वही छोड़ दिया गया। क्या आप ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स, किलर स्पॉट्स, जहां ज्यादा

* Not recorded.

एक्सीडेंट्स होते हैं, उस मोड़ की या उस सड़क पर एक्सीडेंट्स होने की हिस्ट्री है, उनका संज्ञान लेंगे**?** हमारी वे सड़कें खूनी सड़कें बन चुकी हैं।

सर, मेरे चार दोस्तों की मौत आवारा पशुओं की चपेट में आने से हो चुकी है। क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो वह बताइए।

श्री नितिन जयराम गडकरी: स्पीकर साहब, सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसमें कुछ बातों में निश्चित रूप से विचार करने लायक स्थिति है। अभी हमें एन.एच.ए.आई. की सड़कों पर 786 ब्लॉक स्पॉट्स मिले थे। उसके लिए हमने 12,000 करोड़ रुपये मंजूर किए और उसमें से अब ***350*** स्पॉट्स इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन, जब इसकी जानकारी आई तो अभी इन ब्लैक स्पॉट्स की संख्या 5,000 के ऊपर चली गई। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, म्युनिसिपल रोड्स और एन.एच.ए.आई., ये सब हमारी मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट है और अब हम इन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज और रोड वाइज आईडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, जिसके बारे में बताते हुए मुझे संतोष हो रहा है कि सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई है, उसमें 7,000 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी, 3,500 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक और 3,500 करोड़ रुपये ए.डी.बी. हमें लोन दे रही है। मैं हर बार, विशेष रूप से, इस बात का उल्लेख करूंगा कि तमिलनाडु ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अच्छा काम करके 24 प्रतिशत एक्सीडेंट्स और डेथ्स को कम किया है। मुझे लगता है कि हम इस 14,000 करोड़ रुपये को राज्य सरकार को देंगे और इन ब्लैक स्पॉट्स को इम्मीडिएट, मिड-टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवीजन करके पूरे स्पॉट्स को इम्प्रूव करने को हाइएस्ट प्रायॉरिटी देंगे। इससे रोड्स एक्सीडेंट्स कम होंगे और पंजाब में भी इस पर ध्यान देंगे।

(Q. 366)

श्री उदय प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का विस्तारपूर्वक जवाब दिया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर है और जबलपुर-जयपुर एक्सप्रेसवे है, उसका जो चौराहा है, वह हिन्दुस्तान के व्यस्ततम चौराहों में से एक है। उस पर स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण किया गया है। निजी लोगों और गरीबों ने जो अतिक्रमण किए थे, वे हटा दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार के और स्थानीय निकायों के जो अतिक्रमण हैं, वे आज भी खड़े हुए हैं। उन्हें निर्धारित समयावधि में हटाकर, उस स्थान को, जो करोड़ों रुपये कीमत की जमीन है और जो कई एकड़ में है, उसे तार की फेंसिंग करके या दीवार खड़ी करके सुरक्षित करने का क्या कोई काम मंत्रालय करेगा, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय स्पीकर महोदय, यहां पर अतिक्रमण हटाए गए हैं और वहां केवल छ: बाकी हैं। उनमें से चार स्टेट गवर्नमेंट के अतिक्रमण हैं। उसमें जो हाट-बाजार कंस्ट्रक्टेड है, उसे एम.पी. हाउसिंग बोर्ड ने राजमार्ग फ्लाईओवर के पास कंस्ट्रक्ट किया है और एक पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी का कम्पेनसेशन भी ले लिया है, लेकिन फिर भी वे उसे हटाते नहीं हैं। उन्हें बार-बार नोटिस दिया गया है। पर, आज सम्माननीय सदस्य के द्वारा सवाल पूछने के बाद मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि राज्य सरकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाए। अगर उन्होंने नहीं हटाया तो उसे बुलडोजर लगाकर तोड़ा जाए और उसे निकाला जाए, इसके आदेश दिए गए हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, मेरा छोटा-सा आग्रह है। यह छूट जाएगा। कृपया इसकी अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, पूछ लीजिए।

श्री उदय प्रताप सिंह: अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

महोदय, जिस तरह रेलवे ने खाली जगहों पर काम किया है, उसी तरह से क्या एन.एच.ए.आई. भी वहां पर रोजगार पैदा करने के लिए कोई हाट-बाजार या इस तरह के कॉम्प्लेक्सेज बनाकर या रोजगारमूलक कोई योजना बनाकर काम देने का काम करेगी, जिससे स्थान भी सुरक्षित रहे, क्या मंत्रालय का ऐसा कोई विचार है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष जी, सवाल का स्पष्ट उत्तर है कि ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि यह मेरा मैनडेट नहीं है, परंतु रोड साइड अमेनिटीज़ का मैनडेट है। हमने रोड के बाजू में होस्टल, रेस्टोरेंट, बाजार, बाद में उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, बाद में हैंडलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट जैसी योजनाएं बनाई हैं। खादी ग्रामोद्योग के लिए कुछ जगह रिजर्व की गई है। ऐसे 2000 रोड साइड अमेनिटीज़ बनाने का प्लान बना है। पहले 20 का टेंडर भी निकला हुआ है। उसके द्वारा वहाँ का हैंडलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट का काम होगा। वहाँ का फूड अवेलेबल होगा। वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हम यहाँ तक सीमित हैं। इसी में हम काम करेंगे। बाकी उनका जो विषय है, उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं, उनके पास है। उनका मार्गदर्शन लेकर आगे कोई योजना बनती है तो उसमें हम सहयोग करेंगे।

(Q.367)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: Sir, the Mihir Shah Expert Committee has recommended the creation of a National Water Commission, merging the Central Water Commission and the Central Ground Water Board, which looks at aquifer mapping, groundwater management, and possesses the mandate of data governance and water policy. My question to the hon. Minister is this. Does the Government have any plans to implement this suggestion?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मिहिर शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की संस्तुति की थी। हमने उसके ऊपर विचार किया है। वर्तमान में भी मंत्रालय के स्तर पर विचार चल रहा है। जहाँ तक जिस विषय के मूल को लेकर इन्होंने प्रश्न किया है कि उसके कारण ऐक्विफर मैपिंग का कार्यक्रम हो सके। ऐक्विफर मैपिंग ऑलरेडी सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कर रहा है। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो चिह्नित किया गया है, उसमें से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ऐक्विफर मैपिंग प्रोग्राम हो गया है। मैंने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 256 आइडेन्टिफाइड वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनके जो वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स हैं, उनमें प्राथमिकता के साथ आने वाले वर्ष तक इस कार्यक्रम को पूरा किया जा सकेगा।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Sir, it is widely known that the practice of providing power subsidies to farmers has been a factor in the decline of water resources and water levels in our country. Although, this is a State subject, my question to the hon. Minister is this. Has the Government looked at some kind of overarching consultation to look at some sort of regulation for use of electricity for ground water extraction by the farmers?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से जायज है। हम सब लोगों ने कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस चिंता को अनुभव किया हुआ है। क्योंकि यह राज्य का विषय है और इसे राज्य को ही करना है। मैं पंजाब की सरकार का उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर किसान को बिजली मुफ्त में मिलती है और जमीन के अंदर पानी की हालत निरंतर गिरती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 'बिजली बचाओ पैसा कमाओ' की योजना ली है, ताकि वहाँ मीटर लगाकर असेस करें। जो एस्टिमेटेड है कि कितना पंप साइज लगाया हुआ है, उसके ऊपर उनके साल भर के बिजली का व्यय होना चाहिए, जो सरकार सब्सिडी देती है। अगर किसान उसमें बचत करता है, उससे कम बिजली जलाता है तो जितनी बचत उसने की है, उसके लिए सर्टेन अमाउंट पर उस किसान का पैसा सब्सिडाइज करने के लिए तथा उसे इनशेन्टिवाइज करने के लिए दे रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्यों को निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

SUSHRI S. JOTHIMANI : Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would like to appreciate the hon. Minister for his committed and sincere efforts in setting up the Expert Committee to assess the water situation in every district across India. I have participated in one such meeting in my Parliamentary Constituency, Karur. These are all things which have been discussed elaborately in the meeting. There are three lakes in my Parliamentary Constituency, namely, Dhathampalayam Lake, Velliyanai Lake, and Panjappatti Lake. If all of these are rejuvenated, thousands of hectares of irrigation and drinking water facilities may get better in the district of Karur. We are making some efforts in the areas of water conservation and ground water

management. I would like to request the hon. Minister to add sufficient funds in support of our efforts.

The Minister, in his reply, also said that no funds have been allotted under the Cauvery Integrated Water Scheme. So, I would also like to request the hon. Minister to allot funds under Cauvery Integrated Water Scheme for Aravakurichi Assembly, Vedasandur Assembly, Karur Assembly, Krishnarayapuram Assembly, Viralimalai Assembly, and Manapparai Assembly. All of these are very long-pending demands of the people of my Parliamentary Constituency, which are also very well discussed in the meeting. Unless and until the funds are allotted, our efforts would be meaningless. So, I would request you to consider this very important issue. Thank you.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है और माननीय सदस्य ने हमारे प्रयत्नों के लिए धन्यवाद दिया है, उसके लिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने तीन रिजर्वायर्स की बात की है, प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का दायित्व जल संसाधन के रिजर्वेशन के लिए काम करना है। इन्होंने कावेरी नदी के माध्यम से वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाने की चर्चा की है, इसका दायित्व भी प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का है। हम 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक ग्रामीण आवास को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2024 तक प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार इस पर जो प्रपोजल बनाकर भेजेगी, उस पर 50 प्रतिशत राज्यों की हिस्सेदारी है और नार्थ-ईस्टर्न, हिमालयन स्टेट्स के लिए 90:10 का रेश्यो है, उसके ऊपर हम काम करने के लिए कमिटिड हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब हमने विस्तार से देखा है। भूजल स्तर में लगातार कमी हो रही है। आप अगर पिछले कई वर्षों के भूजल स्तर का कम्पेरिटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रति वर्ष भूजल स्तर नीचे जा रहा है। यह आने वाले समय में खतरे की घंटी है।

उत्तर बिहार में कभी जलस्तर नहीं घटता था, लेकिन इस साल देखा गया कि जलस्तर घटा है। इसका मुख्य कारण है कि लोग परंपरागत तालाब, कुएं आदि को एन्क्रोच करके भर चुके हैं और इस वजह से भूजल स्तर नीचे जा रहा है। बिहार सरकार ने 'जल, जीवन हरियाली मिशन' शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जितनी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, उनको एन्क्रोचमेंट फ्री करके पुनर्जीवित कराया जाए।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है, हम मानते हैं कि यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करने का अधिकार है।

हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ट्रेडीशनल वाटर बॉडीज़ को पुनर्जीवित करने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्यों को एडवाइजरी जारी करने का विचार रखती है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने और अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक बार इस विषय पर बात करते हुए चिंता व्यक्त की है कि देश के भूगर्भ में जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है।

देश के कुल जल की आवश्यकता की 65 परसेंट आपूर्ति भूगर्भ के जल से होती है। पिछले 40 सालों में इरिगेशन नेटवर्क की कवरेज जितनी बढ़ी है, उसका 85 प्रतिशत हिस्सा भूगर्भ जल पर निर्भर है। निश्चित रूप से भूगर्भ जल का स्तर लगभग 20 प्रतिशत हिस्से में गिर रहा है और

लगातार इसमें कमी आ रही है। कुछ हिस्सों में जहां सस्टेनेबल हैं, वहां भी जीरो से दो मीटर तक डाउनफॉल रिकार्ड किया गया है। यह चिंता का विषय है और समय की मांग है कि अब हमें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

मैं बिहार सरकार का अभिनंदन करना चाहता हं। ठीक इसी तरह गुजरात सरकार ने 'सुजलाम सुफलाम', महाराष्ट्र सरकार ने 'जलयुक्त शिविर', राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने 'मुख्य मंत्री जल स्वाबलंबन', आंध्र प्रदेश सरकार ने 'नीरू चेट्टु', तेलंगाना ने 'मिशन काकातिया' जैसी योजनाएं बनाई हैं। इस तरह से अनेक प्रदेशों ने अनेक स्तर पर प्रयास किए हैं। भारत सरकार मनरेगा और वाटर शैड के माध्यम से कुछ सप्लीमेंटरी प्रयास राज्य सरकारों के सहयोग के लिए करती है।

जहां तक एडवाइजरी इश्यू करने का सवाल है, हमने मॉडल वाटर लॉज़ बनाकर राज्यों को भेजा था, 15 राज्यों ने इसे स्वीकार किया है, 15 राज्यों ने इसे एडॉप्ट भी किया है। मेरे विद्वान मित्र अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मिनिस्टर ने भी राज्यों को अर्बन एरियाज़ में भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज को मेंडेटरी करने के प्रोविजन की संस्तुति की है। मुझे लगता है कि इसमें सबको प्रयास करने और काम करने की आवश्यकता है।

हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सात प्रदेशों में, जो वाटर स्ट्रैस प्रदेश हैं, 78 डिस्ट्रिक्ट्स में एक पायलट प्रोजेक्ट 'अटल भूजल मिशन' के नाम से प्रारंभ किया है। आज तक हमने सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात कही थी, लेकिन पहली बार इस देश में साथ ही साथ डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करने के लिए कैपिसिटी बिल्डिंग करने और जनजागरण करने का काम किया है।

12.00 hrs

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Sir, in the water stressed Districts, particularly, Virudhunagar, Ramanathapuram and Thoothukudi, water is the biggest problem; and these are all Aspirational Districts also.

Can the Minister assure us that there will be a separate plan for the Aspirational Districts for water management? If any such plan is there, he can inform the House. I would be thankful to him.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, इस तरह के सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए विशेष रूप से प्लान होगा। इसके लिए मैं यहां किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दे सकता हूं। लेकिन, जलशक्ति अभियान में हमने ऐसे 33 जिलों को इनक्लूड किया था।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के लोग दुनिया के उत्तर मेरु से दक्षिण मेरु तक हर जगह रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डायस्पोरा हिन्दुस्तान के लोगों का होता है। आज कोरोना वायरस के चलते अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वह हिन्दुस्तान के लोगों को हो रही है। अमेरिका से लोग आते हैं। अमेरिकन एयरपोर्ट ने उनको पास कर दिया, लेकिन, जब वे हिन्दुस्तान के हवाई जहाज पर चढ़ने जाते हैं तो वे कहते हैं कि इसको निरस्त कर दिया गया है। वहां कहा जाएंगे, कहां रहेंगे, वे कैसे आएंगे, यह हम सबको देखना पड़ेगा। इस तरह से लाखों की तादाद में लोग बाहर फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ईरान से इटली और इटली से अमेरिका, हिन्दुस्तान के लोग पूरी दुनिया में इस तरह से अटके हुए हैं। सरकार इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाए, यही मेरी गुजारिश है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, coronavirus issue has shaken the whole of the world, and we are not out of it. Today, we have heard that the hon. Prime Minister is going to address the nation at 8 p.m.

Let the hon. Prime Minister also address the House after his speech at the national level. This is my request.

माननीय अध्यक्ष: माननीय विदेश मंत्री जी ने पूर्व में सारे विषय को सदन के अंदर रख दिया है और सरकार ने इस बारे में आगे बढ़कर कदम उठाए हैं।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसे हुए 58 विद्यार्थियों को लेकर है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विदेश मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। हम सभी सांसद, जो घटना हुई है, उसके बारे में उनसे सम्पर्क करें। फिलीपींस में पढ़ने वाले सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। वे मलेशिया आए और मलेशिया से उनको सिंगापुर में रखा गया । आज तीसरा दिन है। पिछले दो दिनों में सभी छात्रों को जिस प्रकार की परेशानी सहन करनी पड़ी, सौभाग्य से माननीय मंत्री श्री जयशंकर जी से हम सभी सांसदों ने सम्पर्क किया था और आज प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन कर चुके हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि सभी छात्रों को, जो सिंगापुर एयरपोर्ट पर हैं, जिनमें 25 महिला छात्र हैं, जो पूरे देश के हैं, कोई मुम्बई से, हैदराबाद से, चेन्नई से और कोई गुजरात से है। मेरी विनती है कि जो छात्र सिंगापुर एयरपोर्ट पर हैं, उनको फिर से मलेशिया न भेजा जाए, उन्हें तुरंत भारत में लाने की व्यवस्था करें और उनको मदद करने की व्यवस्था करें।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, the issue of coronavirus is serious. The Government of India is taking stern steps. The world is also appreciating those steps taken. But why is this partiality towards the Parliament of India? Are we not citizens of India? …(*Interruptions*)

12.04 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alon gwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2363/17/20]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2018- 2019, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2018-2019.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2364/17/20]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Power Research Institute, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Power Research Institute, Bengaluru, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2365/17/20]

(3) A copy of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading license and other related

matters) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. L-1/253/2019/CERC in Gazette of India dated 31st January, 2020 under Section 179 of the Electricity Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 2366/17/20]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2367/17/20]

(3) A copy of the Airports Authority of India (Recruitment and Promotion) Regulations, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. A- 60011/67/2011-PP (Pt.I) in Gazette of India dated 12th February, 2020 under Section 43 of the Airports Authority of India Act, 1994, together with an explanatory note.

[Placed in Library, See No. LT 2368/17/20]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 14A of the Aircraft Act, 1934:-

(i) The Aircraft (Third Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.579(E) in Gazette of India dated 20th August, 2019, together with an explanatory note.

(ii) The Aircraft (First Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.22(E) in Gazette of India dated 10th January, 2020, together with an explanatory note.

[Placed in Library, See No. LT 2369/17/20]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2370/17/20]

(3) A copy of the Merchant Shipping (Standard of Training, Certification and watch keeping for Seafarers) Amendment Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.97(E) in Gazette of India dated 10th February, 2020 under sub- section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 2371/17/20]

(4) A copy of the Calcutta High Court Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. COR.2022-16th September, 2019 published in Kolkata Gazette dated 22nd November, 2019 under sub-section (4) of Section 16 of the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 2372/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

(1) S.O.582(E) published in Gazette of India dated 6th February,

2020, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 66 (Old NH No. 17)(Goa-Karnataka Border to Kundapur Section) in the State of Karnataka on DBFOT (BOT) Toll basis.

(2) S.O.583(E) published in Gazette of India dated 6th February, 2020, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 75 (New NH No. 44)(Gwalior-Jhansi Section) in the State of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh under NHDP Phase II on EPC mode.

(3) S.O.743(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2020, regarding rates of fees to be recovered from the users of Nalbari-Bijni- Guwahati-Nagaon-Lanka-Hatikhali Section in the State of Assam on EPC mode.

(4) S.O.850(E) published in Gazette of India dated 25th February, 2020, making certain amendments in the Notification No. S.O.1964(E) dated 21st June, 2017.

(5) S.O.4039(E) published in Gazette of India dated 8th November, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.689(E) dated 4th April, 2011.

(6) S.O.4040(E) published in Gazette of India dated 8th November, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(7) S.O.4142(E) published in Gazette of India dated 19th November, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.689(E) dated 4th April, 2011.

(8) S.O.4143(E) published in Gazette of India dated 19th November, 2019, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway No. 17 to National Highways Authority of India.

(9) S.O.4144(E) published in Gazette of India dated 19th November, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(10) S.O.4528(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(11) S.O.4529(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2019, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway Nos. 95 and 01 to National Highways Authority of India.

(12) S.O.4530(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(13) S.O.4531(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(14) S.O.4532(E) published in Gazette of India dated 18th December, 2019, entrusting the stretches, mentioned therein, of National

Highway No. 111 (New NH 130) and New NH 149B to National Highways Authority of India.

(15) S.O.175(E) published in Gazette of India dated 13th January, 2020, making certain amendments in the Notification No. S.O.689(E) dated 4th April, 2011.

(16) S.O.350(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2020, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway Nos. 347BG, 552G and 753L to National Highways Authority of India.

(17) S.O.695(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2020, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(18) S.O.696(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2020, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

(19) S.O.697(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2020, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway No. 2E (Belghoria Expressway) in the State of West Bengal to National Highways Authority of India.

[Placed in Library, See No. LT 2373/17/20]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2374/17/20]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2375/17/20]

12.08 hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

माननीय अध्यक्ष: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 18 मार्च, 2020 को सभा में प्रस्तुत अपने दूसरे प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति देने की अनुशंसा की है –

1. श्री चन्द्र शेखर साहू	18.11.2019 to 13.12.2019
2. श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	26.11.2019 to 13.12.2019; 01.02.2020 to 11.02.2020;' & 02.03.2020 to 31.03.2020
3. डॉ. फारूख अब्दुल्ला	05.08.2019 to 06.08.2019; 18.11.2019 to 13.12.2019; 31.01.2020 to 11.02.2020; & 02.03.2020 to 20.03.2020
4. श्रीमती अपरुपा पोद्दार	16.03.2020 to 03.04.2020
5. सुश्री मिमी चक्रवर्ती	02.03.2020 to 03.04.2020

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

12.09 hrs

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

316th Report

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, मैं 'महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे' विषय पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 316वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री असीत कुमार माल।

श्री असीत कुमार माल (बोलपुर): मेरे पास पेपर ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: आपका नाम शून्य काल में लगाया था। क्या आप भूल गए?

SHRI ASIT KUMAR MAL : Hon. Speaker, Sir, I would like to raise an important and serious issue about Coronavirus which has broken out all over the country.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पहले आसन से इजाजत मांगनी चाहिए थी कि जिस विषय पर आपने अविलंब लोक महत्व के मामले का सवाल दिया था, उसको आप चेंज करना चाहते हैं। आपने पश्चिम बंगाल में नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र को बोलपुर से कोलकाता स्थानांतरित किए जाने के संबंध में विषय दिया था।

SHRI ASIT KUMAR MAL: Sir, with your permission, I would like to change my subject. सर, नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आज के बाद जब परमिशन लेंगे तक विषय को बदलने दिया जाएगा। अब आप बोलिए।

SHRI ASIT KUMAR MAL : Thank you, Sir. Coronavirus has broken out all over the country. More than 9,000 people have been affected. Three persons have already died. The people all over the country are suffering from extreme panic. More and more isolation and quarantine facilities are needed to facilitate the sufferers.

I would like to demand a statement from the hon. Prime Minister in this matter. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : इस पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिलकर जॉइंट एफर्ट करना चाहिए।

श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री असीत कुमार माल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी वही सब्जेक्ट है, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सिंगापुर में फंसे हुए भारत के 58 बच्चे, जो फिलीपाइन्स लास पिनास शहर के जोनाल्टा फाउण्डेशन स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिकल की शिक्षा ले रहे विद्यार्थी हैं। भारत आने के लिए, वे 17 मार्च, 2020 की दोपहर में एक विमान से फिलीपाइन्स से मलेशिया आने के लिए निकले थे, लेकिन वहां एयरपोर्ट पर आने के बाद उनको पता चला कि वहां से मुंबई जाने के लिए उनको बैन किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे तीन दिनों से सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मैंने आदरणीय मंत्री महोदय से विनती की थी कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर, इन बच्चों को सिंगापुर से मुंबई लाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी, श्री राहुल रमेश शेवले, श्री गोपाल शेट्टी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आज आपसे एक मिनट एक्स्ट्रा समय मांगती हूं।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान देश के एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लाखों बेरोजगार नौजवानों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगी कि केन्द्र और राज्य सरकार के अधीन लाखों सरकारी पद आरक्षण के अनुपात में विगत कई वर्षों से खाली पड़े हैं। मेरी सरकार से मांग है कि विशेष अभियान चलाकर इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। पिछले दिनों हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों में विभागानुसार पद निकाले गए हैं, जिनमें आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। अगर इन विभागों के पदों को एक साथ समूह में निकाला जाए तो आरक्षण लागू हो सकेगा और एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

अध्यक्ष जी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के जो योग्य छात्र हैं, जिनकी मेरिट सामान्य वर्ग में आती है, उन्हें आरक्षण की सीमाओं में बांधकर न रखा जाए। मेरी सरकार से मांग है कि उन योग्य छात्रों का सामान्य वर्ग के अवसर प्रदान किए जाएं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बाध्यता है, उसे समाप्त किया जाए। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है और सामान्य वर्ग के लोगों को 50.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार से मांग है कि 2020 में जातिगत जनगणना कराकर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लागू किया जाए।

साथ ही, मैं आपसे मांग करती हूं कि जिन विभागों का निजीकरण किया गया है, वहां भी आरक्षण को लागू किया जाए। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है, जिसमें इन वर्गों के लोगों की एक भी नियुक्ति नहीं की गई है, जो बेहद दुखद है। न्यायपालिका, राज्य सभा, विधान परिषद में इन वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है और इन वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम संख्या में है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं मांग करती हूं कि वहां भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए।

अध्यक्ष जी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति मानक के अनुसार नहीं दी जा रही है, उसे भी तत्काल मानक के अनुसार प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी, श्री मलूक नागर, श्री रितेश पाण्डेय और श्री गिरीश चन्द्र को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जम्मू की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू शहर जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है और यह केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राजधानी भी है, लेकिन यहां पीने के पानी की बहुत किल्लत है। आने वाले दिनों में गर्मी आ रही है और गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा किल्लत हो जाएगी। जल शक्ति मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की तरफ से जो प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है, उस पर धनराशि आवंटित करें, ताकि वहां पर, जम्मू शहर में जो पानी की किल्लत आ रही है उसे दूर किया जा सके और लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। धन्यवाद।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, with your permission, I want to change my subject in today's 'Zero Hour'.

Sir, I am supporting for whatever precautionary measures that were taken by the Government of India through the Ministry of External Affairs and the Health Department for preventing coronavirus. But I have to express the concerns of the people from my Constituency. They are stranded in different airports in various countries. Already our Members have expressed their issues yesterday and today also. But only one flight has been operated from Kuala Lumpur airport to our country. So many other people who are left over there are still waiting for further information. From my Constituency also, so many people are waiting there. People are facing similar conditions and similar situation in Manila airport and also in Philippines. Many people of India from various countries like Italy, Malta, Moldova, Armenia and Singapore and also from European Union are waiting there to come back to India.

I would like to know from the Ministry of External Affairs what plans they have got to rescue and bring them back and rescue them to India. I urge upon the Ministry of External Affairs and also the Government to send some chartered flights there for their return journey. Also, the Government should give direction to the Embassy officials to provide them with the minimum necessities like accommodation, food, medical care, etc. Thank you, Sir.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam Speaker, Sir. There is a very good four-lane connectivity in place from Chennai to Salem.

One is *via* Vellore and another is *via* Tindivanam. The local community and the agriculturists are all against the new eight-lanes being laid from Salem to Chennai because they want expansion of the already existing four-lanes into eight-lanes, instead of a new one. Further, the newly constructed buildings, a lot of agricultural lands and the local sentiments of the agriculturists are to be taken into consideration. People from the local community have already raised this issue. I have met our leader, Thiru Stalin and also our youth wing leader, Thiru Udhayanidhi Stalin. They have urged upon us to insist on the Government to expand the existing four-lanes into eight-lanes, instead of going in for a new eight-lane connectivity, by giving consideration to the sentiments of the local community and the agriculturists. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मेरठ के किसान हैं – रघुराज सिंह। उनके पुत्र विवेक सांगवान ने बी.टेक. की शिक्षा हेतु पीएनबी की जानी शाखा से 2009 में शिक्षा के लिए तीन लाख तेरह हजार रुपये का लोन लिया था। बी.टेक. की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद विवेक सांगवान को कैंसर हो गया, पिता ने निजी स्तर पर जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम करके उसका इलाज कराया, परन्तु विवेक सांगवान को बचाया नहीं जा सका और 1 नवम्बर, 2013 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् छात्र के पिता रघुराज सिंह को बैंक के द्वारा निरन्तर कर्ज का सहऋणी मानते हुए, कर्ज की वसूली हेतु नोटिस दिए जा रहे हैं तथा ऋण भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी जा रही है। एक गरीब किसान, अगर वह गरीब न होता तो उसका

बेटा कर्ज क्यों लेता, जो पहले ही अपने पुत्र को गवां चुका है तथा आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो चुका है, बैंक के ऋण का भुगतान करना उसके लिए संभव नहीं है।

महोदय, शिक्षा ऋण हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति के गारन्टर होने अथवा किसी अन्य गारन्टी की अनिवार्यता नहीं होती है। साथ ही, बैंक द्वारा शिक्षा ऋण लेने वाले का बीमा भी करवाया जाता है। ऐसे में मृतक छात्र के पिता रघुराज सिंह पर ऋण भुगतान के लिए बैंक द्वारा दबाव बनाना बहुत ही अनुचित है। मेरा आपके माध्यम माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले का त्वरित संज्ञान लें। यह एक इमरजेंसी केस है, रोज रघुराज सिंह बहुत परेशान रहते हैं, उनको राहत प्रदान करने की कृपा करें।

यह बजट सत्र है, इसलिए मैं विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे छात्र-छात्राओं, जिनकी मृत्यु शिक्षा ऋण लेने के पश्चात्, शिक्षा के दौरान ही हो जाती है, उनके शिक्षा ऋण को माफ करने का स्पष्ट नीतिगत निर्णय लेने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, श्री गणेश सिंह, डॉ. निशिकांत दुबे और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद, सर। जिस तरह से युद्धस्तर पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार काम कर रही है, वह बधाई की पात्र है।

सर, मेरा क्षेत्र दार्जिलिंग भारत में एकमात्र ऐसा जिला है, जिसके चार इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं - एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। सिलीगुड़ी से गुजरकर ही पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से जुड़ता है। देश भर और दुनिया भर के सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स मेरे क्षेत्र में आते हैं। वहां राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इसके लिए मैंने

पत्र व्यवहार भी किया है। मेरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता की पूर्ति करें।

सर, ऐसी कठिन परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट और दार्जिलिंग के लोग, जिनकी आंखें छोटी-छोटी हैं, नाक छोटी है, उन पर पुणे में, दिल्ली में, कोलकाता में और बाकी देश भर में नस्लभेदी टिप्पणियां की जा रही हैं। मुझे लगता है कि इसे तुरंत रोकना चाहिए और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

सर, मैं अन्त में एक बात कहना चाहूंगा। मेरा पूरा क्षेत्र टूरिज्म पर टिका हुआ है। वहां बहुत सारे लोग टूरिज्म के माध्यम से ही अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे अजमेर लोक सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जो हवाई अड्डा है, वहां अभी चार उड़ानें दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और बैंगलुरु हैं। इसमें अभी पूरे के पूरे 78 सीटर प्लेन चल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन है कि वे मुम्बई, बैंगलुरु और कोलकाता से ज्यादा उड़ानें शुरू करें। हमारे यहां सृष्टि के रचियता ब्रह्मा जी का मंदिर है। हमारे यहां ख्वाजा साहब की दरगाह और विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ है। यहां वर्तमान रनवे की लम्बाई 2000 मीटर है। इस रनवे की लम्बाई एक हजार मीटर बढ़ाकर कुल तीन हजार मीटर की जाए। वर्तमान रनवे की मजबूती इतनी कम है कि उसके ऊपर एयरक्राफ्ट्स लैंड नहीं कर सकते हैं। इस रनवे की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई जाए। रनवे के एक्सटेंशन का कार्य करने से पहले भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा एक सर्वे कराया गया था। वहां टूंकरा की पहाड़ियों को 23 मीटर और

18 मीटर तक नीचे किया जाए। प्रसार भारती का 200 मीटर का गगवाना में टॉवर है, उसे 71 मीटर नीचे किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ अपनी डिमांड रखें। किसकी ऊंचाई कम करनी है, उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी देख लेगा। आप यह बताएं कि क्या चाहिए।

श्री भागीरथ चौधरी: महोदय, बैंगलुरु, कोलकाता और मुम्बई हवाई यात्रा शुरू की जाए। वहां आवागमन के लिए 75 टर्मिनल्स और 75 टर्मिनल्स प्रस्थान के लिए संचालित हैं। इनकी संख्या 300-300 टर्मिनल्स करने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा वहां दो एयरक्राफ्ट की पार्किंग की व्यवस्था है। वहां सात एयरक्राफ्ट की पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती की एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसान फलों, सब्जियों एवं अन्य कमाऊ फसलों की खेती बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उत्पाद को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अत: उपरोक्त समस्या को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, जिससे किसान भाई अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Thank you, Speaker, Sir. Neelachal Ispat Nigam (NINL), Odisha is a joint venture company of MMTC Ltd. and the Government of Odisha through IPICOL and OMC Ltd. This is 1.1 million-tonne integrated steel plant with 2500 acres of undisputed land which is sufficient for expansion of up to 10 MTPA, with a captive mine of 110 million tonnes of estimated reserve and mining lease for 50 years. Around 10,000 people are dependent on NINL for livelihood.

Sir, MMTC has decided to divest its share in NINL. This resulted in the blow down of blast furnace since June 19. The employees have been demanding the merger of NINL with either SAIL or RINL or NMDC or any PSU. Unfortunately, the Central Government has cleared the way for privatization by approving the proposal of strategic disinvestment of 100 per cent equity shareholding in NINL without any investigation.

Sir, through you, I would urge upon the Government to withdraw the decision taken in respect of privatization, immediate infusion of working capital for commencing production and resumption of payment of wages of employees and workmen. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सप्तगिरी उलाका द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली, उमरखेड, किनवट, हथगांव, बसमत में कल भारी मात्रा में बर्फवारी हुई। ओलावृष्टि के कारण काफी फसलों का नुकसान हुआ है। गेहूं, चना आदि फसलों को बहुत क्षति पहुंची है, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को भारी

नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की राशि किसानों को दी जाए और जल्द से जल्द जिला प्रशासन द्वारा पंचनामा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हेमन्त पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Hon. Speaker, Sir, with your permission, I would like to speak in Malayalam. This is a very serious matter. You may kindly give proper direction to the concerned Ministry or the Government. I am going to raise a very important issue before you.

*Sir, the list of Pradhan Mantri Awas Yojana has been released. The Government has declared that they will construct 61,50000 houses. But unfortunately, the Government did not even have the consideration to allow even 10 houses for Kerala. I am expressing my deep felt anguish on knowing about this discriminatory attitude towards Kerala. Maybe the Central Government will have differences of opinion with the State Government on several issues. Those could be political or apolitical differences. Whether political or apolitical problems should be resolved. But this attitude of making the deprived people of a state suffer, is a gross injustice, and a violation of all political ethics. I want to emphasise this point, before this august House.

---

* .... *English translation of this part of the speech originally delivered in Malayam.

Sir Kerala is a State that has faced the havoc of three floods and the Tsunami. About one lakh houses were destroyed in those three floods. Another one lakh houses have been partially destroyed. About 5000 people have lost their lives. This Government has not done justice to Kerala. We have differences of opinion with the Left Front Government in Kerala. But as a society we are united, in building a new Kerala. At this juncture we were hoping a lot from this major project named Pradhan Mantri Awas Yojana.*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजती है, तभी केन्द्र सरकार करती है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI K. SUDHAKARAN: Sir, whatever may be the issue between the State Government and the Central Government, that should be sorted out. It is the duty of the Governments to sort it out and not the people of Kerala. You do not punish the people of Kerala. That is my humble request.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री के. सुधाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि कुछ महीनों पहले मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी, सिंगरौली में एक इंटरसिटी ट्रेन की सौगात प्राप्त हुई थी, जो सिंगरौली से जबलपुर जाएगी। संचालन की तिथि भी निर्धारित हो गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया, और यह कहा गया कि हम इसका संचालन कुछ समय बाद करवाएंगे, लेकिन आज तक इसका संचालन नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंगरौली जिला औद्योगिक जिला है। जबलपुर में उच्च न्यायालय स्थित है और वहां बड़े-बड़े स्वास्थ्य संस्थान भी हैं। हमारे जिले के निवासी कार्यालयीन और व्यापारिक कारणों से वहां से आते-जाते रहते हैं। अगर यह ट्रेन संचालित हो जाती है, तो वह सिंगरौली जिले से चलेगी और सीधी जिले के मडवास को छूते हुए, शहडोल जिले के हमारे संसदीय क्षेत्र के बेवहारी विधान सभा को छूते हुए आगे निकलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि इस ट्रेन का संचालन शीघ्र अति शीघ्र करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON. SPEAKER: Shri Rajmohan Unnithanji.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Hon. Speaker, Sir, I thank you very much.

HON. SPEAKER: No. माननीय सदस्य, क्या आप विषय परिवर्तन कर रहे है?

श्री राजमोहन उन्नीथन: नहीं, नहीं, सब्जेक्ट परिवर्तन नहीं कर रहा हूं।

HON. SPEAKER: Then, you are not allowed.

… (*Interruptions*)

श्री राजमोहन उन्नीथन: सर, सब्जेक्ट परिवर्तन करना है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN: The Speaker is asking me to change the subject. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। हम आपको नेक्स्ट एलाउ कर देंगे।

श्री संतोख सिंह चौधरी जी।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): अध्यक्ष महोदय, जब महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और भारतीयों को अंग्रेजी सामान का उपयोग बंद करने और केवल भारतीय उत्पादों का प्रयोग करने के लिए कहा, तो खादी इस आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनी। एक तरह से खादी मेक इन इंडिया प्रोग्राम बना।

लेकिन दुख की बात है कि आज वही खादी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आदमपुर में पंजाब खादी मंडल है। वर्ष 1925 में महात्मा गांधी आदमपुर आए और वहाँ के कारीगरों से अति प्रभावित हुए और वहीं पर उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसका पहला ऑफिस आदमपुर में स्थापित किया गया। उस खादी मंडल में जो हजारों कारीगर थे, उनको रोज़गार दिया।

इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन के कारण आज खादी अन-पॉपुलर हो गई है, यह पॉपुलर नहीं रही। आदमपुर का जो खादी मंडल है, वह एक सिक यूनिट बनता जा रहा है। उस खादी मंडल के पास छ: एकड़ जमीन है। जहाँ हजारों कारीगर काम करते थे, वहाँ अब सिर्फ 20-25 कारीगर ही बचे हैं।

आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरी माँग है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को निर्देश दिया जाए और आदमपुर खादी मंडल को रिवाइव किया जाए। इसके लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए और इसे एक स्किल डेवलपमेंट सेन्टर के रूप में विकसित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, रेलवे के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम किए गए हैं।

मुम्बई से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली तक आती है। यह ट्रेन वहाँ से चलकर महाराष्ट्र के बोरीवली में रुकती है और बोरीवली से चलकर सीधे सूरत में रुकती है। बोरीवली से सूरत के बीच लगभग 275 किलोमीटर का अंतर है। इसके बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, इसके कारण मेरा एरिया दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, साउथ गुजरात का बलसाड़, पूर्व महाराष्ट्र के लोग इतनी अच्छी ट्रेन की सुविधा से वंचित हो जाते हैं। जो मेरा एरिया है, जैसा कि मैंने अभी कहा, वह सबसे बड़ा इंस्ट्रियल एस्टेट है। दादरा और नागर हवेली एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऐसी जगह पर स्टॉपेज न मिलने के कारण हमारे लोगों को और वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सभी को इससे भारी नुकसान हो रहा है।

इसलिए आपके माध्यम से भारत सरकार से, खासकर रेल मंत्रालय से और माननीय रेलवे मंत्री जी से विनती है, इसके बीच में वापी स्टेशन है, अगर अंतर के हिसाब से भी देखा जाए, तो यह बिल्कुल वायेबल है और यात्रियों के हिसाब से भी देखा जाए, तो यह वायेबल है, इसलिए वापी स्टेशन पर इस राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, Sir, thank you very much. Resilient India has done very well insofar as dealing with

COVID-19 is concerned. But I feel that there are a couple of things which we need to focus on. One thing is, while we have set up 45 VDRL labs and we are further increasing it to 60 more labs, there are private hospitals in Delhi which are not admitting COVID patients or patients suffering from this particular pandemic.

I think the Delhi Government needs to activate the private health sector. There are vulnerable sections in the society. जो डेली वेजेज पर काम करने वाले लोग हैं, अभी जो समय चल रहा है, उसमें उनके पास खाने की तकलीफ होना स्वाभाविक है। एफसीआई के जो गोदाम या अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं, उनमें अधिक मात्रा में अनाज पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाए, खास तौर पर राज्य सरकारें, उन अनाजों का डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस के माध्यम से करें ताकि अधिक-से-अधिक अनाज बाँटे जाएँ।

अध्यक्ष जी, उसका कारण है, वह यह है कि अभी अप्रैल में गोदामों में और अनाज आ जाएंगे, तो कपैसिटी से अधिक जो अनाज पड़े हुए हैं, यही समय है कि उनको निकाल दिया जाए और जो वलनेरेबल सेक्शंस हैं, उनको यह सुविधा दी जाए।

मुझे लगता है कि जब कोई अच्छा काम करे, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल उनकी पीठ थपथपाने की जरूरत होती है। इसलिए जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने एम्बुलेंस चालक हैं, भारत सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको हमें धन्यवाद कहना भी बनता है।

उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि 130 करोड़ के अपने देश में मात्र 2 मृत्यु हुई हैं, जो तीसरी मृत्यु हुई है, वह कोविड-19 की वजह से नहीं हुई है, वह जंप करने की वजह से हुई है। इन सबको हमें एप्रिशिएट करना है।

When times become tough, the best out of people comes out. I must appreciate the Media also. The best in Media has come out. They have also done a good job in creating awareness relating to this subject.

It is time to revisit the Indian format, the Indian way of living, Ayurveda, our food habits, vegetarianism and keeping minimalistic contact with strangers.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Sir, Coimbatore city is known for the textile industry. In this city, Sardar Vallabhai Patel International School of Textiles and Management is functioning which is an autonomous institute under the Ministry of Textiles. It was approved by AICTEA.

It has signed a Memorandum of Understanding with the Central University of Tamil Nadu at Thiruvarur. It is offering B.Sc. – Textile, two years' full time Post Graduate Diploma in Management and MBA courses for various streams connected with the textile industry from the year 2016-17.

An assurance was given by administration of Sardar Vallabhai Patel Textile College that this Institute will be merged with the Central University, Thiruvarur which is promoting textiles related courses in Tamil Nadu. After passing an examination conducted by the Central University Students got admission in this Institute with the expectation that the fee structure will be

reduced and the Degree Certificate would be given on merit for future employment opportunities.

I came to know that the issue of merging with the Central University, Thiruvarur was not materialised by the Textile Ministry upto 2019 as assured by the management during the admission and the students' representatives were not given an opportunity to meet the Secretary of the Textile Ministry.

I hereby request the Textile Minister to make a personal intervention to settle the matter. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री बी. मणिक्कम टैगोर को श्री पी. आर. नटराजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.36 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Resuming of service of Budh-Purnima Express (14224/14223) and demand for 100 per cent refund of cancellation fee

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वैसे तो देश में अभी कोरोना के चलते बहुत सारी ट्रेन्स रद्द हुई हैं, लेकिन एक गाड़ी है, जो चार-पांच महीनों से कुहासा के कारण रद्द है। वह गाड़ी सारनाथ से राजगीर तक चलती है, जिसका नंबर 14223/24 है। महोदय, कुहासा कब का खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक इस गाड़ी का परिचालन शुरू नहीं किया गया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोरोना के कारण देशवासियों से यह अपील की कि बहुत आवश्यक हो, तब ही लोग यात्रा करें। देशवासियों ने उनकी अपील का सम्मान करते हुए अपनी बहुत सी यात्राएं स्थगित की हैं। आज के दिन बड़ी संख्या के लोग अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से इस संबंध में मांग करना चाहता हूं। मेरी जानकारी में यह है कि लोगों पर टिकट का कैंसिलेशन चार्ज लग रहा है। मैं मानवता के आधार पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोरोना के चलते लोग अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं, जिसकी माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी लोगों से अपील की है तो उन पर टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का परिचालन कोरोना का प्रभाव खत्म होते ही तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): स्पीकर सर, हम सुशील जी की बात का समर्थन करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): मंत्री महोदय की ओर से इस विषय पर उत्तर आना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर, श्री गिरीश चन्द्र एवं श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय, जिसे हम सब आपातकाल के नाम से जानते हैं, इस दौरान देश भर के लाखों लोगों को जेल में डालकर तरह-तरह की यातनाएं दी गईं।

महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्य इस यातना के शिकार हुए थे। इस दौरान इन लोगों के परिवारों ने भी बहुत प्रकार की यातनाएं सहीं और कई परिवार तो बर्बाद भी हो गए।

लोकतंत्र की रक्षा में इनके योगदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य भाजपा शासित राज्यों में इनको लोकतंत्र सैनानी का दर्जा देकर सम्मानित किया गया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली और कांग्रेस फिर से आई, तो फिर से इन पर अत्याचार हुआ।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि देश के लोकतंत्र की रक्षा में जिन्होंने योगदान दिया, जेल में निरुद्ध रहे, उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देकर और हर संभव मदद देकर सम्मानित किया जाए।

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Thank you, Sir. I wish to first and foremost convey my thoughts and prayers to the people, the families and the dear ones of the victims of this dreaded Coronavirus. I also commend the rapid response and proactive efforts shown by the Central Government and various State Governments to address this issue as also the doctors, the nurses and the medical community who are at the forefront putting their own health and lives at risk. I think that we have to sincerely thank them from the bottom of our hearts.

This is undoubtedly the first such outbreak in the age of social media, and it brings along with it a host of new kinds of problems of wholly different

dimensions, which needs to be addressed. There are so many rumours, conjectures, misinformation and fake news in abundance in the social media across various platforms. I would urge the Government to expedite and set up a dedicated social media handle to address the issues, and dispel fears and doubts of the common man who is already stressed by this unprecedented situation. At this point, inaccurate information should not be allowed to spread at any cost. The more we educate the easier we eradicate is my humble opinion.

I would also like to urge the Government to begin formulating a contingency plan for the daily wage labourers, the day-to-day vendors and the small businesses and traders who are facing livelihood threat as they do not have the luxury or option of sitting at home and waiting it out till the virus passes or this issue is resolved. I think that this has to happen parallelly and immediately so as not to precipitate this crisis any more. I thank you for giving me this opportunity.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती सुमलता अम्बरीश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Thank you Speaker, Sir. Today, I would like to bring to the notice of this House that the Indian Embassy in Manila has stopped responding to the students who are there at the airport.

Today, I happened to call a couple of students and they have mentioned this fact that the University is almost 80 kms. away from the airport and the

local transport is also stopped. Who is going to take care of those students? Our country has banned somewhere around 27 countries because of Coronavirus. What kind of measures are being taken by us for the students who are stuck at the airports in those countries?

My suggestion to this House would be that as we are having quarantine facilities, why we cannot bring back all the students to our country and lodge them in these quarantine facilities so that students and their families will be happy. What would be the fate of those students after 31st March? Something has to be spelt-out from the Government of India side in terms of the situation being faced by those students. We have to take care of the students and their parents also, and some sort of message has to be given to all the people in the country. The hon. Prime Minister should take initiative in addressing the safety of those students. This is my humble request to the Government of India, that is, to take this initiative.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मारगनी भरत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR):** Speaker Sir, on 17th March, 2020, we suffered a great loss due to heavy rainfall and gusty winds in the Shirpur taluka of Dhule district in my Parliamentary constituency of Nandurbar. A resident of Shirpur named Shri Rajendra Mali, aged 55 years died after a sheet of tin fell on him. Almost 3230 farmers have been affected in

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

as many as 44 villages. The District Administration is carrying out the assessment work.

I would like to request the Government through you Sir that compensation should be given to these farmers at the earliest and adequate financial assistance should also be provided to the families of the deceased.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसद में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जिन भाषाओं को अलाऊ किया गया है, उनमें से किसी भाषा में अगर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो पहले सदन को सूचना दे दें, ताकि उनकी भाषा का ठीक से अनुवाद किया जा सके।

12.46 hrs

SUBMISSION BY MEMBER ... Contd.

Re: Resuming of service of Budh-Purnima Express (14224/14223) and demand for 100 per cent refund of cancellation fee

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, अभी रेलवे का एक विषय आया था, जिसे दो-तीन माननीय सदस्यों ने उठाया था। इसमें "No cancellation fee will be charged for 155 cancelled trains. Passengers would get 100 per cent refund." यह ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से इश्यू हो गया है। …(व्यवधान)

_____

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपका विषय सदन में आ चुका है।

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Sir, I would like to thank you for allowing me to put forward the concerns related to my parliamentary constituency of Raigad, Maharashtra.

Budget allocation for the Ministry of Tourism has been just Rs.2500 crores. Also, the Ministry of Tourism has decided to cut down on theme-based tourism circuits under *Swadesh Darshan* scheme. Sir, my

parliamentary constituency Raigad in Maharashtra, with rich flora and fauna, attracts scores of tourists from across the globe. This influx of tourists also brings revenue and creates job opportunities to thousands of locals. The Ministry of Tourism, which functions as the nodal agency for development of tourism in the country, has been tirelessly making a headway in tourism infrastructure, promoting India as preferred destination, facilitating tourists visiting India by providing training and professional education so as to cater to the growing hospitality industry which is expected to reach a high value by the end of 2023. The said efforts are possible through implementation of various schemes. One such scheme under tourism infrastructure is *Swadesh Darshan*. The *Swadesh Darshan* scheme encompasses 13 thematic tourist circuits based on which I would like to recommend a few hotspots of tranquility and enlightenment in my Lok Sabha constituency of Raigad, Maharashtra. Nine coastal destinations are Anjarla, Murud, Jaigad, Malgund, Ganpatipule, Aareware, Bhatye, Guhaghar, Velneshwar.

I am aware that the list has turned out to be quite exhaustive. However, in the interests of holistic development of tourism, higher employment opportunities, and preservation of local culture and tradition, I would strongly recommend to the Government to kindly include the above-mentioned tourist hotspots under various categories of *Swadesh Darshan* Scheme. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): धन्यवाद सर, आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महाराष्ट्र में दो दिन पहले उत्तर महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ के जलगांव डिस्ट्रिक्ट और बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में काफी बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उसमें रबी की जितनी भी फसलें हैं, वे बर्बाद हो गई हैं, जिस कारण किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। जिला प्रशासन के माध्यम से वहां सभी किसानों का पंचनामा किया जा रहा है, लेकिन मेरी इस सदन के माध्यम से मांग है कि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी किसानों को जल्द से जल्द मदद देनी चाहिए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' है, उसके अंतर्गत सभी प्रपोजल्स को भी जल्द से जल्द सैंक्शन करके किसानों तक मदद पहुंचाई जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती रक्षा निखिल खडसे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, मैं आपका ध्यान कुआलालंपुर में फंसे हुए 60 भारतीयों की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन लोगों की टिकट हो गयी थी, बोर्डिंग हो गयी थी और इनका लगेज भी चला गया था, लेकिन लास्ट टाइम पर कह दिया गया कि भारत सरकार ने आपको बोर्डिंग करने से मना कर दिया है। भारत सरकार की इजाज़त मिलेगी तो आप बोर्डिंग करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि वहां कर्फ्यू लाइक स्टेज है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, खाना नहीं है, सारे मॉल बंद हैं और लोग परेशान हैं। बड़ी मुश्किल से उन लोगों को चावल मिले और कच्चे-पक्के चावल उन लोगों ने खाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उन लोगों को फौरन हिन्दुस्तान वापस लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. एस.टी. हसन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Sir, I rise to speak on the gravest issue that is currently facing us, the COVID-19.

Under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, India has so far been successful to address this pandemic and is able to prevent mass infection. In the wake of current situation, the prices of precautionary face masks have skyrocketed. I request the hon. Finance Minister, the hon. Commerce Minister and the hon. health Minister to look into a couple of issues. First, there should be a strict oversight to prevent hoarding and those indulging in it should be penalised. Second, the face mask is being subject to GST. I request that any type of tax on the face masks be lifted.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Lord Mountbatten rightly observed: "Mahatma Gandhi will go down in history on par with Buddha and Jesus Christ". Each iota of India has cherished the memory of Mahatma Gandhi, so also Payyanur in Kerala's Kannur district.

Payyanur in Kannur district is one of the rare places in Kerala associated with the blessed life of Gandhi ji. Gandhi ji visited the Ashram of Swami Ananda Theertha at Payyanur on 11th January, 1934. Swami Ananda Theertha was the last disciple of Sree Narayana Guru and was known for his ardent fight against the social injustices and caste discrimination in Kerala. Gandhi ji spent the whole day in Ashram and planted a mango tree which is still thriving. The ashes from the funeral pyre of Gandhi ji are also preserved there.

The Ministry of Culture, Government of India, had constituted a Gandhi Heritage Sites Panel in 2006 whose Report identified 39 core sites and created a Master List of 2000 sites visited by Mahatma Gandhi to be preserved for

posterity. The Panel recommended the setting up of a Gandhi Heritage Sites Mission and accordingly the Mission was set up in 2013.

The Government of Kerala has proposed a Mahatma Gandhi Smriti Museum at the Old British Police Station, a protected monument at Payynur, at an estimated cost of Rs. 4.45 crore. On this 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, the Government of India may be pleased to given financial assistance from the Gandhi Heritage Sites Mission to set up the proposed museum at Payyanur. It would be a fitting tribute to both Gandhi Ji's legacy and to Payyanur.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में मेरे क्षेत्र की बात रखने का समय दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा में देश का दूसरे नंबर का ग्रीन एयरपोर्ट है। वडोदरा गुजरात का तीसरे नंबर का बड़ा शहर है। इस एयरपोर्ट से भरूच, छोटा उदयपुर, पंच महल, गोधरा और आणंद से यात्री विदेश जाते हैं। मैं आपके माध्यम से नागर उड्डयन मंत्री जी से वडोदरा ग्रीन एयरपोर्ट पर hub-and-spoke यानी इमिग्रेशन की सुविधा शुरू करने की मांग रखती हूं। जल्द से जल्द से यह सेवा वडोदरा एयरपोर्ट पर शुरू की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Hon. Speaker, Sir, to give relief to the rural economy, the Government has exempted Agricultural Produce Marketing Committees (APMCs) from the purview of the two per cent tax deducted at source on payments above Rs.1 crore. The two per cent TDS was introduced to discourage cash transactions and to encourage transition towards a less-cash economy. Speaker, Sir, I would like to suggest to the Minister of Finance to increase the limit of Rs.1 crore to Rs.2.5 crore or Rs.5 crore to help traders who are facing problems in making payment to farmers who refuse to accept cheques. The traders cannot absorb the two per cent TDS. The problems of farmers are really genuine. They come to towns to sell their agricultural products and use cash to purchase seeds, fertilisers and other farm inputs. Villages do not have efficient banking facilities like towns. Hon. Speaker, Sir, through you I would like to urge upon the Minister of Finance to increase the limit of Rs.1 crore to Rs.5 crore so that there can be easy transactions.

माननीय अध्यक्षः श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Mr. Speaker, Sir, I represent Nagarkurnool Parliamentary Constituency in Telangana State which is in a very backward region. The population of ST community is predominantly high at more than three lakhs in Achampet. The literacy rate there is very low. While the Union Government and the State Governments have started a lot of

schemes and welfare programmes for development of SC/ST communities, the fruits of most of those schemes are yet to reach the beneficiaries. It is learnt that a total of 226 Ekalavya Model Residential Schools (EMRSs) are functioning across the country by the end of 2018. It is high time the Government established such an EMRS at Achampet which comes under my Parliamentary Constituency Nagarkurnool. Due to lack of sufficient schools, particularly Ekalavya Model Residential Schools, students belonging to ST community are facing a lot of hardships in getting quality education. I firmly believe that establishment of an Ekalavya Model Residential School at Achampet is the need of the hour. Keeping that in view, I would earnestly request the Union Government and the hon. Minister of Tribal Affairs to kindly accord approval for sanctioning of an Ekalavya Model Residential School at Achampet so that students belonging to ST community there get an opportunity to get quality education without putting any financial burden on their parents.

माननीय अध्यक्षः श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री रमुलु पोथूगन्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government to the need of constructing departmental buildings for various Post Offices in my Constituency Attingal, Kerala. Even though the Postal Department has its own land, construction of buildings is pending at many places. The Post Office at Pangode is presently functioning

from a rented building with a monthly rent of Rs.7,500. The Department owns about 25 cents of land here. The Post Offices at Varkala, Vithura, Avanavanchery, Perumkuzhy and Palayamkunnu also have no buildings of their own. The Postal Department has already purchased land at Varkala, Perumkuzhy, Avanavanchery, Palayamkunnu and Vithura. Yet, all these Post Offices are presently functioning from rented buildings. The demand for construction of buildings for these Post Offices is pending for long and the work was proposed to be completed in the 10th Five-Year Plan. I request the Government to consider this matter and take necessary steps for construction of buildings for these Post Offices.

माननीय अध्यक्षः श्री कुलदीप राय शर्मा को एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.00 hrs

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष जी, एयरसेल एक कंपनी थी, जो भारतवर्ष में मोबाइल सर्विसेज़ ऑफर करती थी, वह मैक्सिस कम्युनिकेशन था। जब वह बिहार में लॉन्च हुआ तो उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था और उसके बाद वह कंपनी बंद हो गई। नेटवर्क बढ़ाने के लिए एयर-मैक्सिस वालों ने बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रीब्युटर्स अपॉइन्ट किए, किसी से पांच लाख रुपये लिए, किसी से दस लाख रुपये लिए, उसके बाद वह कंपनी बंद हो गई। आज बिहार में कम से कम हजारों ऐसे लोग होंगे, मैं संख्या तो नहीं जनता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने इसमें इनवेस्ट किया था और वह कंपनी जब बंद हो गई तो इन सब लोगों की पूंजी डूब गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने अपना इनवेस्टमेंट किया था, क्योंकि कम दाम में सबसे ज्यादा बिकने वाली बिहार की टेलिफोन सर्विसेज़ यही थी,

इसलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बने और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो मेहनत की पूंजी लगाए थे, उनके पैसे वापस करने की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): अध्यक्ष जी, मैं सदन में एक गंभीर विषय रखना चाहता हूँ, जो मुझसे संबंधित है। पश्चिम बंगाल के प्रशासन द्वारा स्थानीय राज्य सरकार के निर्देश के माध्यम से प्रतिदिन नियम-कानून का उल्लंघन करते हुए शांति व्यवस्था भंग हो रही है। महोदय, दिनांक 17.03.2020 को रात में लगभग एक से दो बजे के बीच बिना किसी सूचना के हमारे आवास, ठाकुरबाड़ी में राज्य सरकार के प्रशासन की लगभग आठ से दस गाड़ियां जबरन घर में घुस गयीं और हमारे घर से सामान लूट लिया गया तथा हमारे कार संचालक और कुछ समर्थकों को बंदी बना लिया गया है। …(व्यवधान) प्रशासन के द्वारा हमारे घर-परिवार के सदस्यों को अपशब्द और मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को अन्दर करने का विचार चल रहा है। महोदय, इसके साथ पश्चिम बंगाल पुलिस ने मेरे घर के सामने घेराबंदी कर रखी है, जिससे न कोई बाहर आ पा रहा है और न ही कोई अंदर जा पा रहा है। …(व्यवधान) यह घटना पहली बार नहीं हुई है। जब भी मैं संसद की कार्यवाही में भाग लेने दिल्ली आता हूँ, हमेशा राज्य प्रशासन हमारे परिवार के ऊपर अत्याचार करता है, जिसकी वजह से हमारे परिवार के अन्दर एक डर का माहौल पैदा हुआ है। सर, मैं बहुत दुख के साथ यह कहना चाहता हूँ कि एक सांसद के साथ अगर ऐसा होता है, तो आम नागरिक वहां कैसे जीवन बिता रहा होगा? …(व्यवधान) मैं इस विषय पर आपको बताना चाहता हूँ। …(व्यवधान) एक बात है कि जो पश्चिम बंगाल के आम नागरिक, आप जो सोच रहे हैं कि एक समय था जब डाकू आ कर घर में लूट लेता था, लेकिन अभी इतना डर पैदा हुआ है कि पुलिस-प्रशासन गाड़ी ले कर आता है और घर लूट कर ले जाता है, डकैती कर लेता है।

…(व्यवधान) मैं यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। …(व्यवधान) इस विषय को सुरक्षा देने के लिए आप थोड़ी कृपा करें। …(व्यवधान) इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। …(व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशील कुमार सिंह, डॉ. सुभाष सरकार, श्री सौमित्र खान, श्री हरीश द्विवेदी, श्री राम कृपाल यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री जॉन बर्ला एवं श्री राजीव प्रताप रूडी को श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए आग्रह आया है। मैं प्रयास करूंगा कि विधायी कार्य के पश्चात शाम को सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया जाए।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

———————

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri A. Raja *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now we will take up Item No. 11 – Matters under Rule 377.

(i) Need to declare Manjhi Garh and Karah Garh in Saran district, Bihar as heritage sites and develop them as tourist places

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोक सभा, बिहार के सारण (बिहार) जिलान्तर्गत मांझी प्रखंड के मांझीगढ़ एवं बनियापुर प्रखण्ड के कराहगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूँ।

उपर्युक्त दोनों गढ़ ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल के इतिहास में भी दोनों गढ़ों की महत्ता और विशेषता के संबंध में चर्चा है। आज भी इन स्थलों पर अनेकों लोग देश, प्रदेश यहां तक कि विदेशों से भी इसे देखने के लिए आते हैं। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि उक्त दोनों गढ़ों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घोषित कर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। ऐसा होने से हमारे संसदीय क्षेत्र के विकास के साथ-साथ देश के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मांझीगढ़ एवं कराहगढ़ को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करते हुए पर्यटनीय दृष्टि से विकसित करने के लिए अलग से पैकेज दिया जाए।

(ii) Need to establish a Central Agriculture University in Santhal Pargana region of Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, seventy per cent of the Jharkhand State's population lives in rural areas and is primarily dependent on agriculture, but unfortunately, the condition of agriculture is not good in the State. The State lacks critical inputs such as new technology, good quality seeds, research, and extension network to transform its agricultural practices in a big way. The Government is focussing on agriculture in a major way; but we need more support from the Government.

I would, therefore, request the Government to kindly consider setting up a Central Agriculture University in Jharkhand on the same lines as is being planned for Meghalaya. Both Meghalaya and Jharkhand have a large tribal population and both the States are rich in forest and mineral wealth, but lag far behind in agricultural production. It will be in the interest of the State if a Central Agriculture University is established in Santhal Pargana region of Jharkhand State, which is a historically deprived and backward region of the State.

(iii) Regarding establishing a Nepali Language Council

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Sir, Nepali language is one of the 22 languages recognised under the VIII Schedule of our Constitution on 20th August, 1992. Across India, there are over 1.5 crore Nepali-speaking citizens.

Even though it is recognised as a second language in West Bengal and Sikkim in theory, very little has been done for promotion and preservation of the language.

Even after almost three decades since the recognition of Nepali under the Scheduled languages of India, there is not even a single dedicated DD Nepali or AIR Nepali channel.

Academically, nothing much has been done to preserve the language. Central Universities like Visva Bharati in West Bengal do not offer any course in Nepali; schools in Darjeeling and Dooars, where majority are Nepali-speakers, do not have proper teachers and study materials.

I request the hon. HRD Minister to establish a Nepali Language Council with the mandate to preserve and promote Nepali language in India.

(iv) Need to resume the construction of bypass road in Gumla city in Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा (झारखंड) के अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक जनहित के मुद्दे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच.23 पर गुमला शहर में निर्माणाधीन गुमला बाईपास के अधूरे निर्माण कार्य से स्थानीय जनता को हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

गुमला शहर के लगातार हो रहे विस्तार के कारण शहर में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम के कारण स्थानीय जनता बहुत परेशानी में है। मेरे द्वारा 15वीं लोक सभा से ही यह मुद्दा उठाया जाता रहा है, परिणामत: गुमला बाईपास पास हुआ, बहुत प्रयासों के पश्चात कार्य भी प्रारम्भ हो सका, परन्तु कार्य प्रारम्भ होने के कुछ दिन बाद से ही निर्माण कार्य बंद पड़ा है। अधूरे पड़े निर्माण कार्य के कारण स्थानीय जनता बहुत परेशान है। इस पर आवागमन करने वाले दिनोंदिन बढ़ रहे वाहनों की संख्या के कारण स्थानीय जनता सहित, संपूर्ण क्षेत्रवासी अथवा वाहन चालकों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, उपरोक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि निर्माण कार्य रुकने के पीछे कौन-कौन से मुख्य कारण रहे? निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था, कार्य को कब तक पूरा किये जाने का अनुबंध किया गया था? काम रोकने संबंधित निर्माणन कंपनी के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया गया? जनता की परेशानी को देखते हुए, सरकार कब से निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार कर रही है? क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्य रोकने के पश्चात जनता को हो रही परेशानियों की कोई भी, किसी भी स्तर पर समीक्षा की गई है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना करूँगा कि गुमला की जनता को हो रही परेशानी और असुविधा को ध्यान में रखते हुए गुमला बाईपास के निर्माण कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ किया जाए तथा अभी तक के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच करते हुए संबंधित के विरूद्ध ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में जनहित के किसी भी निर्माण कार्य में कोई लापरवाही बरते जाने की पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद।

(v) Need to expedite construction of Ramganj Mandi-Bhopal railway line

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): The Ramganj Mandi-Bhopal train line had been sanctioned long time back but the work is not progressing and the train line has reached only up to Jhalawar. The major portion of the line from Jhalawar to Bhopal is still pending and getting delayed repeatedly. Sir, in my constituency of Jhalawar-Baran, the organic farming of oranges and coriander is undertaken on a large scale and is expected to grow more in future. This train line post completion will help the farmers and traders of my constituency to market their produce and help them prosper by fetching fair market prices for their produce.

I, therefore, urge the hon. Railway Minister to expedite the construction of the railway line.

(vi) Need to run a superfast train from Guna Parliamentary Constituency to Delhi

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के अन्तर्गत तीन जिले गुना, अशोक नगर और शिवपुरी आते हैं। इन तीनों जिला मुख्यालय से प्रतिदिन होकर गुजरने वाले दिल्ली के लिए एक भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। भारत सरकार के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यालय यहां स्थित हैं। इन कार्यालयों के कर्मचारियों को अगर किसी कार्यवश दिल्ली आना हो तो उन्हें भोपाल या बीना रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। मैं स्वयं भी अपने गृह जिला अशोक नगर से दिल्ली आना चाहूँ तो उसके लिए बीना रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से आदरणीय रेल मंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अशोक नगर होते हुए दिल्ली के लिए प्रतिदिन चलने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन की शुरूआत की जाए।

(vii) Need to conduct a fresh survey to include all eligible people under Ayushman Bharat Yojana

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की गरीब जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई और देश की गरीब जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखा।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना सर्वे के दौरान बहुत से गरीब परिवार इस सर्वे से छूट गए हैं। कृपया इसकी ओर ध्यान देकर दोबारा से सर्वे कराया जाए और जो लोग इस योजना के तहत छूट गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिले।

(viii) Regarding water related problems being faced by farmers

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में तथा महाराष्ट्र राज्य में बड़े पैमाने पर बेमौसम बारिश हुई और ओले गिरे, जिससे कि वहां भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। सभी फसलें जमींदोज हुई है। सब फसल हार्वेस्टिंग स्टेज पर थीं। उन्हें इस नुकसान से उबारने के लिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि 48 घंटे में बीमा कंपनियां उनका पंचनामा करें और एन.डी.आर.एफ. द्वारा मदद के लिए महसूल द्वारा पंचनामा करने के शीघ्र से शीघ्र निर्देश दिए जाएं।

महाराष्ट्र के किसान पहले से ही परेशान हैं, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण उनका हाल और बदहाल हो गया है। ऐसे वक्त उनकी नजरें मोदी सरकार और केन्द्र सरकार की तरफ हैं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kaushal Kishore – Not Present.

Shrimati Darshana Vikram Jardosh

(ix) Need to include more hospitals in Surat, Gujarat in the Panel of Hospitals under Pradhan Mantri Relief Fund

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के सीधे मार्गदर्शन में देश में आरोग्य के क्षेत्र में चलाया जा रहा प्रधान मंत्री राहत कोष सामान्य आदमी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रमाणित हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं में उनकी परिधि में जो परिवार नहीं आते, उनके लिए कैंसर, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट एवं अन्य गंभीर बीमारियों में लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र सूरत में प्रधान मंत्री राहत कोष के पैनल में सिर्फ 2 अस्पताल हैं। सूरत में सबसे नजदीकी अस्पताल जो कि इस पैनल में है, वह कम से कम 200 से 250 किमी दूर नडियाड में है और वह भी सिर्फ किडनी के लिए है। समग्र दक्षिण गुजरात में बहुत बड़ी मात्रा में आबादी रहती है। सबसे बड़ा वनवासी जिला दक्षिण गुजरात में होने के कारण यह आवश्यक है कि आयुष्मान भारत योजना में जो परिवार सम्मिलित नहीं हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री राहत कोष के पैनल में दक्षिण गुजरात से आर्थिक राजधानी होने के कारण सूरत में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए।

(x) Need to include certain castes of Chhattisgarh in the list of Scheduled Castes

श्री मोहन मण्डावी (कांकेर): महोदय, छतीसगढ़ में माहार, महारा, माहारा जाति के लोग निवासरत हैं, जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति में महार, मेहर, मेहरा को पंजीयन क्रमांक-33 में अधिसूचित किया गया है, जबकि दोनों जाति एक ही हैं। छतीसगढ़ी भाषा में महार को ही महरा, माहरा, महारा जाति से संबोधित करते हैं, जो कि महार जाति का ही अपभ्रंश है। छतीसगढ़ राज्य में जब भाजपा की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सरलीकरण कर माहरा, महारा, माहारा जाति को प्रमाण पत्र देने हेतु आदेशित किया। किन्तु कुछ लोगों के द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रकरण दायर कर निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। तब से अब तक इस वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है।

केन्द्र को वर्ष 2004, 2008, 2010 में भेजे गए प्रस्तावों में पर्याप्त मात्रा में मानव शास्त्रीय रिपोर्ट एवं संदर्भ साहित्य संलग्न नहीं था। हमारे समाज के लोगों में भी अशिक्षा पिछड़ेपन होने के कारण भारत के महापंजीयक (आरजीआई) आपत्तियों को नहीं समझ पाए। उक्त वर्ष में भेजे गए प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक द्वारा खारिज कर दिया गया, परंतु 13 जून, 2016 को भेजे गए प्रस्ताव में पर्याप्त मात्रा में मानव शास्त्रीय रिपोर्ट संदर्भ साहित एवं अन्य शासकीय दस्तावेज संलग्न कर भेजा गया था। जिसमें महरा, माहरा जाति की उत्पति पहचान और अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने से पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं।

अत: छतीसगढ़ के उक्त वर्ग की माँग को सदन के माध्यम से संज्ञान में लेते हुए नियमत: उचित कार्रवाई की माँग करता हूँ।

(xi) Need to construct roads in villages under Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) के अन्तर्गत थानागाजी में रह रहे अजा/अजजा/बीपीएल परिवारों की अत्यंत गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए शीघ्र समाधान किए जाने का आग्रह करती हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा राजस्थान के अन्तर्गत थानागाजी तहसील क्षेत्र में भी उक्त आवंटन प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम रूप का बास व भंगडोली के अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्तियों को ग्राम मुण्डियावास, तहसील थानागाजी में भूमि का आवंटन वर्ष 1976 में किया गया था। सभी आवंटित भूमि के खातेदारों को अपने-अपने खेतों तक पहुंच मार्ग की प्रशासन द्वारा आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन सभी की आवाजाही अन्य खातेदारों की दया पर ही निर्भर है। आने-जाने को लेकर खातेदारों में आपसी झगड़े भी होते रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आवंटी खातेदार भूमि आवंटन काल से ही पहुंच मार्ग की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रशासन से निरन्तर गुहार लगाते रहे हैं।

मैं सरकार से इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु अनुरोध करती हूं कि थानागाजी तहसील कार्यालय के पीछे से चैकत्वंक जो ग्राम लावा का बास-जोधावास-कीरों की ढाणी होते हुए ग्राम टोडी तक पहुंचती है, में जोड़ते हुए एक नया मार्ग खसरा नं. 128, बारानी तृतीय रकबा 6.4700 है, भूमि में से बनाते हुए चडलेल के अन्तर्गत डामरयुक्त या सीसी रोड ग्राम खेडा मुण्डियावास तक बनवाकर लगभग 600 व्यक्तियों (अजा/अजजा/बीपीएल) को आवाजाही की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करती हूँ कि संदर्भित चैकत्वंक आधा भाग जो टोडी ग्राम की ओर जाता है, वर्षा के कारण पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता है।

(xii) Need to develop Ganga river front in Farrukhabad, Uttar Pradesh

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): माननीय सभापति जी, फर्रूखाबाद अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहां गंगा तट पर माघ माह में प्रयागराज के बाद कल्पवासियों का एक महीने तक राम नगरिया मेला लगता है जहां पूरे देश से श्रद्धालु संत आकर एक माह गंगा तट पर कल्पवास करते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के गंगा तट पर स्थित ढाई घाट, पांचाल घाट, श्रंगीरामपुर, अटैना घाट पर स्नानार्थियों की सुविधा के लिए स्नान घाट नहीं बने हैं, जिससे कि प्रतिवर्ष कई स्नानार्थी गंगा की लहरों में समा जाते हैं। मात्र एक स्नान घाट पांचाल घाट पर बना है जो कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अपर्याप्त है।

फर्रूखाबाद में भी गंगा जी के दोनों ओर रिवर फ्रंट का निर्माण करने का कष्ट करें। इससे मेरे अति पिछड़े क्षेत्र फर्रूखाबाद के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा एवं गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने में भी सहयोग मिलेगा।

(xiii) Regarding appointment of Computer Teachers in schools

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय सभापति जी, देश के विभिन्न राज्य जैसे – बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात इत्यादि राज्यों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी@ स्कूल योजना के तहत पिछले आठ-दस सालों से कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही थी जो पिछले तीन-चार सालों से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्यों में ठप्प है।

एक तरफ देश के छात्र-छात्राएं कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित हैं, दूसरी तरफ पिछले आठ-दस सालों से कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।

अत: महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक को पुन: बहाल करने का कार्य जल्द से जल्द किया जाए।

(xiv) Need to take adequate measures in hospitals to tackle Corona Virus menace in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री रामदास तडस (वर्धा): चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक दुनिया के ज्यादातर देशों तक पहुंच चुका है। भारत इन देशों में से एक है। भारत में भी लोग कोरोना वायरस की वजह से दहशत में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि सेवाग्राम आश्रम, विनोबा भावे जी की कर्म भूमि पवनार आश्रम, महानुभाव की काशी रिद्धापुर, बोर व्याघ्र प्रकल्प एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय है। यहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं तथा हिन्दी विश्वविद्यालयों में देश-विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। देश-विदेश से लोग आने के कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। देश में लगातार संदिग्ध मरीज सामने आने से कोरोना के बचाव के साधनों की मांग बढ़ गई है। सतर्कता रखने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, एलर्जी की दवाओं को पर्याप्त मात्रा में रखने की आवश्यकता है एवं अस्पतालों में एन-95 मास्क (विशेष मास्क) तथा पीपी किट्स उपलब्ध करने की आवश्यकता है।

अत: आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) के कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु एवं सतर्कता रखने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, एलर्जी की दवा का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखने हेतु एवं अस्पतालों में एन-95 मास्क (विशेष मास्क) तथा पीपी किट्स उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे कि सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से रोकने हेतु इसका लाभ मिल सके।

(xv) Need to conserve our environment, water and wildlife

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Hon. Chairperson, Sir, to educate young generations, the need to conserve our environment, water and wildlife and forest and need to educate our coming generations about the manifold increase in vehicles, a subject on the same from class 6th onwards should be included in every Board, be it CBSE, ICSE, IB or State Boards.

(xvi) Regarding testing facilities in National Institute of Virology Alappuzha and Institute of the Virology, Thiruvananthapuram

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to invite your kind attention towards the Corona Virus outbreak which has been declared as a health emergency by the World Health Organization. The Department of Health in Kerala has taken all precautionary measures and multiple level surveillance mechanism is in place. But the biggest impediment faced in such disease outbreaks, which was seen also during the NIPAH virus outbreak, is the inadequacy of virus testing facility in the country. Currently, for any advanced viral testing, the only centre in India is the National Institute of Virology in Pune. It is a matter of grave concern that there is only one advanced centre for virology testing catering to 130 billion population of the country. It is highly adequate in a country like India to have only one viral testing centre and this delays the detection and containment of deadly

infectious diseases like NIPAH, Corona Virus and other similar diseases. This causes delay in getting the results and affects the strategy of containment of such deadly infectious diseases. Hence, I request the Ministry of Health and Family Welfare to take immediate steps to provide funding support to develop testing facilities in the National Institute of Virology in Alappuzha and Institute of Advanced Virology in Thiruvananthapuram and make them centres of excellence to tackle such disease outbreaks.

(xvii) Regarding MSP for Pulses and Millets

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): My Parliamentary Constituency Nandyal of Andhra Pradesh lies in a scarce rainfall area. The Minimum Support Price declared for pulses and millets is not sufficient to cover the production cost. In addition to this, the Government agencies are not procuring the pulses and millets in a timely manner. As a result of lack of procurement by the Central Government agencies, the current rate is Rs. 1000, less than MSP for both the products. Hence, this situation is forcing the farmers to store the crops at private cold storages. Due to this, the farmers are neither able to close their previous loans nor able to secure new crop loans.

In this regard, I would like to request the hon. Minister for Agriculture and Farmers Welfare, through you, to instruct the agencies like NAFED, SFAC to do the necessary procurement at the earliest, so that the farmers could be benefited.

(xviii) Regarding Re-development of old and dilapidated buildings in Maharashtra

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): महोदय, मुंबई में केन्द्र सरकार और उनके उद्यम, ट्रस्ट की जमीन पर स्थित पुरानी इमारतें, जो आज मरम्मत करने की स्थिति में भी नहीं हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं। मुम्बई में पोर्ट ट्रस्ट, एन. टी. सी., एल. आई. सी., रेस, बी. ए. आर. सी., जैसे कई केन्द्र सरकार के उद्यम हैं। इनकी जमीन पर जो पुरानी (सौ साल से भी पुरानी) इमारतें हैं। इन्हें पुनर्विकसित करने की आवश्यकता हैं। न उन्हें पुनर्विकास करने की अनुमति दी जाती हैं न ये उद्यम खुद इसका विकास करते हैं और वहां रहने वाले हमारे नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ चल रहा है। रेस तो जबरदस्ती 24/30 साल से उभरी हुई झोपड़ियों को जबरन तोड़ देती है, जिससे उनमें रहने वाले परिवार बेघर हो जाते हैं। एक तरफ हम पक्के घर देने का वादा करते हैं, दूसरी तरफ यह पुरानी इमारतें, जो कभी भी ढह सकती हैं। इसलिए केंद्र सरकार तुरंत इन मकानों, इमारतों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की सुरक्षा और विकास की नीति घोषित कराकर राहत दें। यही विनती है।

महाराष्ट्र सरकार ने जो पुनर्विकास और एसआरए के कानून पारित किए हैं। उस पर अगर अमल करने की अनुमति प्रदान की तो इस समस्या का निवारण होगा।

(xix) Need to take adequate measures to prevent outbreak of Corona Virus in Gaya Parliamentary Constituency, Bihar

श्री विजय कुमार (गया): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गया (बिहार) में कोरोना वायरस की रोकथाम का विशेष इन्तजाम किया जाए। हवाई रूट बंद किया जाए, क्योंकि यहां चीन, जापान, कोरिया से बौद्ध पर्यटक आते रहते हैं। गया को बोध गया कहा जाता है। यह बुद्ध की धरती है। यहां एक जापानी महिला मिली है, जिसके अन्दर कोरोना होने की पुष्टि हुई है।

14.35 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

(xx) Need to bring back Indian medical students stranded in Phillipines

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, पूरा विश्व इस समय कोरोना के कहर से जूझ रहा है, ऐसे में हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सार्थक कदम उठाकर विदेशों में जो हिन्दुस्तानी रह रहे हैं, उनकी वतन वापसी से लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। फिलीपींस देश में 1500 भारतीय मेडिकल छात्र फंसे हुए हैं। वहां की सरकार ने उन्हें तीन दिन में हिन्दुस्तान जाने के लिए निर्देश दे दिए हैं, मगर 17 मार्च से भारत में फिलीपींस की सारी उड़ाने रद्द कर रखी हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स फिलीपींस के मनीला शहर में हैं, जिसमें से 50 छात्र मेरे नागौर जिले के हैं, वहीं 200 से अधिक छात्र पूरे राजस्थान के हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि विशेष विमान चलाकर उन छात्रों को हिन्दुस्तान लाया जाए और वहां की सरकार उन्हें तब तक तंग नहीं करे। इसके लिए भी विदेश मंत्री जी और भारत सरकार वहां की सरकार से बात करें। कई छात्र वहां पर हवाई अड्डे पर ही फंसे हुए हैं। अगर समय रहते उन्हें वहां से नहीं निकाला गया तो वहां की सरकार उन्हें वहीं पर पाबंद कर देगी, इसलिए इस संवेदनशील मामले पर तत्काल प्रभाव से सरकार संज्ञान ले।

(xxi) Regarding establishing a Kendriya Vidyalaya in Mettupalayam area of Coimbatore district

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, Nilgiris Parliamentary Constituency is located in Coimbatore, Tiruppur, Erode and the Nilgiris districts of Tamil Nadu. There are three Kendriya Vidyalayas in my constituency which lie in the hills of the Nilgiris district, namely, Aruvankadu, Ooty and Wellington. Coimbatore, Tiruppur and Erode districts are plains and approximately 50 kilometres away from the Central Schools situated at Nilgiris district. The only source to reach the schools from plains is Government buses. Thus, the children of the plains suffer a lot as it affects their time as well as their studies.

I, therefore, request the hon. Minister to establish a Kendriya Vidyalaya in Mettupalayam area of Coimbatore district so that the poor children of Coimbatore, Tiruppur and Erode districts could get good education.

———————

14.37 hrs

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA BILL, 2020

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to move:

> "That the Bill to provide for the establishment of an Institute of Teaching and Research in Ayurveda and to declare it as an Institution of national importance for the promotion of quality and excellence in education, research and training in Ayurveda and allied disciplines and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

14.37 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

महोदय, भारत सरकार में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर, जामनगर में विद्यमान आयुर्वेदिक संस्थानों के समूह अर्थात आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेदिक महाविद्यालय और फार्मेसी यूनिट सहित आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल विज्ञान संस्थान को सम्मिलित करके तथा महर्षि पतंजलि योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के स्वस्थ वृत्त विभाग में शामिल करके आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

महोदय, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। आयुर्वेद के ज्ञान एवं सेवाओं के प्रति पूरे विश्व में रुचि एवं मांग बढ़ रही है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज तक कम से कम

14 राष्ट्रों से हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, दस विश्वविद्यालयों में हमने चेयर दी हैं, वहां हमारे प्रोफेसर्स वहां जाकर आयुर्वेद एवं बाकी पैथी के बारे में पढ़ा रहे हैं। हमारे कम से कम 58 इन्फार्मेशन सेंटर्स 28 राष्ट्रों में शुरू किए गए हैं। ये सब देखते हुए, भारत आयुर्वेद का उद्गम देश है और पूरा विश्व आयुर्वेद में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली अत्याधुनिक संस्थाओं के लिए भारत की ओर देख रहा है। प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने से आयुर्वेद शिक्षा के मानकों का स्तर बढ़ाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार आयुर्वेद में विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करने, उन्नत मूल्यांकन प्रक्रिया विधि अपनाने आदि के लिए स्वायत्तता निश्चित तौर से मिलेगी।

इसका कार्य जनमानस के बीच आयुष की गहरी पैठ बैठाने के लिए स्वयं अपने प्रमाणन पाठ्यक्रम तैयार करना है और देश के समक्ष प्रमुख जन-स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए आयुर्वेद की छिपी क्षमताओं को बाहर लाने का अवसर प्रदान करना है। इससे संस्थान को आयुर्वेद में तृतीय परिचर्या विकसित करने और अंतरविषयक सहयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी, ताकि आयुर्वेद को समकालीन महत्व प्रदान किया जा सके।

महोदय, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में आयुष पद्धतियों की तेजी से बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका के महत्व को बढ़ावा मिलेगा। आयुर्वेद के मजबूत होने से स्वास्थ्य पर सरकारी खर्चे में भी कमी आएगी, क्योंकि इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के कारण आयुर्वेद किफायती होगा।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बिल का समर्थन करके इसे पारित करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

" कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और उसे आयुर्वेद और सहबद्ध शाखाओं शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity to speak on the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020.

This is a Bill that is both welcome and disappointing. There is so much interest in our traditional healing system and it should not come as a surprise to anyone because it comes at a time of unparalleled popularity and mainstream acceptance of Ayurvedic practice, both domestically as well as internationally, as the Minister has said.

From the perspective of market conditions, in 2015, the global market for Ayurvedic products, according to our own Government figures, amounted to nearly 3.4 billion dollars, a number that will nearly triple to 9.7 billion dollars by the year 2022, growing at 16.2 per cent. In a recent report, the forecasts predicted were astonishing. The sale of Ayurvedic products is expected to rise three-fold to 8 billion dollars by 2022 from 2.5 billion dollars in 2015, and at this time, an estimated 77 per cent of Indian households are using Ayurvedic products. Similarly, the export of such products from India, on an average, is about 780 million dollars a year, and is expected to grow by 20 per cent annually.

Sir, which State has been the engine of such remarkable growth and expansion in the field of Ayurveda?

HON. CHAIRPERSON: Kerala!

DR. SHASHI THAROOR: Kerala, of course! Well said, Sir.

The State harbours nearly 1,400 industries associated with Ayurveda, which pull in a combined total of 37 million dollars and exports of 8.6 million dollars in addition to an overall 10 per cent market share of the total Indian market for herbal based products and treatment.

Now, as you all know, the origins of Ayurveda can be traced back to the Vedas, starting from mentions in the Rig Veda and subsequently in the Atharva Veda. The term itself derives epistemologically from the word 'ayur' or life in Sanskrit and 'ved' or science, and, therefore, it means 'the science of life'. There is also a general consensus that the practice of Ayurveda was codified in the three main cannons, the *Charaka Samihita*, the *Sushruta Sahmita*, and the *Ashtangahridayam.*

In terms of its remarkable approach to treatment, there is arguably no equivalent of Ayurveda in Western medicine. As many experts have pointed out, unlike European biomedicine, which visualised and conceptualised the body in the form of dissections, Ayurveda looked at the body as a series of systems where the balance of the key elements was to lead a healthy life and longevity. In fact, legend has it that the *Ashtangahridayam* composed by the

famous practitioner Vaghbatta, reached Kerala sometime around the 6th Century BC, which is 2,600 years ago, and it subsequently reached the legendary eight Vaidyar families who, with the help of Kerala's favourable climate and abundant presence of medicinal plants, were responsible for planting the seeds that today have made Ayurveda popular across the world.

Sir, Ayurveda is also associated with Indian nationalism. During the colonial rule, the popularity of Ayurveda rose nationally, first because of the fact that the British were indifferent to the health of Indians, leading to a poor public health infrastructure and the outbreak of several epidemics like the Bombay plague. This meant that traditional medicine was the only option of ordinary Indians and so, Ayurveda came back into popularity. The second reason, of course, was because of the most politically charged revival of interest in our past that the nationalist movement evoked and that led to a renewed interest in Ayurveda.

Of course, in the post-Independence era, under many Congress Governments and others, Ayurveda has revived, and along with Yoga and the larger concepts of India's wellness, we have begun to see a soaring popularity for Ayurveda, which is particularly relevant today when the world is paying more attention to human wellness rather than merely the treatment of symptoms. More and more people around the world are turning to Ayurveda as a preferred source of treatment.

At the same time, in these conditions, there are factors that continue to pose challenges to our aim, to realise the full potential of Ayurveda. The first of these is research and documentation, which of course, I understand, the Bill seeks to address.

I want to tell you, Sir, that sometime around June 2018, a Paper was published by Dr. Cyriac Abby Philips in the American Journal of Gastroenterology. He is a liver specialist, and he talked about how the consumption of an age-old Ayurvedic digestive, *Dashamoolarishtam*, had caused a severe damage to his 40-year-old patient's liver akin, he says, to what would have been comparable to an unhealthy and frequent consumption of alcohol. This article did a lot of damage to India and abroad. Many questioned the safety of Ayurvedic treatment; many Ayurvedic practitioners were not happy, but the fact is, whether you agree or disagree with Dr. Philips, the incident nevertheless revealed the major weakness of our Ayurvedic practice, and that has to do with credible documentation.

Just the sheer speed of how much damage one article and one peer reviewed, a medical journal of repute can do against a traditional practice that dates back 5,000 years is telling. The lack of credible documentation as a concern may come across as a paradox to many because, of course, Ayurveda has been gaining in popularity. But what is interesting is that in western science, they say that 'for science, you must have a clear diagnosis, a

clear prescription, the prescription resulting in such and such results, you document it, you show your research. That is how the science is established.'

Ayurveda is much more instinctive, rather like our ragas, where the basic raga is laid down, and each player plays his own tune improvising from it. Similarly, with Ayurveda, each individual Ayurvedic practitioner will treat each patient differently.

We had a situation where a British Committee on Science and Technology in 2010 headed by the then President of the World Federation of Neurosciences, John Walton, declared in a special report that Ayurveda was a system without any scientific basis. In fact, this Committee, in the value of complementary and alternative medicine theories, ranked Ayurveda lower than even hypnosis or crystal therapy. It took official outrage from the UPA Government at that time, and presentations from a high-level delegation of Indian experts before that Committee, before the latter was forced to see the benefits of Ayurvedic treatment. We even had Defence experts from the Siachen experience, going and saying that the Ayurveda was the most effective treatment for high-altitude sickness.

So, these are the kinds of things we need to do to be able to document effectively. In the absence of credible documentation, case-studies on the proven benefits of the treatment of Ayurveda in specific cases, all it will take is one article, one paper for the international community to dismiss Ayurveda as a voodoo science; something all of us here will agree, it is not. Therefore,

documentation must comply with international standards for reporting and evidence based research, and that is very important when we decide what we are going to do in this Bill and beyond, on strengthening Ayurvedic treatment in our country.

But serious documentation is only one side of the coin. The other important aspect that we do not adequately deliberate over is that legal security and safeguards are not provided adequately to Ayurveda, and indeed, to all forms of traditional knowledge in our country.

आप आयुर्वेदिक तेल के साथ मालिश करते हैं। मेरा गला मुझे तकलीफ दे रहा है। अगर आपका गला खराब है तो शायद आप हल्दी और काली मिर्च दूध में उबाल कर पिएंगे। खांसी के लिए मुलैठी या पेट खराब है तो पुदिना का उपयोग करेंगे। So, you are relying on India's traditional knowledge. That is the ancient wisdom handed down over the centuries if not millennia. हम ने अपनी मां से सीखा है, and of course, it protects us against common and even uncommon ailments.

So, we have much to offer the world through our traditional and diverse resources of knowledge.

We lack a comprehensive system to safeguard those who have, over the generations, protected and honed these resources and this is putting us as disadvantaged in the globalised world. In fact, many of our indigenous communities rely on traditional knowledge for their livelihood and their identity; its misappropriation can prejudice their interests and rights. Ayurveda, for instance, caters to nearly 65 per cent or 70 per cent of our population in rural

India but nothing has been done to safeguard its practitioners and their store of knowledge. In an age when biopiracy is a very real threat, the safety of our traditional knowledge is not something we can defer but it has been ignored in your Bill, Mr. Minister.

Contemporary scientific and technological advancements, when married to tradition, promise great economic potential. That is why, other countries are trying to acquire exclusive privileges in the form of intellectual property rights over India's traditional knowledge by those with very vague connections to our knowledge. Seeing common Indian herbs patented in America gave us all a major wake-up call a few years ago.

So, the intellectual property regime seeks to protect researchers and innovators but it may do the opposite by privileging those who come up with creative new ways of copyrighting traditional knowledge and exploiting the discoveries of the ancients. At its very core, the concept of intellectual property cannot be applied to traditional knowledge because no single person can claim as their property something that is perennial, evolving and in its very nature almost amorphous.

As one of the world's oldest civilisations with a wealth of accumulated traditional resources, it is our responsibility to do what is necessary to maintain the integrity of our cultural inheritance. And if we do not take steps now, misappropriation by others may well lead us to belated, collective regret.

That is why, Mr. Minister, a few years back, I introduced in Parliament, a Private Member's Bill for the protection of Indian traditional knowledge which provided custodianship of all traditional knowledge to either the State or the Central Government, with such custodianship transferred to the practitioners who could show their practices as distinct and exclusive. They were also empowered to market their traditional knowledge as they deem appropriate, ensuring that any commercial value in it would benefit the traditional indigenous people of our country.

By design, my Bill was intended to protect us from foreign appropriation and would have provided an opportunity for Indians to learn more about culture and practices through a legally protected system. Non-custodians could work with the original communities and communities who preserved it. You know, Sir, we have the Traditional Knowledge Digital Library, a data-base containing 34 million pages of formatted information on some 2,26,000 medicinal formulations in multiple Indian languages. This is a major step in this direction. It has helped codify and classify our traditional knowledge so that others cannot grant flawed patents under their system. Unfortunately, my Bill was not adopted by the Government and it eventually lapsed. I do hope, Sir, that the Minister will reconsider incorporating it in his holistic approach on Ayurveda, a need for a traditional knowledge protection Bill in our country. We cannot overlook that while we are discussing Ayurveda.

Sir, I want to make one more point before I turn to the specifics of this Bill. In the globalising world, it seems that there is a controversy about Ayurveda. Many disruptive market forces have come in. There is a clash between the purists and the new-age practitioners of what I once termed 'Ayurveda Lite'. Now, what does that mean? There is no argument about the increasing popularity of Ayurveda. Clinics claiming to offer ayurvedic treatment are sprouting like herbs in places as far afield as London and the Italian Dolomites, and 'ayurvedic tourism' is already a significant money-earner for our national exchequer. We had a debate on tourism the other day, Sir, and Ayurveda remains a major feature of it. We, in Kerala, have been advertising our ayurvedic spas. Many five-state hotels in Kerala, which, a few years ago, would have looked down at anything so *desi*, have, actually, cashed on the rage. But, what are they selling? Tourist brochures often show a winsome blonde being massaged by a lady in a traditional red-bordered white Kerala sari, with jasmine in her hair and a brass lamp at her side. This is effectively packaged exotica. It is not Ayurveda as a remedy for disease, but rather as an upmarket beauty treatment, a relaxation cure for the jaded. A 5000-year old science has become the diversion of choice of the era of the 15-second soundbite.

The purists have been questioning and saying that this not an authentic Ayurveda, Ayurveda is a total system of medicine, meant to treat the body and

mind as a whole and cannot be reduced to merely superficial treatment. They reject this 'Ayurveda Lite' as an abomination.

They are compelled towards the principles that originally inspire Ayurveda. Of course, professional Ayurveda has also rejected the Ayurvedic cosmetics industry and so on. You can argue that it is a good argument for creating strong teaching, training and research in Ayurveda. But let me also offer a slightly devil's advocate position. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, your party is having two more Members. You have exhausted 14 minutes. The time allotted is 18 minutes for the entire party. Two more Members will speak from your Party. Mr. Shashi Tharoor, you have to decide as to how many Members will speak in this Bill.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I will summarize the entire argument to say that as the tourists came, we should be prepared to compromise and we should be flexible in our approach in generating awareness of Ayurveda. We have been discovering that investment in R&D is not enough. It is a fundamental driver on the deliberations of the future of Ayurveda and this Bill comes up short. As a Member of Parliament from Thiruvananthapuram, I have continuously pushed the present Government to establish a National Institute of Medicinal Plants in the city so that we can establish my city's and my State's traditional expertise on the subject, make the Capital city the focal point of cutting-edge research and development in this field and sadly, despite repeated attempts, this proposal has found no takers with the Central Government.

Similarly, National Ayurveda University has failed to fructify. Both could have taken us very far in developing our knowledge and expertise in Ayurveda but there is a dissonance between the Government's purported claim to promote Ayurveda and the reality of its actions. This apathy would extend to other aspects of Ayurvedic education and training. Some of you will recall a report that . …(*Interruptions*)

Between 2016 and 2018, the Ayush Ministry allowed 138 under-staffed and ill-equipped colleges to teach courses in Ayurveda Science and Surgery both at post-graduate and at under-graduate level. This was in contravention of the recommendations of the Central Council of Indian Medicine which had previously inspected these colleges and found them unsuitable to train future practitioners of Ayurveda and that does not augur well. So, I urge the Ministry that we should avoid such self-made disasters.

I also want to point out one more thing. The Bill fails to secure the larger objective of promoting Ayurveda. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please wind up your speech.

…(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : I am just giving 3-4 objections to the Bill. I was told that I can speak for half an hour. You are suddenly telling after 13 minutes to cut down.

HON. CHAIRPERSON : In the Business Advisory Committee meeting, your party leader must have told you that the time allotted to the Congress Party is 17 minutes only.

DR. SHASHI THAROOR : I did not hear that Sir.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

DR. SHASHI THAROOR: Anyway, give me three minutes to quickly summarise.

The Statement of Objects and Reasons of the Bill state that the conferment of the title of Institute of National Importance will be enough to attain self-sufficiency. But how can the Government expect to cater to the demands of our country's 1.3 billion population and fill all the lacunae in our present system by the upgradation of one university? You cannot promote the quality in excellence in education, research and training which is the objective of the Bill by awarding Institute of National Importance to one institution. This results in the failure to establish a nexus between the classification made and the object sought to be achieved by the Bill.

Unfortunately, one of the first ever ayurvedic colleges in the country – the Government Ayurveda College in Thiruvananthapuram was set up in 1889 – a pioneer in this has been ignored, even though it is much older than the Gujarat Ayurveda University. The fact is that it has not even been upgraded to

university, much less being considered for the Institute of National Importance status.

I think there is an amendment coming from my hon. friend Mr. N.K. Premachandran. I would support that. But given the long history of Ayurveda in Kerala which I am sure my other colleagues will repeat, so I would not say it, there have been many arguments for taking the glorious traditions of Kerala Ayurveda into account in deciding what should be an Institute of National Importance.

Sir, the Minister came to my Constituency in 2018 to inaugurate the new wing of an Ayurveda building and he gave a public assurance on this question to upgrade the Ayurveda college in Thiruvanathapuram to a research university and later in Question Hour, in 29th November, 2019, I reminded the Minister and he graciously re-assured us in the House that the Ministry is committed to considering this proposal.

15.00 hrs

But it still remains unfulfilled and I look forward to hearing from the Minister on this. The selective conferment of Institute of National Importance status is an issue that is even beyond this Bill. No one has defined what is an Institute of National Importance. We are talking about strengthening Ayurveda by elevating this particular institution in Jamnagar. But, on what basis, is it considered as national importance? Is there arbitrariness in doing this? Where

is the equality with the other institutions of Ayurveda in this country as provided for in the Constitution?

The Standing Committee on Human Resource Development had once said that there should be parameters to evaluate the institutions. That has not been done. Is it merely because initials of the university are GAU? यह गाउ विश्वविद्यालय हो गया, इसलिए इसको इंस्टीट्यूशन of importance कर दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR : I will just wrap up. Just to finish, I want to conclude by saying I am a cautious optimist. I do believe the future is bright for Ayurveda. I have many other things to speak on the flaws of this Bill.

HON. CHAIRPERSON: Your Party Members would not get chance. If you are taking more time, your Member will be dropped.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, we spent half-an-hour on the Matters under Rule 377.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR : I, therefore, request that what is being done for Gujarat also be done for Kerala. We have a similar national university for training and research on Ayurveda set up in Thiruvananthapuram and let that be conferred as an Institute of National Importance so that this concept has some meaning. The standards are maintained. Training and teaching are properly done. Research and documentation can be archived across the

country so that the credibility of Ayurveda around the world is protected. Thank you.

15.02 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

श्रीमती पूनमबेन माडम (जामनगर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया है। इस विधेयक को लाने के लिए मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे माननीय आयुष मंत्री जी का अभिनन्दन एवं आभार व्यक्त करती हूं। The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020, व्यक्तिगत तौर पर मेरे और मेरे क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि यह संस्था मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है। इस संस्था के माध्यम से भारत की पहचान समग्र विश्व में मजबूती से पहुंचती है। इस संस्था से बहुत से आयुर्वेदाचार्य इस देश को मिले हैं और उन्होंने हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जब यह विधेयक पेश हो रहा था और अभी भी मेरे लर्नेड सीनियर कलीग थरूर जी ने बहुत सारी बातें की कि केवल एक इंस्टीट्यूट को इतना महत्व क्यों? मैं बताना चाहती हूं कि यह बिल किसी एक शहर के लिए नहीं, किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव है, क्योंकि आयुर्वेद की पहचान भारत के साथ जन्म से मजबूती से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद दुनिया में स्वास्थ्य देखभाल की सबसे पुरानी प्रणाली के रूप में माना जाता है। आयुर्वेद एक समग्र दृष्टिकोण है, जो प्रकृति के अंदर निहित सिद्धांतों का उपयोग करता है। वह व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रखकर स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। मुख्य शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रन्थ देवताओं से ऋषियों और फिर मानव चिकित्सकों तथा चिकित्सा के संचरण के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि भगवान धन्वंतरि ने स्वयं वाराणसी में राजा के रूप में अवतार लेकर सुश्रुत सहित चिकित्सकों के एक समूह

को चिकित्सा पद्धति का ज्ञान दिया था। संस्कृत में आयुष का अर्थ है- जीवन और वेद का अर्थ विज्ञान और ज्ञान है।

यह प्रत्येक भारतीय के लिए आज गर्व की बात है कि स्वास्थ्य सेवा की इस सबसे प्राचीन पद्धति का उद्भव भारत में हुआ था। साथ ही साथ आज के समय में भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबके लिए दुख का विषय है कि कहीं समय के साथ हम इस प्राचीन पद्धति से दूर होते जा रहे थे। शायद यही कारण है कि आज की पीढ़ी ने ऐसी बहुत सारी बीमारियां देखी हैं, जो हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में नहीं देखीं। जब से हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश का दायित्व संभाला, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमारी प्राचीन प्रथाओं और विरासत को उचित सम्मान दिया जाएगा। हमारी प्राचीन चिकित्सा की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए ही माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन किया गया और उनके प्रयत्नों से ही आज विश्व भर में योग को एक अलग पहचान मिली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस विधेयक के माध्यम से हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, चूंकि मैं जामनगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, जहां यह विश्वविद्यालय है। मैं इस संस्था के इतिहास के बारे में यहां थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूंगी। यहां बात हुई कि यह संस्था, केरल की संस्था जितनी पुरानी नहीं है, पर मैं बहुत गर्व से यह कह सकती हूं कि इस संस्था में जो कन्सेंसस यहां पर मेरे साथी ने दिए हैं, वे काफी हद तक सही हैं। डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर चिकित्सा की जो प्रणाली है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के प्रयत्न इस संस्था के द्वारा हुए हैं। इस महान संस्था की नींव वर्ष 1952 में रखी गई थी। जामनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडेजेनिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के रूप में इस संस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद 20 जुलाई, 1956 में आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पोस्ट ग्रैज्युएट केंद्र की स्थापना की गई। वर्ष 1965 में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत गुजरात आयुर्वेद

विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद संस्था को गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को लीज पर दिया गया था। इस संस्थान को इसी शर्त के साथ स्थापित किया गया था कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आयुर्वेद में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 50 फीसदी सीटें भरकर संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का बनाए रखेगा। संस्थान और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के मध्य हुए समझौते में संस्थान को भारत सरकार के अधीन वापस लिये जाने का प्रावधान भी किया गया था। संस्थान को पट्टे पर देने के बाद भी केंद्र सरकार ने संस्था के कामकाज के लिए 100 फीसदी वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा था। इस संस्थान को आयुर्वेद के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाने के लिए चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। संस्थान को डब्ल्यूएचओ द्वारा पारम्परिक चिकित्सा के लिए एक सहयोग केंद्र के रूप में भी नामित किया गया है।

यह संस्थान आयुर्वेद, आयुर्वेदिक फार्मेसी और औषधीय पौधों में पीजी और पीएचडी स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय से जुड़े सभी संस्थानों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज परीक्षाएं आयोजित करने के साथ-साथ कैम्पस में स्थित संस्थाओं और कॉलेजों के मेनेजमेंट की भी जिम्मेदारी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की है। At present, this Institute is having 10 Departments offering post-graduate degrees and Ph.D. courses with 13 specialities, six well established labs to conduct research in Ayurveda and a 200-bed hospital.

The Institute has many significant achievements to its credit. I think, this is why it is being granted this status. In 65 years of its existence, it has signed over 30 MoUs at national and international level. This is the first Institute to start pharma-co-vigilance system in Ayurveda, Siddha and Unani drugs. Our

Institute in Jamnagar had started this even before the same was started by allopathic system of medicine.

The Institute has developed many treatment protocols and many treatment guidelines for various diseases. It has published many journals and many papers. International students on international cooperation schemes are supported by the Government of India, and other foreign students also come and study here and they provide for their education themselves. A lot of alumni of this Institute have achieved great heights in the field of Ayurveda, with many of them heading research centres, pharmacies and manufacturing units. उसी संस्थान से निकले हुए बहुत सारे पूर्व छात्र अभी इस सदन में भी उपस्थित हैं।

Sir, the Bill, which has been put before the House, provides for detaching the cluster of Ayurveda institutes from Gujarat Ayurveda University Campus, Jamnagar - Institute for Post-Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Shri Gulabkunwerba Ayurveda Mahavidyala and Institute of Ayurveda Pharmaceutical Sciences, including the Pharmacy Unit.

This Bill also seeks to form one institute, namely, the Institute of Training and Research in Ayurveda. More importantly, it gives this conglomerate the status of institution of national importance. In addition, it is also proposed to subsume the Maharishi Pantanjali Institute for Yoga and Naturopathy Education and Research into the Department of Swasthvritta which is a multi-disciplinary department with focus on personalised preventive and promotive health care.

I am sure that the concerns expressed by my learned colleague would be addressed a great deal. I think, the status is being granted to it to ensure that Ayurveda gets more teeth officially, more power officially and the Centre directly overlooks the progress of this particular institute. सर, प्रत्येक व्यक्ति जो इन तीन संस्थाओं में कार्यरत है, वह प्रस्तावित संस्थाओं के कर्मचारी बन जाएंगे और एक ही कार्यकाल में, एक ही नियम और शर्तों के तहत कार्य करेंगे।

महोदय, हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में वैकल्पिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकताओं की दिशा में जागरूकता आ रही है। सीआईआई-पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में 77 प्रतिशत भारतीय परिवारों ने आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल किया और आज इनकी संख्या और अधिक बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद का वैश्विक बाजार भी आज हम सब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। वैश्विक आयुर्वेदिक बाजार का आकार वर्ष 2015 में लगभग 3.4 बिलियन डॉलर्स से वर्ष 2022 में 9.7 बिलियन डॉलर्स तक होने की उम्मीद है।

महोदय, पहले लोग इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे। Earlier, people used to come to India only for medical treatment. Now, they are focussing on Ayurveda and wellness treatment. Hence, the industry is now shifting from medical tourism to wellness tourism. With the increasing awareness and prevalence of lifestyle diseases, this traditional system of medicine has become immensely popular.

Thus, Ayurveda is not only for treating the diseases, though, of course, if diseases come then Ayurveda tells how to remove those diseases, but Ayurveda is mainly for living a healthy and purposeful life in which the four objectives *Dharma, Artha, Kama and Moksha* are accomplished.

The elevation of the proposed Institute to the status of Institution of National Importance will be a major leap forward for our ancient alternate medical practice.

The Bill seeks to achieve multi-fold objectives. It will provide autonomy to the Institute. It will help develop patterns of teaching in under-graduate and post-graduate medical education in both, Ayurveda and pharmacy. This status will give it the mandate to frame its own certification courses as per national and international requirements for deeper penetration of AYUSH. It will also bring together in one place educational facilities of the highest order for the training of personnel in all important branches of Ayurveda, including pharmacy.

It will also help to attain self-sufficiency in post-graduate education to meet the country's needs for specialists and medical teachers in Ayurveda. It will propel in-depth studies and research in the field of Ayurveda. It will give an enhanced status to the growing role of AYUSH systems in addressing public health challenges in India. It will reduce Government's expenditure on health as Ayurveda is cost-effective because of its preventive and curative approaches.

Finally, it would be a launching platform for many a young minds, into the demand of the wellness industry, that is growing by leaps and bounds.

So, in the end, I whole-heartedly welcome and support this Bill and thank our hon. Prime Minister for giving the much-needed impetus to our rich heritage and reviving our ancient medical practices.

In conclusion, I would like to quote Vagbhatacharya ji. He says:

"आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुखसाधनम्।
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः॥"

It means, "One who seeks life for the fulfilment of , the four objectives of life, *Dharma, Artha, Kama and Moksha*, should extremely respect and abide by the norms of Ayurveda".

Ayurveda is the path to fulfil the dream of Swami Vivekananda, of Bharat guiding the world into spirituality and holistic wellness.

I whole-heartedly support the Bill. I once again thank the hon. Prime Minister, our AYUSH Minister for giving Jamnagar University this special status. I am sure it is going to connect the world and move ahead and get Ayurveda an official recognition at the international platform. Thank you.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Ayurveda, as we all know, is very rich traditional form of medicine which has its roots in India. I would like to quote the famous Saint, if not the greatest of all Sages, from Tamil Nadu, Thiruvalluvar.

He said:

> "Noy Nadi Noy Mudhal Nadi Adhu Thanikkum
> Vay Nadi Vayppa Cheyal"

This means, for a doctor, fist you have to identify what the disease is. Then you have to find out the cause of the disease. Then you have to identify the treatment of the disease and give correct treatment to the patients. So, this has been said even 2000 years back. That was the time when Ayurveda system was prevalent all over the country.

Sir, Ayurveda literally translates to life science. It is not about medicine; it is all about teaching you about how you conduct your life so that you can lead a healthy life. Apart from that, the medical and surgical techniques were used even 2000 years back. Even the modern forms of medicine had evolved.

Being one of the oldest forms of medical practices with great medical and surgical knowledge, they have a saying in our place from where I come. They say:

"Aayiram Perai Konna Arai Vaidyan"

It means, if you kill thousand patients, you are half a doctor. But this is actually a misnomer because a lot of people do not understand the exact context in which it is said. It actually means,

"Aayiram Verkalai Kondral Arai Vaidyan"

Which means, if you kill thousand roots, then you will become half a doctor. This goes to exemplify the essence of the medicinal use of herbs and roots in the olden days. Thousands of roots are being studied by the doctors where they have to analyse what roots are useful and we have learnt these things from nature.

One of the greatest examples is, for snake poison, the treatment was identified by following a Mongoose. When a snake bites it, the Mongoose goes and rolls itself in some leaves and gets cured of that poison. So, this is the basis on which the treatment for snake bites was identified. Similarly, we have learnt a lot from nature. This has evolved over several thousands of years and thus Ayurveda has come into existence.

A lot of people are under the impression that Ayurveda deals with only medicine. But one of the oldest surgeons, belonges to our country, Sushruta, who has written a book called, Sushruta Samhita which is available even now where he explains in great detail about the different surgeries that can be done. The common surgery used to be the Rhino surgery. A lot of people might be wondering why Rhinoplasty surgery was so popular even 2000 years back. Date back to our culture, whenever you had somebody who misbehaved

and the people wanted to punish him, they used to chop off his nose. So, this was a form of punishment which was there. If you see the Ramayana, even Shrpanakha had the same fate, her nose was cut off. As there were so many people without noses, Sushruta devised a procedure.

Even today, in plastic surgery, it is described as an Indian Rhinoplasty Flap, Indian Nose Flap. This is very popular and Sushruta is considered as one of the founding fathers of Plastic Surgery.

To that extent, surgical expertise of India has grown. Apart from Rhinoplasty, they were also well versed with the art of treating Urinary stones, where they used to do surgeries to remove the stones. They also used to treat cataract. It results in blindness. They were able to treat that. They were also well versed with the art of suturing the wounds. In fact, there is a story. I do not know whether it is true or not. They say that they used to allow large ants to bite the edges of the cut wounds and they used to chop off the heads so that they stay in place and this was used to be the most primitive form of suturing of wounds which was done in those days.

Ayurveda does not concentrate only on giving medicines and surgeries. It also talks about prevention in the form of Yoga, meditation, nutritional science and massages. But as these do not have any medicinal value, probably these should be kept separately as preventive medical systems and they should be working on that.

I would like to concur with our hon. Member from Congress. He has mentioned that by giving one particular institute, we are not doing any great service to this science. I am aware that the Ministry of Ayurveda exists there. I believe that, just like you have the Medical Council of India, there should be a Council to be established which monitors the functioning of the practitioners all over the country where they should be able to have some reports, if some quackery or some other issues are happening there and appropriate action should be taken.

Similarly, they should have journals, more number of journals talking about the right medicines which are available and the new research which is being done.

All these things should be incorporated in this form of medicine. Though I am a plastic surgeon, I understand the value of Ayurveda and I have great respect for all forms of medicines. I think that whichever form of medicine is going to be useful for society should be encouraged, and we should patronise those medicines for our system.

There is another thing that they talk about in Ayurveda. It is not just that the medicines come in bottles. A lot of the English medicines that we are consuming today have come from some roots and herbs that were used in India and it was taken away by the western world, repackaged and sent in capsules and bottles back to us. Further, I believe that for the preparation of these medicines there are some texts that describe about what kind of utensils

should be used; what kind of fire wood should be used to light up fire so that the temperature can be maintained at a particular degree Celsius; and what should be the distance between the fire wood and the utensils in which the medicine has to be prepared. So, they had gone into such great detail to describe how the medicines should be prepared also. This shows how advanced our system of medicines was about 2,000 years back when probably most of the western world was walking on four feet rather than two.

I would like to say that the Government should provide adequate funds for this particular department to encourage more research. I am sure that we could know more about medicines and gain more knowledge if we take out the past texts, translate them and get the wealth of secrets, which are hidden in those texts. Thank you very much, Sir.

HON. CHAIRPERSON : Of-late, *Colgate* is talking about *Ved-Shakti*.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir. I rise to speak on the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020.

Ayurveda is the world's most ancient system of natural healthcare, and it enjoyed unquestioned patronage in the past. The world today recognises Ayurveda as a science of healthcare while Allopathic medicine tends to focus on the management of disease. Ayurveda provides us with the knowledge of how to prevent disease and how to eliminate its root cause if it does occur.

The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill seeks to confer the status of an institution of national importance to a cluster of Ayurvedic institutions in Gujarat -- Ayurveda University Campus in Jamnagar. The three institutes, which would be clubbed are the Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar; Shree Gulabkunverba Ayurved Mahavidyalaya, Jamnagar; and the Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, Jamnagar.

Once again, it will be established in the favoured State of the Ruling Party, that is, Gujarat. There are so many Ayurvedic institutions across the country, especially, the J. B. Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital in West Bengal, which is one of the most prestigious institutions in the country besides the Universities in Chandigarh, Bengaluru, Banaras and the famous Kottakkal Vaidyashala in Kerala, which has branches across the country.

I would like to know from the hon. Minister, through you. What is the reason behind such arbitrary selection of institutes for granting INI? What parameters were taken into account for selection of these institutes? The institute that secures first rank in the field of Ayurvedic studies has also been ignored.

The aim of the proposed Bill is to empower the institute into becoming the most important Centre in its field. Why is such a step being taken,

especially, in the State of Gujarat and not in other places where better institutes of Ayurveda exist?

Now, coming to the other features of the Bill, firstly Section 5 (d) states that : “The privilege to be enjoyed by the employees of the institute will remain unchanged”. The Government must see to it that in case any difference exists amongst the three institutes, then they must be done away with and there must be a parity of privileges in the proposed institution.

Section 6(1)(k) states that there will be three Members of Parliament of whom two shall be elected from amongst themselves by the Members of the House of People. I would like to request the hon. Minister, through you, Sir, that Government must make sure that one should compulsorily be from the Opposition party.

Section 7(1) states that the term of office of the elected or nominated Member will be five years but it is not clear whether he or she stands eligible for re-election or not. So, I would request the Minister that it must be mentioned in the Bill in order to prevent any sort of confusion in the future.

Section 8(1) of the Bill states that there will be a President of the Institute who will be nominated by the Central Government from amongst the members of the Institute. Instead of nomination by the President, provision must be made for election of the President by the members of the Institution. This will enhance and promote democratic ideals within the Institute. More so because

he or she will lead the executive wing of the Institute and this must be an elected post and not a nominated one.

Section 15 talks about the financial matters of the proposed institution but there is no mention of regulation of fess that can be charged by the same. It is evident that medical education in India is very expensive and unaffordable for a huge population. Thus, it deprives eligible candidates from becoming a part of the field. Thus, keeping this in mind, the Government must formulate a policy to regulate the fee structure of medical education, not only of this Ayurveda Institute but all other medical colleges charging exorbitant fees.

Section 25 reflects the overpowering and controlling nature of the present Government. Thus, the ruling party, in case of any differences, the decision of the Central Government would be final. The Governing Body of the Institute having people holding high posts and great knowledge who would always work for the development of the institution. The Government must keep this in mind instead of stating that their decision would be final. As the party does not give heed to the amendments proposed by the Opposition parties, similarly it would not give importance to the institutions.

All the Members of the House are representatives of the people of India. We might be from the Opposition parties but form a part of the legislative process, and our right to contribute to law making is not being allowed to be exercised in the way it should be. The House has become a debating ground

where the final say is of the ruling party, and it is arbitrarily taken for granted that the Opposition has nothing to contribute.

I would like to conclude by saying that in order to give Ayurveda the status it deserves, intensive documentation of the currently available ayurvedic treatments practised in different regions in the country and their standardization is more important than the standardisation of drugs. The former would contribute to consolidation of ayurvedic clinical experience and improvement of expertise of the ayurvedic professional and the latter will help the pharmaceutical industry more. This must be mentioned in the Bill in order to ensure that such process is followed strictly.

I would like to request the hon. Minister to look into the grave matter under which fake medicines are being sold under the name of Patanjali and other brands endorsing Ayurveda. Serious steps must be taken against such industries which are playing with the health of people.

Even to this date, there are numerous herbs and plants that are used by the tribal population of India and are known to us. The Government must set up a national expedition to find out these herbs that can play an important role in curing severe diseases given the current scenario of novel virus posing threat to the entire globe. India having eight per cent of biodiversity is capable of contributing in finding out beneficial herbs.

Finally, I would like to bring to the notice of the House that there are two greatly valuable and informative forms of literature on Ayurveda. Firstly,

Chiranjeevi Banaushodhi by Shibkali Bhattacharya; and secondly, the famous film named *Arogya Niketan* based on the novel by Tarasankar Bandyopadhya.

Both are the great sources of information on Ayurvedic discipline. I would urge the hon. Members to read the book and watch the movie to realise its value and importance. I would like to request the hon. Minister that the Books, namely, Dhanvantari, Charaka, Sushruta and Chiranjib Banausadhi by Shibkali Bhattacharya should be translated in all the languages of the country in order to make Ayurveda more developed. With these words, I support the Bill on behalf of my Party and I hope the hon. Minister would consider my points that I have raised here.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, I appreciate the efforts of the hon. Minister, Shri Shripad Yesso Naik, to take up this Bill, which is the brainchild of our hon. Prime Minister, to take Ayurveda forward to reach the entire boundaries of the world. No doubt Ayurveda has reached the boundaries of the world already and in the world, it is being practised in a much better way than us. In Nepal, I wish to say, 80 per cent of the people are using only Ayurvedic medicines and in Sri Lanka also. Though it was started in India, yet it is a growing market in India.

Ayurveda is nothing but the 'Science of Life' and 'Longevity' which was initially invented by Dhanvantari and we all celebrate Dhanvantari's Birthday as Ayurveda Day which comes two days before Diwali. I would request the hon. Minister and all the hon. Members to name it Dhanvantari Institute of Teaching and Research as he was the pioneer of Ayurveda. Let us respect the inventor of this science, the Lord of the Science.

We wholeheartedly welcome the Institute that is coming up in Jamnagar, Gujarat, but as many of our friends are aware that Kerala is the main centre for Ayurveda, we should also have four other centres across India. One should be in Kerala for South India and likewise, let there be four centres of excellence in different regions. The science developed by Dhanvantari has been propagated through Sushruta and Charaka. We have great *Granthas* –Charaka Samhita and Sushruta Samhita. Maybe, the regional institutes can be named after Charaka and Sushruta. We all talk of Tirukkural for good teachings and like

that in medicine, there are so many *Shlokas* in Charaka Samhita and Sushruta Samhita. We should have these reserved institutes take up all the *Shlokas,* understand the meaning and make the research so as to pass it on to the next generations.

With regards to Ayurveda, I would like to talk about one of my real life experiences. My grandmother had cancer and we took her to Sloan Kettering, USA. The famous doctor there said, if she suffers pain after surgery, she will live for one year. Otherwise, there are only six months. We came back. Then we decided to go for Ayurveda treatment. Fortunately, Ayurveda treatment coupled with meditation helped her; she is now 94 years old and she is still strong. So, this is my real life experience of how Ayurveda has worked in my own family. I want this course to penetrate in the society. We have to serve generations and generations with this particular great science of Ayurveda.

Sir, we have two Ayurveda institutes in Andhra Pradesh, one in Vijayawada and another in Tirupati. I request that reasonable grants be sanctioned to them.

Sir, in my Parliamentary Constituency, I have come up with the idea of starting a centre in each municipality for yoga and meditation in an area of 7,000 square feet to 8,000 square feet. These centres cater to yoga and meditation requirements of the people. I now request, through this august forum, the hon. Minister for AYUSH, that alongside yoga and meditation we should have an ayurvedic outlet also in such units which will benefit the users

of Ayurvedic medicine. Ayurveda offers people the most effective and the cheapest medication with least side effects. Hence, I would request the hon. Minister to support our yoga and meditation centres by providing ayurvedic component under the Ministry of AYUSH in my Constituency. Sir, this is the need of the hour. We wholeheartedly support this Bill.

Last but not least, Sir, the entire world is now adopting Namaste, which is an integral part of Indian culture, as a form of greeting each other. Our hon. Prime Minister has made a mention of this. I believe a day would come when our Ayurveda will become the medicine of choice for the whole world. Thank you so much.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, आयुर्वेद को बढ़ोतरी देने के लिए और आयुर्वेद में संशोधन करके उसको ज्यादा महत्व देने के लिए जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

महोदय, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनने वाली है। मुझे भरोसा है कि अपने पूरे भारत देश के उपयोग के लिए इस यूनिवर्सिटी से पूरा-पूरा फायदा होगा। आयुर्वेद अपनी भारतीय संस्कृति की देन है। अपनी भारतीय संस्कृति में चार वेद हैं- ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें अथर्ववेद अत्यंत ही महत्वपूर्ण वेद है। आयुर्वेद में सिर्फ मानव जाति का ही नहीं, बल्कि उनके साथ-साथ पशु, पक्षी सहित सभी सजीव प्राणियों को सुखी और निरोगी जीवन प्रदान करने का काम किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हमारे सारे पूर्वजों ने, जिनमें वैद्य धन्वन्तरि के माध्यम से आयुर्वेद की पद्धति प्रचलित हुई, उसका सारा इस्तेमाल हम आज भी करते आ रहे हैं। पहले इसका प्रयोग ज्यादा होता था, बीच में एलोपैथी आने के बाद तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ी। जैसे तुरंत इलाज मिलता था, वैसे ही ज्यादा बिल भी भरना पड़ता था। एक बार फिर से सारे देश और दुनिया ने आयुर्वेद की उपचार के तरफ जाने के लिए शुरुआत की है। ऐसे वक्त में जब भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद की जो देन है, उसका महत्व बाहर के देशों में भी बढ़ रहा है। दुनिया के जो बड़े-बड़े देश हैं, वे भी आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा संशोधन भी शुरू किया है। ऐसे वक्त में भारत को भी कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने देश को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा संशोधन करना चाहिए। अच्छे अध्यापकों को भी तैयार करना चाहिए। जैसा इसके उद्देश्य में लिखा है कि देश में आयुर्वेद के विशेषज्ञों और चिकित्सा अध्यापकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस बिल की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि यह सही बात है। इसका उद्देश्य सही है और इसका विचार भी सही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, वैसे तो खास कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विचार से भारत में एक नए डिपार्टमेंट, यानी आयुष डिपार्टमेंट

की स्थापना हुई है। शुरू से ही इस मंत्रालय का काम श्री श्रीपाद येसो नाईक जी संभाल रहे हैं। वह अच्छी तरह से इस मंत्रालय का रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं और उसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं।

आयुर्वेद के लिए आवश्यक चीजें वैस्टर्न घाट में ज्यादा मात्रा में हैं। मैं सौभाग्य से गुजरात के एक रिसर्च सैंटर में तीन-चार महीने पहले एग्रीकल्चर कमेटी के साथ गया था। वैस्टर्न घाट में आयुर्वेद रिसर्च के लिए बहुत सहूलियतों का निर्माण हो चुका है। केरल को इसका महत्व ज्यादा अच्छी से मालूम हुआ और केरल ने एडवांस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया। चाहे महाराष्ट्र का वैस्टर्न घाट हो या श्रीपाद नाईक जी का गोवा हो, यहां वैस्टर्न घाट के जितने भी प्रदेश हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इनमें आयुर्वेदिक रिसर्च सैंटर तैयार करने की आवश्यकता है। कई जगह आयुष अस्पतालों का निर्माण हो चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी दो आयुष अस्पताल दिए गए हैं। मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वैस्टर्न घाट के सिंधुदुर्ग जिले में खास तौर से डोडामार्ग एरिया में आयुष की उपचार पद्धति और रिसर्च के लिए काम किया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा उपलब्धियां मिल सकती हैं। मेरा कहना है कि सिंधुदुर्ग के डोडामार्ग में आयुवेर्दिक रिसर्च सैंटर की शुरुआत करें।

जामनगर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जब यहां से ज्यादा जानकारी मिलेगी, रिसर्च का आधार मिलेगा तो इसका लाभ पूरे देश को हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सिंधुदुर्ग में आयुर्वेदिक रिसर्च सैंटर जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए मैं अपनी और अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से बधाई देता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : मैं एक छोटी सी करैक्शन कर दूं। चौथा वेद आयुर्वेद नहीं अथर्ववेद है। वह जानते हैं, बहुत बार स्लिप हो जाता है।

…(व्यवधान)

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak.

As the house is aware, Ayurveda plays an important role in our life and it reduces the cost of the treatment and helps poor patients which is cost-effective because of its preventive and curative approaches.

On behalf of TRS Party, we are welcoming the establishment of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar as an Institute of National Importance and as a premier institute. We also request the Union Government to set up more Ayurveda hospitals and research institutes in Telangana to meet the demands of the people. Some States had glorious Ayurvedic traditions in the country and Telangana is one among them. As the House is aware, research is the backbone of the development of Ayurveda and we have to concentrate and allocate more funds for research institutes.

Now, I come to the issues of Telangana. I would like to state that the Government Ayurveda Hospital in Erragadda in Hyderabad is having a total bed strength of about 100 beds and has average outpatients of 250-300 per day and 68 per cent bed occupancy, which needs more basic amenities and

funds from the Union Government. This hospital may be developed as an Institute of National Importance.

I would also like to state that the Government Ayurvedic Teaching Hospital in Warangal in Telangana is running with about 100 beds and needs to be upgraded with other requirements.

Now, I will come to my Medak parliamentary constituency. The Government Ayurveda Hospital in Toopran which falls in my Medak parliamentary constituency is having a total bed strength of nine beds with less staff and has average outpatients of 50 per day.

I request that under the National AYUSH Mission, steps may be taken to further upgrade this Ayurveda Hospital in near future to help the poor patients who are residing in the local area and who have represented to me several times.

I request the hon. Minister of AYUSH, through the Chair, to kindly intervene in the matter and do the needful. Thank you, Sir.

श्री विजय कुमार (गया): सभापति महोदय, आपने मुझे आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा देश आदिकाल से आयुर्वेद के उद्भव का देश रहा है। हमारे यहां यह पद्धति गांव-देहात, शहर सभी जगह अपनाई जाती है और इसका भरपूर लाभ मिलता है।

इस विधेयक के माध्यम से सरकार आयुर्वेद को शिक्षण और संस्थान के रूप में जामनगर गुजरात में प्रतिस्थापित करना चाहती है, जो जनहित में सकारात्मक पहल है और इससे आने वाले दिनों में लोगों को इलाज के लिए आयुर्वेद के माध्यम से सस्ती दवा मिलेगी और इस पर विशेष वैज्ञानिक शोध का अवसर प्राप्त होगा। जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा और आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान का अवसर प्राप्त होगा।

सरकार की यह सराहनीय कोशिश है कि महर्षि पतंजलि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा को और इसके अनुसंधान संस्थान को आयुर्वेद संस्थान में शामिल करके जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए।

मैं और हमारी पार्टी जनता दल (यू) इस विधेयक का समर्थन करती है और हम आशा करते हैं कि इसके उद्देश्यों से जनता को भरपूर लाभ मिलेगा। आज दुनिया भर में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी, इसकी सेवाएं और इसमें आम लोगों की रुचि बढ़ रही है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार की कोशिश सराहनीय और स्वागत योग्य है।

आज विपक्ष के कुछ माननीय सांसदों ने आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के बारे में सवाल खड़ा किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जो विकास हो रहा है, आयुर्वेद के विकास की जो बात की जा रही है, वह बहुत सराहनीय है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आयुर्वेद पर ध्यान नहीं दिया गया था। आज 'मोदी है तो मुमकिन है' और आगे काम बढ़िया होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गया में जो आयुर्वेद का कॉलेज है, उसको पुन: चालू करवाने की भरपूर कोशिश करें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए खड़ा हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। तीन आयुर्वेदिक संस्थानों का विलय करके एक नया इंस्टीट्यूट बनाने के लिए यह बिल आया है। ये जो तीन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें the Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, Shree Gulabkunverba Ayurved Mahavidyalaya, Jamnagar and the Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, Jamnagar, इन तीनों संस्थानों को मिलाकर नया इंस्टिट्यूट बनाने के लिए आज भारत सरकार का आयुष मंत्रालय यह बिल लाया है। यक एक अच्छा बिल है। इस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है to develop patterns of teaching in medical education in Ayurveda and pharmacy, आयुर्वेद और फार्मेसी शिक्षण पैटर्न को कैसे विकसित करना है। इसका एक और उद्देश्य है to bring together educational facilities for training of personnel in all branches of Ayurveda, to attain self-sufficiency in postgraduate education to meet the need for specialists and medical teachers in Ayurveda, and make an in-depth study and research in the field of Ayurveda.

आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं बिल में देख रहा हूं कि कंपोजिशन ऑफ इंस्टिट्यूट में 15 मैम्बर्स की कमेटी होगी, जिसमें मिनिस्टर ऑफ आयुष भी रहेंगे। आयुर्वेद विभाग के सैक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हैड और हैल्थ डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी सहित 15 मैम्बर्स की कमेटी बनेगी। गुजरात के जामनगर में एक इंस्टिट्यूट खोला जा रहा है। केरल और तमिलनाडू राज्य आयुर्वेद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओडिशा के सी.एम. का भी आयुर्वेद के ऊपर ज्यादा ध्यान है। ब्रह्मपुर में डॉ. अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल है, उसको आयुष डिपार्टमेंट मदद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ओडिशा में एजुकेशन और रिसर्च के

ऊपर आयुष डिपार्टमेंट ध्यान दे। आज जो बिल आया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से धन्यवाद देता हूं।

श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती): माननीय सभापति जी, आपने मुझे आयुर्वेद शिक्षण संस्थान विधेयक, 2020 के महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, भारत में जन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में आई तेजी से और इसमें बढ़ती हुई भूमिकाओं को देखते हुए, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना चाहिए। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में आयुर्वेद की भूमिका को बढ़ाने में और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य की मद पर भारत सरकार का खर्च घटेगा, क्योंकि रोग निवारक दृष्टिकोण से आयुर्वेद किफायती होता है।

सभापति महोदय, दुनिया भर में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी और सेवाओं के साथ-साथ इसमें लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। भारत आयुर्वेद की जननी है। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आयुर्वेद के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण के उन्नत स्थान के लिए भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रही है। सभापति महोदय, प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने से इसे आयुर्वेद शिक्षण संस्थान का स्तर बढ़ाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करने और उन्नत मूल्यांकन कार्यपद्धति को अपनाने में स्वायत्ता नहीं मिल सकेगी और इससे लोगों में आयुष की गहरी पैठ बनाने और अपना प्रमाणन पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार मिल जाएगा तथा जन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी।

15.58 hrs (Shrimati Ram Devi *in the Chair)*

सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जो नेपाल के बार्डर से सटा हुआ है, यहां पर वन औषधियों की बहुतायत में उपलब्धता है। इन परिस्थितियों में मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषध रिसर्च सेन्टर खोलने, आयुर्वेद शिक्षण संस्थान व रिसर्च सेन्टर तथा दवा उत्पादन सेन्टर का निर्माण करने पर विचार करें तो बहुत सराहनीय कार्य होगा। इसी के साथ-साथ सरकार से आग्रह है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सहित आयुर्वेद के कितने संस्थान संचालित हैं, उनकी सूची भी

उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दवाओं और डॉक्टर्स की उपलब्धता के साथ-साथ आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार के लिए भी सरकार उचित व्यवस्था करे।

16.00 hrs

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): धन्यवाद, मैडम। मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल, 2020 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

मैडम, मैंने अपने छोटे से जीवन में मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, वह मुझे आयुर्वेद ने सिखाया है। मुझे आयुर्वेद की जो थोड़ा-बहुत नॉलेज है, वह मुझे श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेदिक महाविद्यालय से मिली है, जिसके बारे में आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदक होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है और मेरी बहुत तीव्र इच्छा भी थी कि आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार, उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक जी के प्रति आभारी हूं कि आजादी के बाद पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जो हमारी पौराणिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके लिए आयुष डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया और उसमें बहुत बड़ा फण्ड भी दिया गया। जो हमारी आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, वे उनका बहुत प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ही आज हम यह बिल लेकर आए हैं। मैं जहां पढ़ी हुई हूं, मैं जिस वजह से यहां खड़ी हूं, वे संस्थाएं गुजरात आयुर्वेद युनिविर्सिटी और गुलाबकुंवरबा आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं, जिनकी चर्चा आज हम यहां पर कर रहे हैं।

मैडम, आयुर्वेद केवल कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, वह चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ जीवन जीने का विज्ञान है। इसीलिए हम किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद मात्र शारीरिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसमें शरीर के साथ-साथ मन और आत्मा के लिए भी बात की गई है। हमने जिसके लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, व्यक्ति के जो

चार पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में गिनाए गए हैं – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके लिए भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है- "आयु: कामायमानेन धर्मार्थ सुख साधनं, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय: परमादर:। "

इसका मतलब यह है कि जो हमारे चारों अर्थ दिए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए। इसमें मोक्ष तक की बात की गई है, न कि सिर्फ शरीर की। इन सभी पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान धन्वन्तरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और सिर्फ हम मानवों को ही नहीं, देवताओं को भी चिकित्सा की जरूरत पड़ती है और वहां स्वर्ग में भी अश्विनी कुमार जैसे वैद्य हुआ करते थे। ऐसी कथाएं हमारे सुनने में आती हैं। ...(व्यवधान) मैं सबसे पहले सरदार पटेल, जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह महाराज, गुलाबकुंवरबा महारानी, प्राणजीवन मेहता, विजय ठाकर, वैद्य सी.पी. शुक्ल को नमन करना चाहती हूं कि सरदार पटेल, जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह महाराज, गुलाबकुंवरबा के परामर्श से ही इस संस्था की स्थापना जामनगर में 1922 में की गई थी। वहां इन सारे वैद्यों ने आयुर्वेद को दिशा दी थी। इस संस्था के चार डिपार्टमेंट्स को जोड़कर, उसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर और श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेदिक महाविद्यालय को इसमें जोड़ा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस, जामनगर और महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट फॉर योगा, नेचुरोपैथी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जामनगर, इन चारों संस्थाओं को इसमें जोड़ा गया है।

इन चारों संस्थाओं को जोड़कर एक राष्ट्रीय संस्था बनाने जा रहे हैं। आईपीजीटी एंड आरए कोर्स 65 सालों से जाम नगर में चल रहा है, इसमें दस विभाग हैं और पीजी की 53 सीट्स, पीएचडी की 20 सीट्स हैं। इसमें अत्याधुनिक 6 लैबोरेट्रीज भी हैं और 200 बैड का अस्पताल भी है। डब्ल्यूएचओ ने इसे पारम्परिक चिकित्सा के लिए स्वीकार किया है और तीन-चार विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत इस संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

सभापति जी, इस बिल की विशेषता मंत्री जी ने और मेरे पूर्ववक्ताओं ने बता दी हैं। मैं आयुर्वेद के बारे में बोलना चाहूंगी। मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन जीने की साइंस है। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य के लिए जो वास्तविक बजट है, उसमें हम बहुत ज्यादा प्रावधान स्वास्थ्य के लिए करते हैं। यदि हम इसमें आयुर्वेद अपनाते हैं, तो हम स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में बहुत ज्यादा कमी ला सकते हैं और हमारे देश के लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है – स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं। यह पहला सूत्र आयुर्वेद का है। आयुर्वेद में सिर्फ दीर्घायु की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि सुआयु के साथ दीर्घायु की कल्पना की गई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करती हूं कि वे इतना महत्वपूर्ण बिल लाए हैं।

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर): महोदया, आयुर्वेद की संस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देने वाली बात निश्चित ही सराहनीय है, लेकिन यह जो बिल The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020 सदन के सामने आया है, इसमें कुछ कमियां देखी जा सकती हैं और कुछ सुधारों का निश्चित संभाव है। बॉय इन लार्ज देखा जाए तो The Bill seems to be a bit vague in nature. This Bill only mentions about all branches of Ayurveda. लेकिन किन सारी ब्रांचेज का इसमें अंतर्भाव किया जाने वाला है, यदि इसकी स्पष्टता हो, तो इससे लाभ होगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसमें 15 सदस्यों को रखा जाएगा, जिसमें से केवल तीन ही टेक्नीकल एक्सपर्ट्स हैं। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर सभी ब्रांचेज का इसमें अंतर्भाव होने वाला है, तो हर ब्रांच का एक टेक्नीकल एक्सपर्ट इसमें हो, तो इसकी फंक्शनिंग में काफी सुविधा होगी, क्योंकि an institute of national importance needs more technical expertise.

दूसरी बात यह है कि फंक्शनिंग प्लान और वर्किंग प्लान इस इंस्टीट्यूट का बताया गया है, it looks vague. For an institute of national importance, the working plan needs to be concrete and very clear. One of the objectives of the Bill is to make an in-depth study and research in field of Ayurveda. आज हम आयुर्वेद की बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आयुर्वेद में आज भी मार्डन रिसर्च मैथोडोलॉजी जैसे कि फेज वाइज क्लीनिकल ट्रायल्स की आज भी कमी है। काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल क्रानिक थैरेपीज में किया जाता है इसलिए आयुर्वेदिक औषधियों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अभ्यास करने की जरूरत है। आज भी हम आयुर्वेद विश्व में मानी जाने वाली चिकित्सा प्रणाली कहते हैं, लेकिन यदि हम यूएस एफडीए अप्रूवल के लिए जाते हैं या यूरोपियन मेडिसिन गाइडलाइन्स की तरफ जाते हैं, तो इसमें आयुर्वेद का उल्लेख नहीं होता है, उसमें सिर्फ हर्बल मेडिसिन का उल्लेख होता है। इसलिए आयुर्वेद विश्व स्तर पर तभी स्वीकार

होगा, जब रिसर्च में पारदर्शिता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन्स आएं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस इंस्टीट्यूट के तहत modern formulation and drug delivery system का आयुर्वेद में अंगीकार करने हेतु कुछ प्रावधान करने के बारे में सरकार क्या कुछ सोच रही है। इसी के उपलक्ष्य में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वर्गीय डाक्टर सरदनी ढाने जी के अथक प्रयास से वर्ष 1989 में मुम्बई स्थित केईएम अस्पताल और नायर अस्पताल में आयुर्वेद रिसर्च सैंटर 1989 से कार्यान्वित है।

देश के विख्यात gastroenterologist surgeon, Dr. Ravi Bapat का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यह गर्व की बात है कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स वर्किंग ऑन आयुर्वेद के चुनिंदा उदाहरणों में से ये दो उदाहरण हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो सेंटर्स को इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस के पर्व्यू में ला कर, उन सेंटर्स की ऑटोनॉमी बरकरार रखते हुए, उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके, जिससे उन्हें ट्रेन्ड आयुर्वेदिक स्टाफ मिले, टेक्निशियंस मिले और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जिससे आयुर्वेद के क्लिनिकल रिसर्च को बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हो सकता है।...(व्यवधान)

मैडम बहुत अहम् मुद्दे हैं। This Bill also loses an opportunity to include the facility of cross training of modern stream of medicine. क्या यह इंस्टिट्यूट आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी तथा एलोपैथी के डॉक्टरों को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज का प्रावधान करेगी? Here I would like to quote my teacher and an eminent gastroenterologist surgeon, Dr. Ravi Bapat. जो हमेशा कहते हैं – "बीमारी तथा रोग के खिलाफ जंग में आयुर्वेद कवच का काम करता है और एलोपैथी बंदूक का काम करता है।"

सभापति महोदया, जंग जीतने के लिए हमें दोनों की जरूरत है। इस इंस्टिट्यूट के तहत इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जिससे भारत का डॉक्टर-पेशेंट रेश्यो 1:1800 है, लेकिन

डब्ल्यू.एच.ओ. के मानकों के अनुसार वह कम से कम 1:1000 होना चाहिए, ताकि इससे लाभ हो। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सांसद, अजय भट्ट जी।

…(व्यवधान)

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर): मैडम, यह बहुत अहम् मुद्दा है। मुझे बोलने के लिए एक मिनट दीजिए मैं कन्क्लूड करता हूं। बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स एक्यूट इलनेस को ट्रीट करने के लिए विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के एलोपैथी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ कोर्सेज का प्रावधान हो तो उससे काफी लाभ हो सकता है।

अंत में, एक अहम् मुद्दा सभी लोग उठा रहे हैं, why only Gujarat? अगर देखा जाए तो Kerala and West Bengal have rich tradition. मैं why only Gujarat की बात इसलिए कर रहा हूं कि केरल और वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी ट्रेडिशन है। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेज की बात करें, तो गुजरात में सिर्फ 29 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेज हैं, जबकि महाराष्ट्र में 62 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेज हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे नेशनल इंस्टिट्यूट गुजरात के साथ-साथ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और केरल में भी बने। आयुर्वेदिक संस्था बनाने की यह सोच अभिनंदनीय है, लेकिन अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाए, तो इससे फायदा होगा। आज भारत आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ भारत इंटीग्रेटेड मेडिसिनल एप्रोच के लिए वर्ल्ड लीडर बन सकता है। इस संभावना पर भी विचार हो, ऐसी मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय सांसद, अजय भट्ट जी।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति महोदया, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं उन सभी साथियों के साथ अपने को संबद्ध करता हूं, जैसे पूनम बहन और दूसरी बहन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी-लिखी हैं, जिन्होंने अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। हम पूरी तरह से आयुर्वेद शिक्षण और संस्थान विधेयक, 2020 का समर्थन करते हैं।

मान्यवर, आयुर्वेद की जो प्रासंगिकता पहले थी, वह आज भी है और यह लगातार बढ़ती जा रही है, यह घटने वाली नहीं है। अगर आप विश्व के तीन दिनों के आंकड़ों को देखें तो कोरोना वायरस के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में हमारा देश सबसे कम प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारी जीवन-पद्धति ही ऐसी है। हमें जीने की ऐसी ही पद्धति सिखाई गई है।

मान्यवर, हमारे विजनरी प्रधान मंत्री जी ने सत्ता वर्ष 2014 में संभाली थी और सत्ता संभालने के तुरंत बाद चार महीनों के अंतर्गत आयुष के लिए अलग मंत्रालय का गठन कर दिया। उसके साथ-साथ उसके लिए बहुत अच्छा बजट भी रिलीज कर दिया। इससे पहले जो सरकारें थीं, उन्होंने बहुत ही कम बजट दिया था और आयुर्वेद को एक तरह से अलग रखा गया। अगर हम वर्ष 2000 से पहले नजर डाले, तो 200 करोड़ रुपये, फिर 300 करोड़ रुपये, इससे पहले तो और भी कम था। माननीय मोदी जी ने सत्ता में आते ही 500 करोड़ रुपये का बजट दिया और वर्ष 2019-20 में 1990 करोड़ रुपये का बजट दिया है। हमें इस समय बहुत बड़ी मात्रा में 2,122 करोड़ रुपये का बजट दिया है, ताकि यह आगे बढ़ सके।

मान्यवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली बार हमें यह बजट बहुत बड़ी मात्रा में मिलने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में प्रिंस चार्ल्स फाउंडेशन के अंतर्गत कॉलेज ऑफ मेडिसिन का हमारा एमओयू साइन हो चुका है, जिस पर काम चल रहा है।

ब्रिटेन में आयुर्वेद फेमस हो रहा है, क्यूबा में पंचकर्म का सेन्टर खुल चुका है। एक-से-बढ़कर एक क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं।

गाजियाबाद में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है। इसी तरह से, दिल्ली के नरेला में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी है।

हमें यह जानकर खुशी होती है कि स्मॉल पॉक्स का जो टीका लगता है, वह भी हमारे यहाँ से ही इजाद हुआ है। इमरजेंसी के दौरान जब धर्मपाल जी को बंद कर दिया गया था, तो बिनोवा भावे जी और जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही नाराज हुए, तो उनको तत्कालीन सरकार, माननीय इंदिरा जी ने रिहा तो कर दिया, लेकिन धर्मपाल जी ने कहा कि मैं कुछ दिनों तक भारत में नहीं रहूँगा और वे विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद उन्होंने तीस सालों तक स्टडी की और उनकी कई पुस्तकें आईं। उनकी जो पुस्तकें आईं, उनमें से एक पुस्तक में जिक्र आया है कि बंगाल में बहुत पहले स्मॉल पॉक्स का जो टीका लगा था, वह वहाँ से इजाद हुआ था, वही कारण बना आज के टीके का। …(व्यवधान) हाँ, मिथिला में भी बना और वहाँ भी बना।

इतना ही नहीं, मैं एक-दो चीजें और बताना चाहता हूँ। सर्जरी के बारे में कर्नल कूट का मामला सभी जानते होंगे। कर्नल कूट एक ऐसा व्यक्ति था, जो हैदर अली के साथ टकरा गया था। अंग्रेजों के साथ बार-बार टकराने से हैदर अली नाराज हुए और उन्होंने उनकी नाक काट दी और उसे घोड़े पर बिठा दिया और कहा कि भाग सकते हो, तो भागो। वह भागकर कर्नाटक के एक गाँव बेलगांव में एक वैद्य के पास पहुँचा। उस वैद्य ने कहा कि क्या तुम इस कटी नाक को लेकर इंग्लैंड जाओगे? उसने कहा कि क्या करूँ, कोई उपाय ही नहीं है कि यह जुड़ जाए। लेकिन उसकी नाक को उस वैद्य ने जोड़ दिया। उसके बाद वैद्य ने कुछ दवाई दी, दवाई लेकर वह इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाने के बाद उसने इंग्लैंड के सदन में यह बात कही कि मेरी कटी नाक भारत के एक वैद्य ने जोड़ी है। इसके बाद, इंग्लैंड से डॉक्टर्स का एक डेलिगेशन भारत आया और यहाँ उस वैद्य के बारे में पता किया। उनसे उन लोगों ने पूछा आप यह कैसे करते हो? उस वैद्य ने कहा कि मेरे यहाँ छ: लाख गाँवों में से हर गाँव में एक वैद्य इसी तरह का है, यानी हमारी विधा इतनी शक्तिशाली विधा थी।

श्री अश्विनी कुमार, जो देवताओं के आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया था। यह आप सब जानते हैं। बहुत कम समय है, मैं बहुत महत्त्वपूर्ण और रोचक बातें बताना चाहता था।

अगर आज पैंक्रियाज का कैंसर हो जाए, पैंक्रियाज में सूजन हो जाए, तो भारत ही नहीं, विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, जो इसे ठीक कर सकती है। लेकिन भारत के एक वैद्य ने एक हजार लोगों को ठीक कर दिया है, जो भारत में ही हैं।

जामनगर नगर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करना श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से दिल्ली के सरिता विहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करना, आयुर्वेद के एक वैद्य, जिन्हें आयुष मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, ऐसी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हैं।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on this Bill.

Madam, while reacting on the provisions of the Bill I have a mixed feeling, both of happiness as well as sadness. Happiness is for the legislation that is sought to be passed. It is a good thing that we are doing. Sadness is owing to the fact that the hon. Minister has ignored the interest of the State of Kerala. The State of Kerala had a very strong case for having this internationally known Ayurvedic higher educational centre. There was a proposal from the Government of Kerala to have a university at Kottakkal which is the heartland of my parliamentary constituency. All the hon. Members who spoke before me on this legislation spoke very high about my State. That was really good to hear. If anybody, inside or outside India, thought about ayurvedic treatment, their first choice is Kerala and Kerala only.

In that sense, Kerala's case is very strong. Kerala is having a very glorious tradition of Ayurveda.

Madam, we know ABC of Kerala. What is expansion of ABC? A stands for Ayurvedic, B stands for Backwaters and C stands for culture. That is Kerala. So, in that sense, our demand for a national institute is very important and significant. It was agreed in principle and the Kerala Government had included it in the Budget of 2015-16. The Government of India was also in favour of it. But unfortunately, that has not yet been materialized. We all know

that there is a tendency around the world to return to the nature. Ayurveda, as correctly pointed out by my friends, is a Sanskrit word which means `science of life'. So, I would like to suggest that development of herbal and medicinal plant is very important since it is a vanishing kind of thing. We all know that Ayurveda already existed in this country since Indus Valley Civilization or maybe before that. So, emphasis on research and training on Ayurveda is very much needed. Creative and innovative kind of things need to be further strengthened.

I would like to say one more thing. There is a need for institutions for Ayurvedic Pharmaceutical Sciences. That is an area where we have to give more emphasis on. We have to give emphasis on other things also which is to keep the originality of Ayurveda. It is very important. Quality and branding of Ayurvedic medicines and its standardization is very necessary.

Another important thing that I would like to say is that damage created by commercialization of Ayurveda is a very dangerous thing. We have to ensure the quality of it. I feel that accreditation of Ayurvedic institutions is very necessary. …(*Interruptions*). I am going to conclude. Please give me one more minute. We are from Kerala and it is a very important place for Ayurveda. …(*Interruptions*). Necessity of R&D in this sector is very essential.

With these words, I conclude.

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूं कि हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री सम्माननीय श्रीपाद येसो नाईक जी के मंत्रालय के विषय में बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। श्रीपाद जी बहुत ही हैल्पफुल और खुशमिजाज़ मंत्री जी हैं। जब भी उनके पास जाओ, वे हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके मंत्रालय के विषय में बात करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है।

महोदया, आज सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक एलोपैथी की डॉक्टर होते हुए मैं आज आयुर्वेद संस्थान के बारे में बात कर रही हूं। एलोपैथी वर्सेज़ अन्य मेडीसिन्ज़ में हमेशा से वॉर चलती रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि भले ही अलग-अलग विभाग हों, लेकिन हम सारे डॉक्टर्स फैमिली तो एक ही हैं, इसलिए मुझे इस विषय पर बात करते हुए अच्छा लग रहा है।

मुझे आज यह कहते हुए कहीं न कहीं दु:ख हो रहा है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, जिसमें हम इंडियन्स रहते हैं, हमें जब तक दुनिया के बाकी लोग आकर किसी चीज़ का महत्व नहीं समझाते, तब तक हमें उस चीज़ का महत्व का पता नहीं चलता है। आयुर्वेद हमारा ही साइंस है, लेकिन जब तक दुनिया नहीं बोलेगी कि चीज़ें आयुर्वेदिक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, आयुर्वेद चाय में आना चाहिए, पेस्ट में आना चाहिए, क्रीम में आना चाहिए, तब तक हम लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आता है।

हमें यह महत्व जानने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि भारतीयों के तौर पर जब हम बड़े होते हैं तो यह हमारी परवरिश का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। हम मराठी में हमेशा कहते हैं कि जब घर में बीमारी होती थी, तो पहले कहां लोग डॉक्टर के पास जाकर गोली या इन्जैक्शन लेते थे, उसे हम 'आजी का बटुआ' या 'आई का काढ़ा' कहते थे। इसे आप हिन्दी में नानी या दादी का

बटुआ कहते थे। मां जो काढ़ा बनाती थी, उसको हम इस्तेमाल कर के अपनी छोटी-छोटी तकलीफों को दूर करते थे।

मैडम, मैं एम.डी. डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। कल को मेरा यह भाषण सुनकर सारे डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे गालियां देंगे। मैं यह कहती हूं कि मुझे पिंपल्स की तकलीफ टीनएज से हमेशा से रही है। आज जब एक या दो माह में पिंपल्स निकल आते हैं तो मैं कोई एलोपैथी की क्रीम नहीं लगती हूं। मैं क्या लगाती हूं, यह सुनकर आपको अचरज होगा। मैडम, मैं टूथपेस्ट लगाती हूं तो वह तुरंत दब जाते हैं, क्योंकि उसमें लौंग का तेल होता है। ये सारी छोटी-छोटी बातें घर में करते रहते हैं, लेकिन इनको हम बड़े पैमाने पर अपनाने से कहीं न कहीं शर्माते थे, कतराते थे। इस शर्मिंदगी को दूर करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, क्योंकि आयुष मंत्रालय की स्थापना ही मोदी जी की सरकार में हुई थी।

आज यहां बहुत सारे लोग बात करते हुए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट को हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए यह बिल आया है। इस बिल का महत्व यह है कि यह तीन संस्थाओं को एक छत के नीचे लाएगा, जिसमें कॉलेजेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इनको करने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि आज समय आ चुका है कि नई बीमारियों की रोकथाम के लिए, उनके इलाज के लिए हम कहीं न कहीं आयुर्वेद की पहल लेकर आगे चलें, जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है, उसको हमें अपने देश में भी मनवाने की आज जरूरत है। यह काम अगर किसी के कार्यकाल में हो सकता है तो मुझे लगता है कि वह हमारे आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में ही हो सकता है। आयुष मंत्रालय का काम भी अच्छा चल रहा है। जो लोग काम करते हैं, उनसे ही लोग उम्मीद करते हैं और मांगते हैं। आज यह इंस्टीट्यूट जामनगर में स्थित है। बाकी इलाकों से भी देश में लोग इसकी मांग कर रहे हैं।

मैं यहां आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक छोटा सा मुद्दा उपस्थित करना चाहती हूं। आयुष मंत्रालय के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयुष हॉस्पिटल बनवाने का जो प्रावधान किया गया

था, उसके तहत मेरे जिले में भी आयुष मंत्रालय ने एक आयुष हॉस्पिटल मंजूर किया है, लेकिन उसका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक हम इसको जिला स्तर पर लेकर नहीं जाएंगे तो आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे।

मैं आपके माध्यम से यह विनती करती हूं कि इसका काम जल्द से जल्द हो सके और पुरातन ज्ञान को नए जमाने के मानक और मापदण्ड पर खरा उतारने के लिए आज यह इंस्टीट्यूट एक पहल है। जब यह इंस्टीट्यूट बनकर फुली फंक्शनल हो जाएगा, तब आयुर्वेद की नॉलेज दुनिया की नॉलेज के सामने अपनी भूमिका निभा पाएगी। मैडम, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए, मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए, इस बिल का समर्थन करती हूं।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I thank you for this opportunity to take part in the discussion on the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020.

To begin with, I congratulate the hon. Minister of AYUSH, Shri Shripad Yesso Naik, for introducing a Bill that seeks to promote the importance of Ayurveda across the nation.

Ayurveda is a necessity, especially today, because of the rising consumption of modern medicines that use chemical ingredients and chemicals that are not familiar to the body. So, they behave like foreign bodies in our body but Ayurvedic remedies are natural and familiar to the body. So, it does not create any stress for the body to accept and get acted in our body.

However, I have some strong objections to the Bill. This Bill seeks to merge three existing Ayurvedic institutions from Jamnagar, Gujarat.

The main objectives mentioned in the Bill are to: (i) develop patterns of teaching in medical education in Ayurveda and pharmacy, (ii) bring together educational facilities for training of personnel in all branches of Ayurveda, (iii) attain self-sufficiency in postgraduate education and to meet the need for specialists and medical teachers in Ayurveda, and (iv) to make an in-depth study and research in the field of Ayurveda.

The main functions of the Institute include: (i) providing for undergraduate and postgraduate teaching in Ayurveda, (ii) prescribe courses

and curricula for both undergraduate and postgraduate studies in Ayurveda, (iii) provide facilities for research in the various branches of Ayurveda, (iv) hold examinations and grant degrees, diplomas, and (v) maintain well-equipped colleges and hospitals for Ayurveda and supporting staffs such as nurses and pharmacists.

Now, each and everyone of these objectives and functions can be better fulfilled by Kerala than any other State in India. Kerala has the largest number of Ayurvedic Colleges and Practitioners compared to any other place in the world and Kerala is, probably, the only State in India where Ayurveda is used as a mainstream medicine.

Ayurveda has a rich history; originally shared as an oral tradition, Ayurveda was recorded more than 5,000 years ago in Sanskrit in the four Vedas namely, the Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. Ayurvedic theory states that all areas of life impact one's health. So, it follows that the Vedas cover a wide variety of topics including health and healthcare techniques, astrology, spirituality, government and politics, art and human behaviour. In short, Ayurveda is a method of getting pampered and healed by the best of what Mother Nature has to offer and if Ayurveda is called the mother of all healings, then Kerala should be called the maternity home, not any other State.

Kerala is one of the very few places in the world where an average temperature of 24-28 degrees prevails in the rainy season. Our State

experience a cool monsoon season with a very good climate throughout the year. The rich weather, the pristine white backwaters, peaceful environment and a source of wide variety of plants and herbs with medicinal value are requirements for the practice of Ayurveda that Kerala offers better than any other place in the world. The Trivandrum Ayurveda Medical College was established in 1899. If none of these compelling reasons are still not sufficient, out of the numerous papers published all over the world on the Ayurvedic heritage and practices, Kerala has the largest number.

So, I urge the Minister to establish an institute on Ayurveda in Kerala with national importance and acknowledge thousands of years of practice of Ayurveda in Kerala.

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Madam Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020.

I would like to first congratulate hon. Prime Minister, Narendra Modiji and the hon. Minister, Sripad Yesso Naikji for bringing this Bill to further strengthen the development of Ayurveda in India.

The Bill has been brought in at the right time in view of the rapidly growing role of Ayush systems in addressing the public health challenges of India; and conferring the status of national importance to this Institute will boost the importance of Ayurveda in public health.

Madam, since I have been allotted only three minutes, I will just try to make some suggestions, through you, to the hon. Minister. The Ministry of Commerce has said that the total world herbal trade is currently assessed as 120 billion US dollars. India's share in the global export of herbs and herbal products is low due to inadequate quality control procedures, lack of research and development, and lack of regulatory framework in the trade of medicinal plants.

For development of Ayurveda and Ayush systems, we have to incentivise and promote the export of herbs and herbal products. Secondly, the dream project of our hon. Prime Minister, PMJAY offers a cashless insurance of up to Rs. Five lakh for poor families. In this connection, I would like to

suggest that if we could include AYUSH system of medicine under this, it will give a boost to the Ayurveda system in this country.

Lastly, I would like to thank the hon. Minister for sanctioning a 30-bed AYUSH Hospital in my constituency, Ahmednagar, which will provide Ayurvedic healthcare facilities to the people of Ahmednagar as well as in its adjoining areas. However, I would like to request the hon. Minister to increase its capacity from 30 beds to 200 beds so that a greater number of people can avail medical facilities.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Madam Chairperson, I thank you for giving me the opportunity.

The initiative of the Central Government to bring the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill is an effort to develop medical education in Ayurveda, with a view to make it a prevalent practice across the country. Our hon. Prime Minister, Narendra Modiji is promoting Yoga and Ayurveda in our country.

As such, I congratulate our hon. Minister of State of the Ministry of AYUSH, hon. Shripad Yesso Naik-ji, for having brought this Bill for consideration in this august House.

Sir, the main motto of the Bill, as mentioned in the Statement of Objects and Reasons, is to conglomerate three Ayurvedic Institutes in the campus of Gujarat Ayurveda University at Jamnagar in Gujarat by establishing them as one institutions, and to upgrade standards of Ayurveda with introduction of various advanced courses in Ayurveda.

On this line, Section 12 of this Bill describes its major objects of developing patterns of teaching, bringing together in one place educational facilities of the highest order for the training of personnel in all important branches of Ayurveda including Pharmacy, attaining self-sufficiency in postgraduate education to meet the country's needs for specialists and medical teachers in Ayurveda, and making an in-depth study and research in the field of Ayurveda.

At this juncture, I would request the hon. Minister for AYUSH to upgrade the National Institute of Siddha situated at Chennai in my State of Tamil Nadu to the level of national importance like IIT, IIM, NIT etc., so that the Institute can itself decide the eligibility criteria for admission and standard syllabus as per national and international demand, duly ensuring the importance to every student.

Apart from the above, I would also request the hon. Minister for AYUSH to commence one National Institute of AYUSH at temple town in Palani, in my State of Tamil Nadu. It is a hilly area where plenty of medicinal minerals and herbs are available adjacent to my Theni Parliamentary Constituency. The said place 'Palani' is the *Samadhi Sthala* of the 'Bogar Siddhar', who was one among the 18 Siddhas, with adequate knowledge of Ayurveda medicine, astrology, spirituality and yoga.

As an expert in medicine, he prepared an amalgam of nine medicinal minerals using about 4,448 rare herbs. Using this amalgam, that is, *Nava Bashanam*, he made the main idol, Moolavar, which is currently worshipped in the said temple for Lord Muruga.

With these few words, I support this Bill. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Chairperson, I rise to support this Bill with a suggestion to declare the Thiruvananthapuram Regional Ayurvedic Research Institute as an Institute of national importance.

Madam, India is proud of the fact that our country is having the origin of Ayurveda, and the whole world is looking at India regarding the innovative models of traditional Ayurvedic knowledge, treatment and medicines.

Ayurveda is a system of medicines, which treats both body and mind. Therefore, it is the right time to give more focus to the Indian Systems of Medicines, particularly, Ayurveda.

Ayurvedic system is a traditional medicine system in India, which is widely practised uninterruptedly. Even during the time of the Buddhist period in India, there are codified literatures dated thousands of years back. For example, Charaka Samhita and Sushruta Samhita. These are very old literatures, which were available even at the time of the Buddhist. It is the first organised form of medicines on the planet, and continues to be a vibrant system of healthcare for millions of people in the world.

Madam, what is the significance of Ayurvedic treatment? Fifty years back, a majority or most of the deaths that took place in the globe, was because of the communicable diseases. But if you examine the '2016 World Health Organisation Report' relating to mortality, you would find that 71 per cent of the deaths are due to non-communicable diseases, namely, cardiovascular, cancer, diabetics and related complications, and respiratory

diseases. Non-communicable diseases kill 41 million people per year. That means, 71 per cent of the death is because of the non-communicable diseases. That is the recent Report of the World Health Organisation of 2016.

What is the significance and unique feature of Ayurveda? We have to see it in that circumstances.

The ayurvedic treatment modalities has a great effect on chronic, non-communicable lifestyle disorders both, in prevention and in improving the quality of life of the patients. This is the uniqueness of ayurvedic treatment. As far as the non-communicable diseases like cardiovascular, diabetes and related complications, cancer as well as all these lifestyle disorders are concerned, we have both, the prevention as well as improved lifestyle in Ayurveda.

Madam, I would like to place on record the significance of Ayurveda in my State of Kerala. My learned friends have almost cited all these things. The State of Kerala is pioneer in promoting ayurvedic system of medicine. We have five Government ayurvedic medical colleges and 20 private colleges. We have the Thiruvananthapuram Ayurvedic College founded in 1889. In 1902, the Kottakkal Arya Vaidya Sala was started. Most of the eminent personalities, the then Presidents, Prime Ministers, were getting treatment in Kottakkal Arya Vaidya Sala, which is 117 years old. It is having academic excellence both, in theory and practice.

There are two ways of ayurvedic medicinal preparation. There is a metallic preparation as well as herbal preparation. In Kerala, we are mainly depending on herbal preparations and, that is why, the side-effects will be very less. That is the significant feature of ayurvedic treatment of Kerala. The climatic conditions of Kerala suits for ayurvedic treatment. Kerala is preserving Ayurveda without losing its theoretical integrity and pragmatic value.

Hence, Madam Chairperson, I demand that Regional Ayurveda Research Institute, Thiruvananthapuram also be declared as an institute of national importance. I also urge upon the hon. Minister and the Government that a National Institute of Herbal Medicinal Plants be commenced in the State of Kerala. If possible and feasible, let it be in my constituency, Kollam. We are ready to provide the land for having such an Institute in Kerala.

Coming to the Bill, I fully support the Bill in having an Institute of National importance in Gujarat. When we give preference to Gujarat, I appeal to the Government to please have a look at the State of Kerala which is pioneer in promoting ayurvedic treatment throughout the globe.

With these words, I support the Bill. Thank you very much.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदया, मैं सबसे पहले तो इस बिल का समर्थन करता हूं। यहां पर जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी वक्ता है, मैं उन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं पहली बार यह देख रहा हूं कि चाहे इधर से बोल रहे हों, या उधर से बोल रहे हैं, सभी लोग आयुर्वेद का समर्थन कर रहे हैं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी और हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाईक जी का भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।...(व्यवधान)

महोदया, यहां कई लोगों ने बोला है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं मुख्य-मुख्य बातें बताना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति और परंपरा का मूल वेद है और वेद से निकला हुआ, ऋग्वेद से निकला हुआ जो उपवेद है, उसका नाम आयुर्वेद है। कई लोगों ने कहा है कि आयुर्वेद केवल मात्र किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है। हमारे जीवन में जो चार पुरुषार्थ होते हैं - धर्म, अर्थ काम और मोक्ष, उनको प्राप्त करने का साधन आयुर्वेद है। इसलिए, आयुर्वेद यह कहता है कि -

'धर्मार्थ काम मोक्षाणां आरोग्यं मूलमुतमम्।'

अच्छा मूल और उत्तम आरोग्य कैसे प्राप्त हो, यह आयुर्वेद बताता है। इसीलिए, डब्ल्यूएचओ ने बाद में किया है, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे पहले स्वस्थ कौन है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, यह सबसे पहले आयुर्वेद ने कहा है। स्वस्थ का मतलब यह है कि स्वस्थ, जो अपने में स्थित है। बिना किसी दूसरे की सहायता लिए, बिना कोई दवाई लिए, जो अपने आप रह सकता है, जो अपने सभी काम कर सकता है, वही स्वस्थ है। इसलिए -

'समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः,
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधियते।'

आयुर्वेद ने सबसे पहले दुनिया के अंदर स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। कई लोग बोलते हैं कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी का नाम आदमी है, लेकिन सबसे ज्यादा बीमार भी मानव ही होता है। जंगली जानवर नहीं होते हैं, पक्षी नहीं होते हैं। वे क्यों नहीं होते हैं? इसका यह कारण है कि हमारा जो मूल आहार-विहार है, हमने उसको छोड़ दिया है और आयुर्वेद इसी बात पर जोर देता है।

वह कहता है कि पॉलीटिक्स करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए –

'सर्वम मन्यत परित्यज्ये शरीरम् अनुपालयेत्,
तद् भावेय भावानाम् सर्वाभावे शरीरानाम्।'

आप दुनिया में सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी is how to remain fit, यह आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद इसकी बात करता है।

मैडम, मेरे कुछ सजेशंस हैं। हमारे मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। कई लोगों का सजेशन आ गया। अभी हम लोग जामनगर के अंदर बना रहे हैं। जामनगर बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहां पर यह इंस्टीट्यूट बनना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर चारों जगह – दक्षिण के अंदर भी बनना चाहिए, उत्तर के अंदर भी बनना चाहिए और पूर्व के अंदर भी बनना चाहिए। मैं माननीय प्रधान मंत्री और सदन से भी निवेदन करूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 69 हजार करोड़ रुपये हैं और आयुष मंत्रालय का, जिसके ऊपर आज सारा सदन एक मत है, उसका पूरा बजट 2122 करोड़ रुपये है। यह बजट कई गुना, कम से कम दस गुना बढ़ना चाहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। उत्तर में पतंजलि बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए पतंजलि को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाना चाहिए, वहां लैबोरेट्री है, वैज्ञानिक हैं, एक्रिडेटिड लैब है, यह सब होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि किस प्रकार से मालूम चलता है कि आदमी बीमार है। आयुर्वेद ने कहा है कि – "नाड़ी, मूत्रं, मलं, जिव्हां, शब्द स्पर्श दृगाकृतिम्। "

नाईक साहब, आज हमारे देश से नाड़ी विज्ञान लुप्त होता जा रहा है, आयुर्वेद से लुप्त होता जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि नाड़ी विज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाए, इस परंपरा को कायम रखा जाए, ताकि इसको जीवित रखा जा सके। मैन्युफैक्चर के बारे में कहना चाहता हूँ कि दवाई हम लोग बनाते हैं, कई बहुत सी गड़बड़ें चल रही हैं, जिससे हमारा आयुर्वेद बदनाम होता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वंसलोचन बांस से निकाली हुई चीज़ है, जिसका आज रेट

दो से ढाई हजार रुपये प्रति किलो है, लेकिन आयुर्वेद की दवाई बनाने वाले लोग वंसलोचन की जगह सिलिका जेल यूज़ करते हैं, सिलिका जेल की कीमत सौ से डेढ़ सौ रुपये किलो है। आयुर्वेद कहता है कि भस्म बनाने के लिए कैल्सिनेटिड करना चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ी-बड़ी भट्टी जला कर हम ऑक्साइड में बनाते हैं, इससे उसकी टॉक्सिटी बढ़ती है, यह बंद होना चाहिए। आयुर्वेद ने जैसे कहा कि जो पद्धति है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम दवाई कैसे बनाएंगे, केवल इस बात की जरूरत है कि हम ऑटोमेशन कैसे करें। आज बड़ी जनसंख्या को देखते हुए हम उसको ऑटोमेशन कैसे करें? मैं माननीय मंत्री जी और सदन से एक और निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद के लोगों को, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भांग से, मॉफीन से कोई भी दवाई बनाने की अनुमति इस देश में आज तक नहीं दी गई है। पेन किलर दवाई बनाने की अनुमति आयुर्वेद को नहीं दी गई है। आयुर्वेद क्यों नहीं बना सकता है? इसके लिए परमिशन देना बहुत जरूरी है। मृगश्रंग नाम से एक भस्म बनती है, जो बहुत सी बीमारियों में काम आती हैं। इस देश के अंदर हमारा वन विभाग करोड़ों रुपये के हिरण के सींग को जला कर खत्म करता है, लेकिन आयुर्वेद के लोगों को बेचता नहीं है, उसका यूज़ होगा, उसकी दवाई बनेगी और बहुत भयंकर बीमारियों के अंदर उसका इलाज काम आएगा। लुकमान वैद्य ने एक बात कही थी कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं, जिसका इलाज वनस्पति के अंदर नहीं है, केवल दो बातों को छोड़ कर के एक बुढ़ापे को छोड़ कर और एक मौत को छोड़ कर। यहां यह हमारा अज्ञान है कि हम वनस्पति के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। लाखों तरह की वनस्पती है, उसका हम क्या-क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं।

मैडम, अप्रैल, 2019 के अंदर एक फिल्म बनी, उसका नाम है ईस्टर्न मैडिसिन, उसमें दुनिया के बड़े-बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के इंटरव्यूज़ हैं। उन्होंने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, अगर आप देखो सन् 2002 के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक एडवर्टाइज़मेंट दिया था, और कहा था कि आज-कल की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, they are not health-

giving industries; they are disease inducing industries. उन्होंने कहा कि किस प्रकार से this is a fraud on cancer.

मैडम, एक बात कह कर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि आज हम अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको आयुर्वेदिक काउंसिल परमिशन देता है। अगर हम कोई दवाई बनाना चाहते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई कोई भी पान बेचने वाला भी रख सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जे.आर.डी. टाटा की बात बताना चाहता हूँ। जे.आर.डी. टाटा ने हेल्थ के बारे में किताब में अपनी भूमिका लिखी है। अंग्रेजी में लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार हो, go to the doctor, get his prescription and pay his fees because doctor has to survive. उसका प्रिस्क्रिप्शन ले कर केमिस्ट के पास आओ, उससे दवाई खरीद कर पैसा दो, क्योंकि Chemist has to survive, लेकिन यह अंग्रेजी दवाई ला कर घर में रहो, but do not take it because you have to survive. अगर अपने को सर्वाइव करना है, अच्छी हेल्थ बनानी है, हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा।

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for giving me this opportunity. Thiruvalluvam says, *"Noi Naadi Noi Muthal Naadi Athu ThaNikkum Vaai Naadi Vaippaseyal".* It means that let us find the disease, its cause, the cure for this disease besides having thorough examination of all the factors using our skill. I wholeheartedly support the Bill for the establishment of an Ayurveda Institute for Training and Research in Jamnagar, Gujarat. Ayurveda is an ancient and traditional form of medicine. It has so much of ancient pride and traditional glory. In villages they call it as grandmother's medicine. It is the best medicine providing cure for several ailments. In Ayurveda form of alternative medicine, there is a permanent solution for diseases like Cancer, heart ailments and urological diseases. Similarly fracture of bones and displacement of bones have permanent solutions in Ayurveda form of medicine. I am proud to know and welcome the setting up of an Institute of Teaching and Research in Ayurveda Medicine in Jamnagar, Gujarat.

Kottakkal Arya Vaidya Sala is an Organisation in Kerala extending best medical service continuously in the field of Ayurveda. I therefore urge upon the Government to set up a similar Research and Training Institute for Ayurveda medicine in Tiruvananthapuram of Kerala. If this Institute is located in Kerala, all the south Indian States will be benefited. Not only giving importance to the Northern States, adequate importance should be given to the Southern States

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

as well. Kerala should be given an opportunity. Particularly, there are two Medical Colleges in my Nagappattinam constituency. Ayurveda form of medicine and Ayurveda drugs should be made available here in these two Medical Colleges. Thank you for this opportunity.

***SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Madam Chairperson, Vanakkam. Ayurveda medicine is a benign gift from India to the entire humanity spread across the globe. I am duty-bound to welcome the Bill aimed to set up the Institute of Teaching and Research in Ayurveda medicine in Jamnagar of Gujarat.as an Institute of National Importance by merging several institutions into one. World famous Ayurveda medicine has lots of presence in Kerala. Similar to Ayurveda, I wish to register here that Siddha medicine is also world famous as traditional form of medicine. That is why near Chennai at Tambaram Sanatorium, a Siddha Medical Research Institute has been set up in the name of Ayothidoss Pandithar. But this Institute has been neglected and is under-developed without due attention. Therefore, the Union Government should declare this Ayothidos Pandithar Siddha Medical Research Institute as an Institute of National Importance. The Union Government should come forward to develop Siddha Medicine throughout the country by strengthening it. I request you that not only at the level of Tamil Nadu State, but also Siddha Medicine should be strengthened with due importance at the national level also. As you have taken steps to set up an Ayurveda Medicine Research and Training Institute in Jamnagar of Gujarat, a similar Institute of National Importance should be set up in Kerala, particularly in Tiruvananthapuram which is famous for Ayurveda medicine and treatment. There is a Coronavirus threat throughout the country and the world. In India, as a cure to this virus,

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

some persons belonging to an organisation are spreading some superstitious practices or wrong belief that drinking cow urine can be a cure to the impact of Coronavirus. I have an appeal to make here. I have learnt that hon. Prime Minister will deliver an address to the nation at 8 pm today. I hope that Hon. Prime Minister will also give some advice in this regard in his lengthy Address to the Nation. Thank you.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं संक्षिप्त में कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं तैयारी बहुत कुछ करके लाया था, लेकिन समय का अभाव है।

आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन धरोहर है। हमारे देश के सैकड़ों ऋषियों ने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके एक-एक सूत्र पर अध्ययन करके इस चीज को हम तक पहुँचाया है। खास तौर से हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, जिन पर अनुसंधान की आवश्यकता है, किया भी है। जैसे चरक की चरक संहिता, सुश्रुत का शल्य चिकित्सा का सबसे प्रथम ग्रंथ है- सुश्रुत संहिता।

सुश्रुत संहिता, वाग्भट का कायचिकित्सा, भाव मिश्र का भावप्रकाशम, माधव का शारंगधरसंहिता, अष्टांग संग्रह, इस तरह से आयुर्वेद के बहुत सारे इस प्रकार के ग्रंथ हैं। कश्यप ऋषि का कौमारभृत्य बाल चिकित्सा शास्त्र है। सैंकड़ों ग्रंथों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ और यहाँ कह सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा विषय रहा है। मेरे गुरू जी स्वामी सर्वानन्द जी ने 85 साल आयुर्वेद की चिकित्सा की। श्रद्धेय स्वामी ओमानन्द जी ने 50 साल आयुर्वेद की चिकित्सा की और मुझे इन दोनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। कई बार एक प्रश्न कहने को आता है कि आयुर्वेद त्वरित काम नहीं करता है, लेकिन आयुर्वेद में इस प्रकार की चिकित्सा है कि एक बार यदि आदमी की जिव्हा पर औषधि चली जाए, तो अचेत व्यक्ति 5 मिनट में खड़ा हो सकता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आयुर्वेद में जो अनुसंधान का काम होना चाहिए था, हम पश्चिम की दौड़ में इस प्रकार बहके कि

हमने पश्चिम की दवाओं पर बहुत काम किया, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए, बड़े-बड़े रिसर्च के काम हुए। मैं बजट में भी देखता हूँ, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने आयुर्वेद की सुध ली है, नहीं तो ऐलोपैथिक के बजट में जितना रिसर्च पर पैसा दिया जाता है, जितने इंस्टीट्यूट खड़े किए जाते हैं, उसके मुकाबले आयुर्वेद में 'आटे में नमक' जैसी स्थिति रहती है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करूँगा कि आयुर्वेद का जो मूल है, वह संस्कृत है। आजकल खास तौर से आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जा रहा है, बायो के स्टूडेंट को तो वहाँ लिया जा रहा है, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी को अवॉइड किया जा रहा है। जब बच्चे के पास संस्कृत नहीं होगी, तो संस्कृत के जिन सामान्य ग्रंथों का मैंने यहाँ नाम लिया है, वह इनको पढ़ेगा कैसे और जब तक उसको भाषा समझ में नहीं आएगी, तो वह उसके विषय को नहीं समझ पाएगा।

दूसरा, मेरा निवेदन यह था कि तीन-चार मंत्रालयों को मिलाकर के एक कमेटी, आयोग बनाया जाए। जैसे आपको जड़ी-बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कृषि मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दोनों मिलकर काम करें। जब तक आयुष मंत्रालय के साथ में कृषि मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम वन औषधि नहीं उगा सकते हैं। आज वनों में स्थिति यह हो गई है, पहले हमारे जितने भी वैद्य लोग थे, वे जंगल में जाकर जड़ी-बूटियाँ लेकर आते थे और ताजा दवाओं, ताजा औषधियों से काम किया करते थे, रस आदि का निर्माण करते थे। आजकल लोग जंगल में घूसने ही नहीं देते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए और इस रूप में डेवलप किया जाए कि वहाँ वन औषधि पैदा की जाएं। बहुत से वृक्ष हैं, बहुत सी जड़ी-बूटियाँ हैं जो समाप्त होती जा रही हैं। हिमालय में बहुत सारी औषधियाँ इस प्रकार की है, जो आज मिलती नहीं हैं। जैसे माननीय डॉ. सत्यपाल जी आपके सामने कह रहे थे कि बांस से हमें जो औषधि प्राप्त होती थी, आज वह नकली आ रही है। बहुत सी दवाईयाँ इस प्रकार की हैं, जो नकली प्राप्त होती हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि

आप इन तीनों मंत्रालयों के साथ समन्वय करके औषधियों को उत्पन्न करने का एक प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाएं, ताकि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति का पूरा विश्व लाभ उठा सके। जो आजकल नई-नई बीमारियाँ आती हैं, इसके लिए सबसे बड़ी एनर्जी अगर कहीं से हमें मिल सकती है तो वह आयुर्वेद से मिल सकती है। आयुर्वेद में किसी भी प्रकार के रिएक्शन की संभावना वन परसेंट रहती है और ऐलोपैथिक में कदम-कदम पर रिएक्शन की संभावना रहती है। मेरा निवदेन है कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020. I would like to appreciate the hon. Minister for taking an initiative for setting up this institute.

Sir, I have an inhibition that the Minister has not taken consideration of the situation in Kerala. I am sure that the Minister has now come to the conclusion that almost all the hon. Members, who have participated in the discussion, have mentioned about the significance of Ayurveda in Kerala. My humble request to the hon. Minister is that along with setting up an Institute of Ayurveda at Jamnagar, he should take an initiative to set up one more national institute of Ayurveda in Kerala because this is the consensus of this House.

Sir, Ayurveda has its origin about 5000 years back in India.

17.00 hrs

Centuries back, Ayurveda was the main medical stream for practice in India. In Kerala, Ayurveda continued to thrive over centuries because of its lands, geographical isolation and fortunes etc. Kerala is the paradise of Ayurveda. No country in the world can claim parity with Kerala in Ayurveda.

Kerala is blessed with good climate and abundant natural herbs that make it the best place to enjoy rejuvenating sessions and the Ayurvedic therapy sessions as well. Around four million people are coming from abroad to India, out of which more than 90 per cent are coming to Kerala for Ayurveda

treatment. People from all over the world come to Kerala in search of Ayurveda treatment.

Madam, please give me one more minute. Prior to the implementation of the institutional education system in Ayurveda, long before the system of gurukula was existing in Kerala, especially in the field of Ayurveda. Ayurvedic disciples educated under the gurukula system have contributed to the renaissance of the Ayurveda in the modern world.

Madam, I would request once again …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सांसद रामचरण बोहरा जी।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Please give me one minute.

Ayurveda system of Kerala is model for our nation. So, I would once again request the Minister to consider starting a national institute in Kerala. Thank you very much.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): माननीय सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आयुर्वेद का महत्व समझा और वर्ष 2014 में आयुर्वेद का नया मंत्रालय बनाया और उसका जिम्मा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया गया। वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए बजट का एलोकेशन किया क्योंकि जो वर्ष बीते, उसमें किसी ने आयुर्वेद पर ध्यान नहीं दिया। अभी वर्ष 2019 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके बजट में 52 प्रतिशत का इजाफा किया।

आयुर्वेद से जिस प्रकार के इलाज होते हैं, प्राचीन काल से जिस तरह से आयुर्वेद में जड़ी-बूटियां लाकर औषधियां बनाई जाती थीं, उस समय यह होता था कि अगर दिन में किसी झगड़े में किसी को घाव लग जाता था तो रात को उस पर मरहम लगाने से रात भर में वह घाव ठीक हो जाता था। अगर किसी चिकित्सा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो वह आयुर्वेद में नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वर्ष 2014 से लगातार छ: वर्षों तक इस पर काम किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद पर जिस तरह से काम हुआ है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने योग को फिर से शुरू करके 177 देशों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का काम किया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि धन्वन्तरि, जो आयुर्वेद के दाता हैं, उनका महत्व समझकर उन्हें मान्यता देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना को आयुष मंत्रालय में देकर देश की आधी आबादी का इलाज करने का काम किया, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, उस अनुपात में आयुष मंत्रालय के केन्द्रीय संस्थानों की संख्या नगण्य है। आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित, वित्त-पोषित जो गिने-चुने संस्थान हैं, उनमें एकरूपता नहीं है। शिक्षकों की योग्यता, अनुभव एवं वेतनमान में बहुत बड़ा अन्तर है। इन संस्थानों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है जबकि एलोपैथी में 65 वर्ष है। इसलिए इनकी भी 65 साल की जाए, ताकि इनके जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का लाभ विभाग को और जनता को मिल सके।

महोदया, आयुर्वेद के नए संस्थानों की स्थापना की जाए। साथ ही, सेवा-नियमों में एकरूपता लाकर सेवानिवृत्ति की आयु को, जैसा मैंने पहले बताया कि इसे बढ़ा कर 65 वर्ष किया जाना चाहिए। प्रामाणिक एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियों के निर्माण के लिए सरकार औषधि निर्माणशाला का निर्देश दे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसी अल्प विकसित चिकित्सा पद्धतियों की प्रामाणिकता की जांच कर लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करें।

[*]**SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE):** I come from the land of ayurveda. Madam Speaker, Kerala is God's own country. It is also the land of ayurveda. Therefore I, whole heartedly support the bill introduced by the Minister. Madam, *Aushani Anaushani, cha drayva guna Karmani dayanti, iti ayurveda*. This was said by Acharya Charaka. *Ayus* or life is the period between birth and death in short, Ayush means life and ayurveda is the knowledge of life. So ayurveda, provides knowledge for the betterment of the quality of life.

Madam in north India, we follow the works of Acharya Susrutha and Charaka, in Kerala we follow the works of Vakbhata Acharya, namely Ashtanga hridaye and Ashtanga Samyam.

Madam, I am mentioning a pertinent point. Our Hon. Prime Minister, had participated in a programme organized in Calicut. It was the international ayurveda fest. He declared on that occasion, that Kerala will be given additional packages for the promotion of ayurveda. But nothing has happened so far. My request Madam, is that since Kerala is the homeland of ayurveda the National Institute for ayurveda should be created in Calicut.

There are so many fake medicines that are produced in our country, because of non availability of raw materials. I want to request the Minister, that there should be co-ordination between the Forest Ministry and the agricultural department and the Educational Ministry and they should coordinate, and

[*] English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

come out with the programme to develop nurseries were medicinal plants and herbs can be cultivated in adequate quantity.

Kottakkal is an prestigious ayurvedic college with a great tradition. I humbly request that Kottakkal may kindly be given the status of a deemed university. I have nothing more so add, but I would like to request the Minister that, you should consider the points I raised here. Because, you yourself had declared when you come to Kerala that you will give a National Ayurvedic Institute to Calicut. So please fulfill that promise you gave us. I conclude, thank you very much.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, मैं इस बिल का बहुत ज्यादा समर्थन करना चाहती हूँ। जैसाकि अभी सत्यपाल जी ने कहा कि ऋगवेद से आयुर्वेद निकला है। आज हम आयुर्वेद और उस पुरानी पद्धति को भूल चुके हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ही आयुर्वेद पर टिकी हुई है। हम तो इंसान हैं, लेकिन आप जानवर को भी देखें तो जो डॉग है, अगर उसको इन्डाइजेशन हो जाता है तो वह घास खाता है। घास खाने के बाद वह वोमिटिंग करता है और उसके बाद उसकी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। आज हम अपनी उस पुरानी पद्धति को भूल चुके हैं। यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के लोग पीपल को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम पीपल को पूजते हैं, क्योंकि वह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम तुलसी को पूजते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा एंटी वायरल और एंटी बैक्टिरियल कोई भी पौधा नहीं है। उसको हम ओसिमम बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो जो यूकेलिप्ट्स है, अगर आप सफेदे के तेल से मालिश कर लें तो मुझे लगता है कि आपका हर तरह का जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है।

अगर हम पुराने समय और रामायण की बात करें, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी हिमालय पर जाकर संजीवनी बूंटी लाए थे, उसकी वजह से उनकी जान बची। मुझे लगता है कि हम अपने आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा दें और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर जगह-जगह इसके संस्थान खोले। अभी पिछले दिनों ही आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत जगह पर वेलनेस सेन्टर खोलें। Prevention is better than cure. इससे हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं। आज वह 8 बजे कोरोना वायरस पर बोलने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब के सब गर्म पानी से गार्गल करें, तुलसी पत्ते का सेवन करें। इसके साथ-साथ अगर हम ज्यादा से ज्यादा संतरा, कीनू, मौसमी फलों को खाएं और विटामिन-सी को अपने अंदर रखें तो हम उस कोरोना वायरस को अपने अंदर पनपने से रोक सकते हैं। मैं इस बिल का बहुत ज्यादा समर्थन करती हूँ। जिस तरह से हमारे मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने इसके अंदर काम किए हैं, इसको बजट दिया है। अगर इसको और भी ज्यादा बजट दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairperson. According to modern Ayurvedic sources, the origin of Ayurveda had been traced to around 6000 BC, when they originated as an oral tradition.

Ayurveda is a discipline of the Upaveda or auxiliary knowledge in the Vedic tradition. Medicine is as old as life itself. Ayurveda is the system of medicine that evolved in India and has survived as a distinct entity from remote antiquity to the present day.

The Sanskrit term 'Ayurveda' translates to knowledge of life. Our five senses serve as the portals between the internal and external realms, as the five great elements of ether, air, fire, water and earth, the dance of creation around and within us.

Madam, systematic development of Ayurveda started in Samhita Era with oldest known manuscript of Charak Samhita. Subsequently, Sushrutra also made a number of compilations. The text of Charak Samhita is a transcription of classroom conversation between Atreya Punarvasu and his students. This is believed to be written in 6th Century BC.

The basic question that arises is who is the father of modern Ayurveda. It is Dr. Muhammed Majeed. He belongs to the place from where our great friend Shri Premachandran comes. He is the world ambassador, also referred to by many, as the Father of Molecular Ayurveda and Chairman of Sami Group of companies. Dr. Muhammed Majeed is the native of Kollam in Kerala. He

introduced to the Americans that Ayurveda from India can act as a complete curative to their various ailments.

Madam, I support the institute being elevated to the status of national importance. We would also expect that in near future, more such institutes will be established throughout the country. Odisha has five good institutions relating to Ayurveda and I would also expect that Odisha also gets adequate support from the Union Government.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नंबर बहुत लेट लगा है, मेरा निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा बोलने का समय दें। मैं मूल रूप से आयुर्वेद का ही चिकित्सक हूं और यहां चुनकर आया हूं। मैं सोच रहा था कि मुझे शुरू में बोलने का अवसर मिलना चाहिए था।

मैं आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 का समर्थन करता हूं। आज आयुर्वेद की महत्ता पर जामनगर में शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए बिल लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज कम से कम इनके मार्गदर्शन में यह देश फिर से आयुर्वेद की महत्ता को प्राप्त करेगा। 3000 से 5000 वर्ष पुरानी विधा, जिसे हम अनेक वर्षों की गुलामी के कारण भूल गए थे, आज पुन: इसे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से योग को लाया गया है, ऐसे ही आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

यहां बहुत से सांसदों ने बातें कही हैं, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। इसमें जितनी विधाएं हैं, उनका आज पुन: अनुसंधान करने की आवश्यकता है क्योंकि यह कहा भी गया है कि दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष, मिट्टी या पेड़-पौधा नहीं है, जो औषधि न हो, केवल हमें उसका गुण धर्म मालूम होना चाहिए। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। औषधियां भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी हैं और हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है। बीमारी केवल इनकी कम या अधिक मात्रा के कारण होती है। जिस चीज की कमी होती है, अगर उसे पूरा कर दिया जाए तो चिकित्सा हो जाती है। एलोपैथी में लक्षण आधारित चिकित्सा होती है और इसमें वात, पित्त, कफ से देखकर होती है। यदि कमी की पूर्ति कर दी जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है।

हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और जड़ी-बूटियों की संख्या कम हो गई है। इनको उत्पादन की दृष्टि से किसानों के साथ जोड़ना चाहिए। आज के समय में उत्पादन का अनुसंधान किया जाना चाहिए कि किस बीमारी में आज के परिप्रेक्ष्य में कितना गुण धर्म बचा है या कितने गुण धर्म की कमी

हुई है। इसे देखते हुए आज की तारीख में कितना डोज़ देना चाहिए, इसके ऊपर अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

नाड़ी परीक्षण के बारे में, जैसे अभी सत्यपाल जी ने बताया, नाड़ी परीक्षण में पहले हमारे पुराने वैद्य केवल नाड़ी देखकर बता देते थे कि तुमने क्या खाया है, क्या पिया है और क्या बीमारी है, उसके आधार पर वे चिकित्सा करते थे। इसलिए, आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मैडम, एक मिनट। इसको प्रत्येक औषधि के गुणधर्म के आधार पर करें। आयुर्वेद में खान-पान के बारे में भी बताया गया है। सुबह से लेकर रात्रि तक हमारी दिनचर्या क्या होगी? आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और मौसम के हिसाब से सारा खान-पान और रहन-सहन था। हम बीमार नहीं होते थे। आयुर्वेद में यही चीज है कि हम बीमार न हों पहले इस बात की चिंता करें और बीमार हो जाएं तो कैसे ठीक हों, इस बारे में सोचें। इस बात का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। इसीलिए, जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे जो दैनिक खान-पान के तरीके हैं, यदि हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमें बीमारी से लड़ने में और अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ...(व्यवधान) आप मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दे दीजिए। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूं। मैं केवल दो लाइन बोलना चाहता हूं।

माननीय सभापति: आप मुझे लिखकर दे दीजिए।

डॉ. ढालसिंह बिसेन: कम से कम एक मिनट दे दीजिए। अनुसंधान के साथ-साथ जिस तरह से इस देश में चार धाम हैं, उसी प्रकार यदि देश के चारों कोनों में आयुर्वेद के प्रशिक्षण और अनुसंधान के केंद्र बनते हैं, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा।

आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली के लिए जब तक संस्कृत को सिलेबस में नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, वैसे ही संस्कृत की शिक्षा वाले व्यक्तियों को एडमिशन दिया जाए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमें सिलेबस में बच्चों को स्वस्थ व्रत के बारे में भी

पढ़ाना चाहिए। स्वस्थ कैसे रहें? यदि यह बात सिलेबस में अंकित हो जाएगी तथा हम मैट्रिक तक स्वस्थ व्रत के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें आगे के जीवन में स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairperson, Madam.

There is a vast network of Ayurveda healthcare delivery system in Kerala, and there is no doubt about it. In Kerala, every Panchayat has one Ayurveda dispensary; in every taluka we have a taluka hospital; and in every district we have a district hospital. So, Kerala has a wide network for Ayurvedic treatment. We are giving equal importance to Allopathy as well as Ayurveda. However, the problem is that the entire expenditure for dispensary, taluka hospital and district-level hospital is borne by the State Government. The National Health Mission should give financial assistance to the Ayurveda Health Centre, taluka hospital and district-level hospitals. We can improve infrastructure and other facilities of these hospitals. The problem being faced there is that sufficient number of buildings for it are not there; there is shortage of medicines; there is shortage of doctors; salary issue is there; and also shortage of paramedical staff.

If the Ministry of AYUSH, Government of India gives special consideration to Kerala and allots special assistance for improving the Ayurveda treatment there, then it will be very much helpful for the people of Kerala who are willing to have Ayurvedic treatment. The hon. Minister is very much aware about the Kerala Ayurvedic treatment as also Homoeo, Siddha and Unani.

There are so many super-speciality hospitals and medical colleges in private sector, and Government Ayurveda medical colleges are also there. Santhigiri Ashram is also running a hospital and college, and Mata Amritanandamayi Math is also running the Ayurveda college and hospital. Mr. M. K. Raghavan also just now mentioned about Kottakkal Arya Vaidyashala, which is a world-famous Ayurveda centre. These Centres should be upgraded as deemed Universities. This will be helpful for the Ayurveda sector, the students as well as patients who would get good treatment and good facilities.

Madam, I am concluding. I would urge upon the Government, through you, that fund constraint is a very big problem in Kerala. This year, NHM is not giving funds either for Ayurveda, Siddha, Unani or Homoeo.

I do not know what is the reason. Hence, I would request the hon. Minister to give an assurance that Ayurveda treatment and Ayurveda sector would be provided with sufficient funds for the construction of hospital buildings, development of infrastructure, etc. The Government of India should ensure that maximum assistance is extended to Kerala.

17.21 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): मैडम, धन्यवाद। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के लिए 2 से 3 लाख करोड़ रुपये का बजट मिनिस्ट्री का होना चाहिए था। Today, we see that we have become the victims of British policy, which destroyed our Indian culture. That is why, I would say that I am grateful to all the hon. Members from Kerala. केरल में आयुर्वेद के इंपोर्टेंस को मेंटेन किया हुआ है।

मैं अपने भाषण को माननीय सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी के भाषण से शुरू करता हूं। जब लक्ष्मण जी इंजर्ड हुए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी को ढूंढ़ने के लिए हिमालय में जाकर पर्वत को उठाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हिमालय में संजीवनी है। मैं माननीय मंत्री जी श्री श्रीपाद येसो नाईक जी को बताना चाहूंगा कि केरल में आयुर्वेद को बढ़ाया जा सकता है। रॉ मेटेरियल के लिए हमारे पास जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश है। आज एक ऐसा प्लान है Subject to correction, caterpillar in botanical language, *yarsa gumba* which cost Rs.2 or Rs.3 lakh in India but the same being black-marketed in South East Asia at Rs.40 or Rs.50 lakh. This plant, which is available in Arunachal Pradesh, is purchased; and when it reaches Burma and China, it costs Rs.60 lakh. यही संजीवनी है। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि I really appreciate traditional herbal medicines. I really appreciate Dr. Shashi Tharoor for speaking on research, development and documentation. These are necessary. आपने हमारी कांस्टिट्एंसी में आयुष बिल्डिंग बनाई है। अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आप आयुर्वेद को भी शामिल कीजिए। हम अरुणाचल प्रदेश में एक जंगल को काटकर और आग जलाकर खेती करते थे But power company has come to Arunachal Pradesh and now, they are replanting the trees which is important for cancer treatment. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पार्लियामेंट्री कांस्टिट्एंसी में एक लड़की है। She is M.Sc. Gold medallist, and B.Sc. in Agriculture. Today, she is practising four medicines. She is having patients from the USA, South Korea, France, Israel and Switzerland. हिन्दुस्तान में जिसको भी ब्लड कैंसर हुआ या लीवर कैंसर हुआ तो Blood Cancer and Liver Cancer are being treated and cured in Arunachal Pradesh. Hepatitis B in being cured by this medicine . Allergy, skin disease, epilepsy, kidney stones, and even HIV and blood Cancer are being treated by traditional

form of medicines in my constituency in Arunachal Pradesh. I think, it is high time the Government of India should look into it. We must go back to the origin. This Ministry should be allotted with huge amounts so that the future of India, the future of this country is safe and secured. Humanism depends on Ayurveda. With these words, I conclude.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, आयुर्वेद, जिसका 5000 साल पुराना इतिहास है, उसके बारे में बोलने का आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, एलोपैथी अगर एक बीमारी को ठीक करती है तो दो बीमारियां साथ में दे भी देती है। आज एलोपैथी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज थोड़ा स्लो है, लेकिन इफेक्टिव है और आम लोगों की पहुंच में है। जो ऐसे कदम सरकार उठा रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं 29 सितम्बर, 2019 को उनके आवास पर एक पत्र लेकर गया था और 50 बेड का होम्योपैथी का पंजाब का पहला हास्पिटल बनाने के बारे में इन्होंने मुझे आश्वासन दिया। उसके लिए पत्र व्यवहार सरकार के बीच चल रहा है। हमारे पास इनका ऑफर लेटर भी आ गया है। मैंने पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी से बात भी कर ली है। वहां एक ट्रस्ट है, जिसके पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, इन्होंने मुझे कहा कि पहले वहां 50 बेड का हास्पिटल बनेगा, उसके दो साल बाद कॉलेज और उसके बाद होम्योपैथी की पहली यूनिवर्सिटी वहां बनेगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, वह मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ मरीजों से मिलवाया, जो उनके इलाज से ठीक हो गए हैं। हमारी ऐसी जो जड़ी-बूटियों की पुरानी परम्परा है, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में भी हमें ऐसे आयुर्वेद का कोई संस्थान देंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, उस होम्योपैथी हास्पिटल के बारे में प्लीज जरूर बताइए।

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I support this Bill. Today, I feel privileged to stand here and speak as a Parliamentarian as my maternal grandfather, Dr. Kumaran, was also an Ayurvedic practitioner. We have rich cultural and traditional values in Ayurveda but what is lacking is that we do not have enough scientific documents and clinical trials and journals to take it to the next level where we can sell it to the westerners and also boost our economy through Ayurvedic medicine. I would urge upon this Government to take steps towards this to set up a separate unit where they only take care of establishing scientific data which can be proved so that Ayurveda can be taken to the next level. Also, I would request the hon. Minister to set up international centres of excellence, not only national centres of excellence, in Kottakkal, Kerala and also in Tamil Nadu.

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, Vanakkam. Thiruvalluvar has said in Tamil about Ayurveda medicine. “Mikunum Kuraiyinum Noi Seyyum Noolor Valimuthalaa Enniya moonru.” It means that the learned books count three with wind as first among the three of these; as anyone of the three prevail or fail it will cause a disease. Tirukkural explains clearly the basis of Ayurveda medicine that with an increase or decrease of any of the three factors, Vatham, Pitham and Kabham, thereby resulting in health issues. Not only Ayurveda Medicine, Siddha Medicine is promoted successfully in Tamil Nadu. Similar to Ayurveda, Siddha medicine should also be given an important place. There are several Medical Colleges in Tamil Nadu. Particularly in Karur the Medical College of Tamil Nadu Government is functioning successfully. This was opened recently. Even though there are space constraints in this College due to political reasons, I urge upon the Union Government to start a separate Department for Ayurveda with bed facilities in Karur Medical College.

HON. CHAIRPERSON: Sushri Jothimani, have you informed that you would speak in Tamil?

SUSHRI S. JOTHIMANI : Yes, Sir.

17.28 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

SUSHRI S. JOTHIMANI : There are departments of Ayurveda medicine in many Medical Colleges of Tamil Nadu. But in these medical colleges, there is

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

no place for manufacturing Ayurveda drugs or having bed facilities for providing treatment to patients. Wherever we have Departments for Ayurveda Medicine, we should create places specifically earmarked manufacturing Ayurveda drugs as well with additional bed facilities for patients getting Ayurveda treatment. Similarly, in all the newly opened Medical Colleges, particularly in Karur there should be separate departments for Siddha medicine and Ayurveda medicine. Thank you.

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम 34 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। यह खुशी की बात है कि जो भी सदस्य बोले हैं, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं, हम उन पर निश्चित तौर से विचार करेंगे।

आयुष मंत्रालय का अध्यादेश स्वास्थ्य योजना को आगे बढ़ाना, पारम्परिक पद्धति को विकसित करना, उसे बढ़ावा देना और प्रचारित करना है, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अस्वस्थ लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। आयुष बीमारियों को रोकने, उचित आहार और योग के अभ्यास के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य चिकित्सा पर लोगों की निर्भरता को कम करना और सामुदायिक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। किसी ने कहा है कि Ayurveda is science of life. यह प्रिवेंटिव भी है, प्रमोटिव भी है और क्योरेटिव भी है, इसलिए तीनों स्तर पर यह अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और अन्य पारम्परिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई

पहल की हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2014 को माननीय नरेन्द्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र में योगा के बारे में जो रेजोल्यूशन लाए और आज हम देख रहे हैं।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): आज हम आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं। यह योग का विषय नहीं है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : योग तो असली आयुर्वेद है। Yoga is a part of Ayurveda. जिस तरह से योग है, उसी के साथ-साथ आयुर्वेद भी आगे बढ़ रहा है। नेशनल आयुष मिशन के जरिये मैं हर डिस्ट्रिक्ट के सदस्य से आह्वान करता हूं कि इस आयुष मिशन के जरिये देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल सभी पैथी का, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी आदि होने चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 102 अस्पतालों का काम शुरू हो चुका है। जिन्होंने भी प्रपोजल भेजा है, उसका अप्रवल दे दिया है। अभी मान साहब बोल रहे थे कि पंजाब में भी 50 बैड का होम्योपैथी का अस्पताल बन रहा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस स्कीम द्वारा आपके डिस्ट्रिक्ट में आप यह अस्पताल मांगिए, जिससे कि हमारी सभी पैथी का प्रचार उस अस्पताल द्वारा हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वर्ष 2017 में दिल्ली के सरिता विहार में, बदरपुर के पास शुरू किया था और आज कम से कम वहां 2000 से ज्यादा पेशेंट ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं। हमारा 100 बैड का अस्पताल आठ-आठ दिन, दस-दस दिन फुल रहता है। कहने का मतलब है कि आज लोगों में आयुर्वेद के प्रति, आयुष के प्रति रुचि और दूसरी पैथियों के लिए भी बढ़ रही है।

प्रो. सौगत राय: क्या करोना के लिए भी इसमें कोई दवाई है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : हाँ, हमारे पास जो-जो भी था, हमने एडवाइजरी जारी कर दी है। मुझे कहने में खुशी है कि पहले कोई कम्पनी इंश्योरेंस में आयुष को शामिल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज कम से कम 27 बीमा कम्पनियों ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। आप आयुष में जो भी इलाज करेंगे, उसका भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा। गुणवत्तायुक्त आयुष शिक्षा मुहैया कराने का जो काम है, वह मुख्य व्यापक उद्देश्यों में से एक है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर

कुल 704 आयुष कालेज हमारे देश में हैं। उसमें आयुर्वेद के ज्यादा हैं। उसके बाद होम्योपैथी के हैं, फिर यूनानी के हैं, फिर सिद्धा के हैं, योगा और नेचुरल पैथी के भी हैं। इसमें से कम से कम 45 हजार स्नातकोत्तर आयुष व्यावसायिक शिक्षा हर साल प्राप्त करते हैं। मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य निकाय के रूप में 11 राष्ट्रीय स्तर पर आयुष संस्थान कार्य कर रहे हैं। इनमें से 11 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 संस्थानों में नभ एक्रिडिटेशन का काम चल रहा है।

इस गुणवत्ता को सख्त मानकों में कायम रखा जा सके, यह हमारा प्रयास है। जो हॉस्पिटल्स या कॉलेजेज होंगे, उनको नव एक्रिडटेशन लेना पड़ेगा, हमारी यह कोशिश चालू है। कई कॉलेजों ने नव एक्रिडटेशन का काम शुरू किया है। आईटीआरए बिल, 2020 में तीन संस्थानों, जैसे आयुर्वेद, स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, श्री गुलाब कुवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर की फार्मेसी इकाई सहित आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस संस्थान को पृथक करने तथा एक संस्थान अर्थात् आयुर्वेद प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) का गठन करने तथा उस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के स्वास्थ्यवृत्त विभाग में महर्षि पतंजलि योग और प्राकृतिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को मान्यता प्रदान करना भी प्रस्तावित है।

आईपीजीटीआरए के 10 विभागों में यह क्यों किया? माननीय शशि थरूर जी ने प्रश्न पूछा कि गुजरात ही क्यों, जामनगर ही क्यों? इस आईपीजीटीआरए के 10 विभागों में स्नातकोत्तर डिग्री 53 सीटों और 13 विशेषज्ञताओं के क्षेत्र में पीएचडी डिग्री 20 सीटें और आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए 6 सुस्थापित प्रयोगशालाएँ और आयुर्वेद में शिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग प्रदान करने के लिए 200 बिस्तरों वाला अस्पताल है। संस्थान की स्थापना आयुर्वेद में विश्व स्तर के अकादमीविदों, चिकित्साभ्यासियों और अनुसंधानकर्ताओं को दृष्टि में रखकर की गई है, ताकि यह आयुर्वेद संस्थान एक उच्च कोटि का संस्थान बने और आगे चलकर

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त करे। इस संस्थान का लक्ष्य प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के संरक्षक की भूमिका निभाते हुए शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा-उपचार और अनुसंधान के क्षेत्र में योग्य मानव संसाधन विकसित करना है। इस अभियान में भारत और पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रोत्साहन और प्रचार-प्रसार भी शामिल है। इस संस्थान में आईपीजीटीआरए को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग केन्द्र के रूप में नामांकित किया है, यह उसका एक पहलू है। डब्ल्यूएचओ ने अपने कार्यकलाप के भाग के रूप में यहां फार्माकोविजिलेंस एक प्रशिक्षण कार्याशाला भी आयोजित किया है। आईपीजीटीआरए ने अपने पांच वर्षों के इतिहास में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, आयुष औषधि में फार्माकोविजिलेंस पद्धति आरंभ करने वाला यह पहला संस्थान है। इस संस्थान में विभिन्न बीमारियों के लिए अनेक चिकित्सा प्रोटोकाल और चिकित्सा नियमावली को विकसित किया गया है। औसतन तीन-चार छात्रों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है। कम से कम 43 देशों से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं और मेरे ख्याल से सरकार उन पर खर्च करती है।

महोदय, दो व्यापक मुद्दों के बारे में सभी ने कहा है, जामनगर क्यों, केरल क्यों नहीं? आयुष को शुरू हुए यह छठा साल है। यह केवल शुरुआत है। एक-दो शुरू हो जाने के बाद हमें आगे काम करने में आसानी होगी। आपने कहा तिरुवनंतपुरम के इंस्टिट्यूशन के बारे में कहा है। Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram is also a premier Ayurveda Teaching Institution currently running under the State Government. As far as this institution is concerned, even though it is having graduate and post-graduate courses, wide range of collaborative research and professional network activities in academics are yet to be developed by this institute.

जब ये एक्टिविटीज आगे बढ़ेंगी, तो मैं कह सकता हूँ कि हम इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे देंगे। उसके बाद, जो भी प्रपोजल हैं, निश्चित रूप से उन पर विचार किया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक ही नहीं, इस देश में पाँच से दस विश्वविद्यालय हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार और इसकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें ज्यादा इंस्टिट्यूट्स की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब अगला नम्बर आएगा, तो निश्चित रूप से तिरुअनन्तपुरम का आएगा।

डॉ. शशि थरूर: वह आपकी मदद के बिना नहीं होगा।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : वह तो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे।

रिसर्च के बारे में आप लोगों ने कहा है, अभी चारों पैथीज के रिसर्च काउंसिल हैं, जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कई फॉर्मूले लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, मेडिसिन भी बन रहे हैं। चारों रिसर्च सेन्टर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। रिसर्च तो शुरू है, लेकिन इसे और तेज गति से करना चाहिए, जब इस इंस्टिट्यूट में भी रिसर्च का काम होगा, तो निश्चित रूप से उसमें मदद हो जाएगी।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय): माननीय सांसदगण का कायाकल्प करा दीजिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: कायाकल्प के लिए भी एक सिस्टम है। एक-एक करके हम आगे जाएंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सर, ये जो बाल उड़ता है, इसका कुछ उपाय है?...(व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: महोदय, सभी सांसदों ने जिस तरह से इस बिल को सपोर्ट किया है, मैं उनका तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो विचार प्रकट किए और उन्होंने हमें जो सूचनाएँ दी हैं, हम उन पर सही वक्त पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। जामनगर और बाकी जगहों पर रिसर्च सेन्टर क्यों नहीं हैं, मैंने उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं।

महाराष्ट्र के बारे में जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वे माननीय कोले साहब हों या माननीय विनायक राऊत जी हों, उन्होंने मेडिसिन इंस्टिट्यूट्स के बारे में जो सजेशंस दिए हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि कम-से-कम आज सभी पैथीज की काउंसिल्स के लिए बिल्डिंग़्ज़ की व्यवस्था हो, हरेक पैथी के नेशनल इंस्टिट्यूट हरेक स्टेट में हों, यह हमारा प्रयास है। जब ऐसे इंस्टिट्यूट्स बनेंगे, तभी इनका प्रचार-प्रसार होगा और इनका उपयोग रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छी तरह से होगा।

मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो विचार प्रकट किए हैं, जो सूचनाएँ दी हैं, हम उन पर निश्चित रूप से अमल करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए,...(व्यवधान)

महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय सुरेश जी और कई सदस्यों ने जो डिमांड किए हैं, जब हमें मौका मिलेगा, चाहे केरल में हो या बाकी स्थानों पर हो, जैसे ही हमारे पास फंड आएंगे, हमने किसी राज्य के साथ फंड के मामले में डिसक्रिमिनेशन नहीं किया है। हमारे पास जो भी फंड आए, हमने उनको वैसे ही राज्यों के पास पहुँचा दिए हैं। जब हमारे पास ज्यादा फंड आएंगे, हमारे मित्र ने डिमांड की है कि आयुष का जो बजट है, वह बहुत ही कम है। जब हमें ज्यादा बजट मिलेगा, तो हम ज्यादा फंड आपके राज्यों को रिलीज करेंगे।

अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में फोक मेडिसिन का हमने एक इंस्टिट्यूट स्थापित किया था। वहाँ की कठिनाइयों को सामने रखते हुए, माननीय सांसद श्री तापिर गाव जी ने माँग की है कि फोक मेडिसिन और आयुर्वेद को जॉइंट करके काम किया जाए। मैं इसके लिए उनको आश्वस्त करता हूँ कि आयुर्वेद और फोक मेडिसिन दोनों को मिलाकर हम इंस्टिट्यूट चलाएंगे।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): There should be an Ayurveda clinic in Parliament House.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: आयुर्वेद में सभी तरह की दवाएँ हैं। हमें थोड़ा मौका दीजिए, सभी तरह की दवाएँ हम देने की कोशिश करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक के पारित होने से चिकित्सा क्षेत्र में उत्तम मानव संसाधन एवं विकास एवं आयुर्वेद में उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से अवसर मिलेंगे।

मैं सभी माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने के लिए सहयोग और समर्थन करने का अनुरोध करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आयुर्वेद की जो मार्केट है, वह बहुत तगड़ी मार्केट है। ...(व्यवधान) यह मार्केट 30 हजार करोड़ रुपये की है और इसका ग्रोथ 16 परसेंट है। ...(व्यवधान) वर्ष 2022 तक आयुर्वेद मार्केट की टोटल नेट वर्थ 9.7 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। ...(व्यवधान) इसका मतलब फ्यूचर में आयुर्वेद मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। ...(व्यवधान) हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ...(व्यवधान) सबसे बड़ा मुद्दा रिसर्च का है। ...(व्यवधान) रिसर्च के लिए आपको पैसा नहीं मिलता है, यह आपने यहां कहा है, लेकिन पैसे के बिना तो रिसर्च नहीं हो सकता कि पैसा नहीं है, इसलिए रिसर्च नहीं होगा। ...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद के लिए प्योर-हर्ब चाहिए, लेकिन आजकल उसमें बहुत आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए, हर्ब का रख-रखाव करने के लिए जो बोर्ड है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अधीर रंजन जी, आप इधर देखकर बात कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं और एक बात कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो हमारे सामने आ रही हैं, वे क्वॉलिटी एंड स्टैन्डर्ड ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन हैं।

सर, मैं दो-तीन मिनट में नहीं, दो-तीन शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरी बात यह है कि इसके लिए नैसिसरी रिसर्च गाइडलाइन नहीं है, कोई क्लीनिकल एप्लीकेशन नहीं है। क्लीनिकल एप्लीकेशन नहीं होने से एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं होती है। …(व्यवधान) सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप रिसर्च करते हैं, लेकिन रजिस्ट्री के क्लीनिकल ट्रायल्स आपके पास नहीं हैं। रजिस्ट्री के क्लीनिकल ट्रायल्स आपके पास होने चाहिए। आपको आम लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

सर, हिन्दुस्तान में 77 फीसदी लोग आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको सारी जानकारी नहीं है। …(व्यवधान) इनको मैरिट्स और डीमैरिट्स की जानकारी नहीं है। आप सबको धड़ल्ले से आयुर्वेद का कारोबार करने का मौका देते हैं, न कोई फीस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई लाईसेंस है, जिसकी मर्जी, धड़ल्ले से कारोबार करते जाओ।

आयुर्वेद हॉस्पिटल्स और मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्स से जो डॉक्टर्स निकलते हैं, उनको नौकरी कहां मिलती है? जिस दूर-दराज गांव में एलोपैथी डॉक्टर नहीं है, वहां आप आयुर्वेद डॉक्टर को इस्तेमाल करते हैं। …(व्यवधान) आप जब तक आयुर्वेद डॉक्टर को एलोपैथी डॉक्टर की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आयुर्वेद पढ़ने के लिए आम बच्चों और युवाओं में दिलचस्पी नहीं आएगी। …(व्यवधान)

सर, मैं ये सारी बातें कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) मैं एकदम लास्ट में रिडन्डेन्ट टीचिंग प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूं -

The Continuing Medical Education (CME) programmes being conducted by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth are the only faculty development programmes formally available in the field of Ayurveda at present. The programmes suffer from redundancy and repetition of material. There is no enough emphasis laid upon instructional methods that are innovative in nature, the examination and evaluation skills are criticised as obsolete, and the research methods and research ethics need to be more thorough and have to adjust to the needs of the present day. The way forward in order to help the practice of Ayurveda in the long-term would be to also try unconventional methods in the field, as a result of changing needs of the society, and not wholly relying on traditional methods.

सर, भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी थे। …(व्यवधान) समुद्र मंथन करते हुए उन्होंने जो शक्ति उगली थी, उसी से आयुर्वेद पैदा हुआ। आयुर्वेद का अर्थ है – जिसमें आयु का ज्ञान होता है। आप ज्यादा ज्ञान लीजिए, आपको भी तन्दुरुस्ती की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आयुर्वेद मिनिस्ट्री, दूसरी तरफ आर्मी, आप कैसे संभालेंगे? इसलिए आप ज्यादातर आयुर्वेद दवा इस्तेमाल करते रहिए। मैं आपका समर्थन करता हूं।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अधीर रंजन जी, थैंक-यू।

अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि कांग्रेस पार्टी ने यहां अपने सुझाव रखे हैं। हमारी जो एपेक्स रिसर्च काउंसिल्स हैं, वे हर रोज़ अपना रिसर्च का काम करती हैं। कम से कम आयुर्वेद में ही हमारी मेन 35 एपेक्स बॉडीज़ हैं, बाकी रिसर्च की 31 बेंचेज़ हैं। इन काउंसिल्स के रिसर्च केसेज़ मेरे

ख्याल से पीरियॉडिक जनरल में पब्लिश भी होते हैं। यह काम शुरू हो चुका है। आज जो नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, उनमें भी जब रिसर्च होगा तो उनमें भी निश्चित तौर पर मदद करेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि जैसे, हमारे डॉक्टर्स हैं, मैने जैसा, कहा कि 45 हजार डॉक्टर्स हर साल पढ़ाई करके बाहर आते हैं। आज नेशनल हैल्थ मिशन में हमारे आयुष के डॉक्टर्स अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वे आयुष मिशन में काम कर रहे हैं और नेशनल हैल्थ मिशन में भी काम कर रहे हैं। इसी तरह से हर सेंटर पर हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और पैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और उसे आयुर्वेद और सहबद्ध शाखाओं शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

Clause 2 Declaration of Institute of Teaching and Research in Ayurveda as an Institution of national importance

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 3 Definitions

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Though the hon. Minister has given the assurance, I am still moving this amendment to caution him. Sir, I beg to move:

Page 2, line 9,--

after "Pharmaceutical Sciences, Jamnagar"

insert *"*and the Regional Ayurveda Research Institute for Life Style Related Disorders, Thiruvananthapuram". (2)

Page 2, *after* line 32,--

insert *'*(*ka*) "Regional Ayurveda Research Institute for Life Style Related Disorders, Thiruvananthapuram" means Regional Ayurveda Research Institute for Life Style related Disorders (RARILSD), unit under the Council for Research in Ayurveda Sciences functioning at Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala'. (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Establishment and incorporation of Anteceding Institution as Institute of Teaching and Research in Ayurvdea

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is the same amendment. Sir, I beg to move:

Page 2, line 41,--

after "Pharmaceutical Sciences, Jamnagar"

insert "Pharmaceutical Sciences, Jamnagar and Regional Ayurveda Research Institute for Life Style Related Disorders, Thiruvananthapuram". (4)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Effect of incorporation of Anteceding Institutions as Institute of Teaching and Research in Ayurveda

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am seeking two minutes' time just to explain this amendment. This amendment is regarding those who are employed in the institute. What is the fate of those employees? As per the new provision, they will be enjoying all the benefits. They will continue in service. It says, 'unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by regulations'. That means, if it is altered by regulation, he has to go out. It is totally, anti-labour, and unfriendly with the existing staff. Kindly accept this amendment. I hope, Saugata Roy ji has also moved the same amendment. Amendment Nos 5,6 and 7 relate to this problem of the existing staff. Their benefits shall never be curtailed by means of having a new institute. That is my amendment.

Sir, I beg to move:

Page 3, lines 17 and 18,--

omit "unless and until his employment is terminated or until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by regulations". (5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 3, *omit* lines 19 to 24. (6)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

Page 3, line 26, -

after "Jamnagar"

insert "and the Deputy Director (General), Regional Ayurveda Research Institute for Life Style related Disorders, Thiruvananthapuram". (7)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

Page 3, *for* lines 16 to 18, -

substitute "as are available to persons of similar rank or position employed in the All India Institute of Medical Sciences:". (10)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Composition of Institute

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving Amendment no. 8, that is, after "Gujarat", insert "Kerala". I beg to move:

Page 3, line 46, -

after "Gujarat"

insert "and Secretary, Department of Health, Government of Kerala". (8)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 11 से 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Hon. Speaker, Sir, just give me one minute. I would like to say something. I was disappointed to find that the Institute of Ayurveda was set-up in Gujarat instead of West Bengal or in Kerala.

West Bengal has a great tradition of Ayurveda. So, at least, in the composition of this Institute at Jamnagar, the Secretary of Department of Health from West Bengal should be included. I also want that after "three Members of Parliament", you should insert "belonging to the States where Ayurvedic institutions are prominent".

I beg to move:

Page 3, *for* line 46, -

substitute "(c) four Secretary, Department of Health, from different States like West Bengal, Kerala, Karnataka and Gujarat where Ayurvedic institutions are prominent, *ex-officio*;

the Secretaries, Department of AYUSH of four States, where Ayurvedic Institutions are prominent like West Bengal, Kerala, Karnataka and Gujarat, *ex-officio*".

(11)

Page 3, *for* lines 48 and 49, -

substitute "(e) the technical head of Ayurveda, not below the level of Superintendent of Ayurveda Hospital having masters degree in Pharma (Ayurveda), ex-officio;".

(12)

Page 4, line 8, -

after "there experts in Ayurveda,"

insert "belonging to the States of West Bengal, Kerala and Gujarat,". (13)

Page 4, line 10, -

after "three Members of Parliament,"

insert "belonging to the States where Ayurvedic institutions are prominent". (14)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 10 Governing Body and other Committees of Institute

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I am moving Amendment no. 9, that is, after "Jamnagar", insert "Thiruvananthapuram".

I beg to move:

Page 5, line 20, -

after	"Jamnagar"
insert	"and Deputy Director (General), Regional Ayurveda Research Institute for Life Style related Disorders, Thiruvananthapuram". (9)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बनेा"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 31 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1 Short title and commencement

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्नील, क्या आप संशोधन 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I have only one amendment. Hon. Minister, kindly accept the same. It is a very small amendment. Instead of "Institute of Teaching and Research in Ayurveda", I am amending it as "Institute of Research and Development in Ayurveda". It is a very small amendment. Kindly accept it.

I beg to move:

Page 1, line 5, -

for "Institute of Teaching and Research in Ayurveda"

substitute "Institute of Research and Development in Ayurveda". (1)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: I beg to move:

"That the Bill be passed".

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अगर सदन की सहमति हो तो अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर आपके आग्रह पर सदन 7 बजकर 30 मिनट तक बढ़ाया जाए? सभी माननीय सदस्य अपनी विषय वस्तु को संक्षेप में एक मिनट के भीतर रखने का प्रयास करें।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

18.00 hrs

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में मिंट है, जहां कॉइन बनते हैं। उस टक्साल के इम्प्लाईज़ की एक गृह निर्माण संस्था है, जहां टक्साल की कॉलोनी है, उस कॉलोनी में टक्साल के कर्मचारी रहते हैं। पहले उसमें तीन बिल्डिंग्स बनी थीं, बाद में वर्ष 1990 में और आठ बिल्डिंग्स बनीं और कुल मिलाकर 11 बिल्डिंग्स हो गयीं। ये 11 बिल्डिंग्स वर्ष 1990 में बनी थीं। अभी नई बनी इन बिल्डिंग्स की मरम्मत के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। लेकिन पिछले हफ्ते में मेनेजमेंट ने नोटिस दे दिया कि बिल्डिंग्स कमजोर हैं, लोग उनमें रह नहीं सकते हैं, आप लोग वकेट करो। उसके पहले उन्होंने कहा था कि हम जिम्मेवारी लेते हैं और लोगों को मकान देने की कोशिश करते हैं। वे उपलब्ध नहीं हो पाए और अब उनको कह रहे हैं कि आप अपने लिए स्वयं मकान की कोशिश कीजिए। आपको भी बुरा लगा कि मैंने खुद उस जीएम को फोन करने का प्रयास यहां से किया। वह फोन नहीं उठाते हैं। मैंने सिक्योरिटी से बात की कि मुझे बात करनी है। उनको समझाओ कि अभी कोरोना चल रहा है, वेकेशन की नोटिस न दें। आपने 12 करोड़ खर्च किए हैं तो बिल्डिंग मजबूत कैसे नहीं हुई? क्या आप सभी लोगों को रास्ते पर लेकर आएंगे? वहां करीब 214 परिवार के 600 लोग रहते हैं। अगर आप सारी बिल्डिंग्स खाली करवा लेंगे तो लोग कहां जाएंगे? यह मिंट सरकार की कम्पनी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से निवेदन है कि ये बिल्डिंग्स इतनी कमजोर नहीं हैं। इनका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया है या नहीं, यह मालूम नहीं है। लेकिन लोग रास्ते पर आ जाएंगे, इसके लिए आप इंटरवेंशन कीजिए। वर्ष 2018 में 12-15 करोड़ रुपये खर्च किए गए, उसके बाद अब बिल्डिंग्स खाली करवा रहे हैं। आप इसकी जांच कीजिए, इतनी ही मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।

मैं आपके माध्यम से भूतल परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हो रहे चहुंमुखी विकास के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रयासों से जो विकास कार्य चल रहा है, वह ऐतिहासिक है। भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या से तपो स्थली चित्रकूट तक फोर लेन सड़क निर्माण की घोषणा हुई थी, जिसे मेरे आग्रह पर सतना माँ शारदा की पवित्र पीठ मैहर तक बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति भी हुई थी, किन्तु कार्य का डीपीआर अभी तक नहीं बनाया गया है। इसी तरह दो राज्यों को जोड़ने वाली पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्र से होते हुए सतना, सेमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, इलाहाबाद की सड़क के निर्माण का प्रस्ताव जिस पर सैद्धांतिक सहमति हो चुकी थी, उसका भी डीपीआर अभी तक तैयार नहीं किया गया है। आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि अगर इन सड़कों की मॉनीटरिंग पूरी हो गयी हो तो तत्काल डीपीआर के आदेश दिए जाएं।

इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 नौगांव, छतरपुर, पन्ना, सतना, बेला, सीधी, सिंगरौली इन सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है। नागौद, जसो, पवई, दमोह सड़क के भी निर्माण का कार्य अधूरा है। इन दोनों सड़कों के कार्य को तत्काल पूरा किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Hon. Speaker, Sir, I am very sorry to tell that 600 people are stranded in Iran and 6000 people are crying for them in Kanyakumari. The children are expecting their fathers to come back and brothers are expecting to see their brothers. The situation is worse. Their

request is that if it is possible, you can bring them back through boats or ships to Kanyakumari. In Kanyakumari, people are totally upset.

Sir, I would request you to tell our Government to bring them back by boats or ships to Kanyakumari. It is my humble request on behalf of fishermen of Kanyakumari.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बेमौसम बरसात की ओर ले जाना चाहती हूं। देश के कई हिस्सों में 13 से 15 मार्च के बीच वर्षा और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तीन दिन की ओलावृष्टि ने रबी फसल के साथ-साथ सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तूफान की वजह से कई जगह बिजली के पोल एवं तार भी क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोगों के मकान ध्वस्त हो गए।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा सहित संपूर्ण झारखंड में हुए फसलों के नुकसान तथा अन्य क्षति का आकलन करने के लिए वहां पर एक केन्द्रीय दल भेजा जाए और अविलंब मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): In the words of Radhanatha Ray

"Swarupa Anshupa loke agochara
Pujyaspada hela gospada Pushkara"

It means

The naturally formed lake Anshupa remains unknown & invisible while lake Pushkar formed by cow-hooves garners all the fame & reverence.

Anshupa is a sweet-water lake situated on the banks of river Mahanadi & gets inundated by Mahanadi water only. The lake has an area of five thousand acres. It was covered entirely with aquatic weeds. With the support of Work Bank Rs. two crores & thirty lakhs were spent to clear the weeds. Being the largest sweet-water lake it attracts a lot of migratory birds. Fishing activities are taking place too, giving a boost to the income of nearby panchayat residents. Government has taken up many developmental activities in the area too.

Sir, through you I'd like to request the Government to accord appropriate status to the Anshupa lake as per the Ramsar Convention. This will pave way for more central financial assistance as well as aid from abroad. This will increase the inflow of tourists to the place & it can become a major tourist attraction & garner revenue.

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, आज आप सभी अनुशासन का पालन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

…(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आधार कार्ड केन्द्रों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आधार कार्ड केन्द्रों में समस्त आधार कार्डों में जो परिवर्तन होते हैं, या कोई संशोधन होता है, उसके लिए आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कराना होता है, तभी वह हो सकता है। अभी राजस्थान में चने और सरसों की खरीद हो रही है, तो किसानों को आधार कार्ड के माध्यम से मोबाइल पर ओटीपी भेजा जा रहा है। लेकिन वहां पर काफी किसानों के मोबाइल नंबर्स आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं और वे उसको लिंक कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहां पर उसके केन्द्र नहीं है। राजस्थान के करीबन 35 केन्द्रों के आवेदन पिछले छः महीने से केन्द्र के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन केन्द्रों की स्वीकृति जल्दी हो सके, ताकि किसानों के फोन में ओटीपी आ सके और वे अपना माल सरकार को बेच सकें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी. पी. जोशी को श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important matter during the Zero Hour.

Viral diseases are very much prevalent in the State of Kerala. This may be attributed to a number of reasons. We have a large population of migrants in the State. Several Keralites work in other countries. Frequent travelling

between different places can lead to exposure to different viruses and thereby causing virus-related diseases. In a State like Kerala which is densely populated viral diseases have a greater tendency to spread. For doing all the viral disease related tests, earlier we were dependent on the Pune-Manipal Virology Institute. The Alappuzha Virology Institute was set up in the State of Kerala with the assistance from the Central Government. When there was the NIPA virus outbreak in Kerala, the suspected blood samples were tested there and now the blood samples of people affected by the Corona virus is also being tested there. But the issue is that after the blood samples are tested in Alappuzha Virology Institute, they are being sent to Pune-Manipal Virology Institute for re-confirmation. This is causing a lot of delay for starting the treatment of the affected people.

So, I would like to request the Central Government to upgrade the Alappuzha Virology Institute to the standard of the Pune-Manipal Virology Institute. The Central Government should allot a minimum of Rs. 10 crore at the earliest for improvement of the infrastructure of this Institute, particularly given the Covid-19 scenario.

Sir, the other point is that more than 500 Keralites are stranded in countries like Malaysia, Philippines and Italy. The State Government has requested the Central Government for ensuring safe return of these people. I would like to request the hon. Prime Minister and also the Ministry of External

Affairs to intervene in the matter to ensure safe return of these people to our country at the earliest. Thank you.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अति महत्वपूर्ण व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्री के माध्यम से प्रत्येक सांसद को 10 छात्रों का प्रवेश केन्द्रीय विद्यालयों में कराने हेतु अधिकृत किया है। जबकि एक-एक सांसद के पास पांच से ले कर दस विधान सभाओं का क्षेत्र है। मेरे पास दो हजार फार्म्स आए हैं। ऐसे ही सभी सांसदों के पास आए होंगे। ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में कम से कम तीस छात्रों का प्रवेश दिलाने के लिए अधिकृत किया जाए या इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, जिससे कम से कम हमें दिक्कत तो न आए।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, श्री सी.पी. जोशी, श्री अजय कुमार, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्रीमती जयकौर मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में ओबीसी छात्रों को 27 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलने की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा हर राज्य में अलग-अलग है और स्टेट कोटा में आरक्षण तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसलिए केन्द्र कैसे हस्तक्षेप करे, यह सवाल उठता है। यहां मैं कहना चाहती हूँ कि 31 जनवरी, 2007 के पहले एस.सी. एवं एस.टी. के छात्रों के सामने भी यही समस्या थी। लेकिन उस वक्त सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया था और उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय स्तर पर 22.5 प्रतिशत का आरक्षण हमारे एस.सी. एवं एस.टी. के छात्रों को मेडिकल के प्रवेश में दिया जाए, ऐसा सुनिश्चित किया था। इसी तर्ज़ पर सरकार ओबीसी के लिए भी कोर्ट में एक याचिका दायर कर ऐसी व्यवस्था करे कि अखिल भारतीय स्तर पर 27 प्रतिशत का जो आरक्षण

है, वह एमबीबीएस और पीजी की सीटों में ओबीसी छात्रों को दिया जाए, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा न होने की स्थिति में हर अकेडमिक सेशन में ओबीसी के छात्रों को एमबीबीएस और पीजी में तीन हजार से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरंत कोर्ट में इस बाबत एक याचिका दायर कर ओबीसी छात्रों के हितों की रक्षा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह, श्री देवजी एम. पटेल, श्री मलूक नागर एवं श्री उदय प्रताप सिंह को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): My Parliamentary constituency, Karur, is known for its handloom, textiles, mosquito net and bus body building industries. We are the fourth largest exporter in the country. These industries employ around two lakh people. Importantly, 80 per cent of them are women, but ESI hospital in Karur is very small with minimum facilities. It needs to be upgraded to a multi-speciality hospital to cater to the needs of the employees. With full hope, we request the hon. Minister to respond to us positively in this regard.

Apart from that, many Tamil students across the world are stranded. These are more than 500 students. The colleges and schools are closed. I urge upon the External Affairs Ministry, through you, to take necessary steps to bring back the Tamil Nadu students.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you hon. Speaker Sir for allowing me to speak. I would like to bring to the attention of the House a serious issue concerning differently abled people. The GST tax on

wheelchairs, on braille paper and a lot of implements that differently people use is at five per cent. Now, in keeping with global standards, I really request the Government to remove this because for people who cannot walk, this is like a tax on walking. When this had happened and when this had been brought up in the GST Council in 2017, the then Revenue Secretary had said that they will be able to claim input tax credit and wheelchair prices will come down. But now we see in the past three years that wheelchair prices have not come down. So, you could please tell the Government to revisit this and to remove the five per cent GST on wheelchairs, braille paper and implements for differently abled people.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय को सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल नष्ट होती है और तुरंत सरकार उन्हें मुआवज़ा दिला देती है। प्राकृतिक आपदा तो समय-समय पर आती रहती है। हाल ही में ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से भी बहुत सारी फसलें नष्ट हुई हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार तुरंत उनके बैंक खाते में राशि जमा कर देती है। लेकिन मुझे मथुरा में यह पता चला कि वहां के किसान बहुत ही उदास थे और कहने लगे कि हमें तो मुआवज़ा नहीं मिलता है।

इसके बारे में मैंने पता किया। जो छोटे किसान हैं, वे बड़े किसान, जो उस खेत का मालिक है, उनसे पट्टे पर खेती लेते हैं और साल भर मेहनत करते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करके उस खेत में काम करते हैं। लेकिन फसल नष्ट होने पर जब मुआवजा मिलता है, तो उन गरीब किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है। इसके लिए मुझे लगा कि जैसे मकान का मालिक किरायेदार के

साथ एग्रीमेंट करता है, उसी तरह अगर बड़े किसान छोटे किसान के साथ, जो पट्टे पर लेते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट का प्रबंध हो जाए, तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उससे उनको फायदा मिल सकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना है कि हर किसान बहुत खुशहाली का जीवन बिताए। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी जो सपना है, तो वह सफल हो सकता है और हमारे किसान बहुत खुश हो सकते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आज तो आपने बहुत शुद्ध हिन्दी बोली।

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु – उपस्थित नहीं।

श्री राम शिरोमणि।

श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती-बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इन जिलों में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी विकास कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता है। यहाँ के गरीब व किसान के बच्चे आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, टेलीफोन, विद्युत, सड़क आदि से वंचित हैं। नेपाल बार्डर से सटे हुए सुदूर तराई इलाकों व वनों में थारू जनजाति रहती है, जो अभी भी विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाई है।

महोदय, इस क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कॉलेज न होने के कारण यहाँ के मरीजों को अपने इलाज हेतू लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे इनकी माली हालत पर असर तो पड़ता ही है, साथ-साथ अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस क्षेत्र के किसानों को अपने फसल की सिंचाई के लिए सरकार की किसी भी योजना का लाभ तक नहीं मिलता है। किसानों को समय पर न ही गन्ने की पर्ची मिल पा रही है, जिससे किसान अपने

गन्ने की बिक्री नहीं कर पाते हैं तथा अभी हाल में ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। उसका मुआवजा दिया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता व किसानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कोई विशेष अनुदान राशि आवंटित की जाए। ये दोनों जिले आकांक्षी जिले की श्रेणी में भी आते हैं। धन्यवाद।

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस की वजह से आज सिर्फ देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर जितने भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, सब लोगों से सरकार ने कहा कि सारे धंधे-दुकानें बंद कर दो, तो बंद कर दिए गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स बंद कर दिए गए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक सरकारी बैंक ने कितना इनसेंसेटिव डिसीजन लिया है और मैं चाहूँगा कि उस डिसिजन का सभी लोगों को निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंक है और उसने पूरी ब्रांचेज़ को एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी करके यह कहा है कि देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, तो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उसके अंदर बेचो। देखिए, उसमें क्या लिखा है-

> "Looking at the risk of pandemic "COVID 19", awareness and demand of Health Insurance have increased. This is the time to use this as business opportunity and help our customers by offering suitable Health Insurance Products."

यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंक है, जहाँ एक तरफ हम दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि अपना कारोबार बंद करो, बल्कि यहां तक कहा है कि इस पीरियड के अंदर स्पेशल ड्राइव चलाओ कि कोरोना वायरस की वजह से जितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं, बेचो और जो सबसे

ज्यादा बेचेगा, उसको तीन लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। उस बैंक की ब्रांच का जो एप्रेजल रहेगा, वह इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि इस तरह के बैंक, जो इस मौके के ऊपर अपना धंधा-कारोबार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री सैयद इम्तियाज़ जलील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अब्दुल खालेक – उपस्थित नहीं।

श्री गुरजीत सिंह औजला।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): स्पीकर सर, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान जो बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए गए, उनकी तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, अमरीका में जो इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वहाँ बिल्कुल उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, हाउस अरेस्ट कर दिया है।

एक तो हमारी एम्बेसी उनके साथ तालमेल करे, क्योंकि अगर उन्हें कोई इलाज भी कराना होता है, तो इलाज बहुत महँगा है। वे फर्स्ट सिटिजन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, उन्हें कम तवज्जो देते हैं।

दूसरा, उनका कारोबार भी बिल्कुल खत्म हो गया है। जो वहाँ की सरकारें हैं, जो उनके अपने सिटिजन हैं, उन्हें तो वे कुछ न कुछ आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन वहाँ इनका कोई काम नहीं बचा है। जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, जिन्होंने जन्म वहाँ लिया है, उनके माँ-बाप इंडिया के हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। जिन्होंने जन्म लिया है, जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, वहाँ का जन्म है, वहाँ की नागरिकता है, अब इन सबके इंडिया आने के लिए सरकार प्रावधान करे, क्योंकि उनके माँ-बाप यहाँ हैं, उनके पासपोर्ट्स इंडियन हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से गुजारिश है कि सबको इंडिया आने की इजाजत दी जाए, ओसीआई कार्ड होल्डर और जो बच्चे वहाँ के नागरिक हैं। धन्यवाद।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

मान्यवर, जब चुनाव चल रहा था तब हमने अपने क्षेत्र की दशा देखी थी। हमारा क्षेत्र गंगा के किनारे है, बहुत लंबी दूरी गंगा के तट पर स्थित है। हर बार जब बरसात होती है, बाढ़ से बहुत से गाँव पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं। बाढ़ का पानी गाँवों में आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है। हर बार उनका घर बदलना, स्कूल बदलना, शिक्षा, खाना, स्वास्थ्य आदि सब अस्त-व्यस्त हो जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वहाँ पर बरसात से पहले पत्थर की ठुकाई हो जाए, ताकि इस बार बरसात आने से पहले उन लोगों को सुविधाएं मिल सकें। माननीय मंत्री जी को कहीं से रिपोर्ट दी गई, जिसके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं कि वहाँ पर 91 किलोमीटर काम हो चुका है, 6 जगह सहायता केन्द्र बनाए गए हैं। जबकि मैंने वहाँ पर जाकर देखा है और अधिकारियों से भी हमने पूछा तो कोई भी कार्य वहाँ नहीं हुआ है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार उसकी पुन: जाँच करवाकर वहाँ पर कार्य कराने का कष्ट करें ताकि हमारी सरकार की जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की मंशा है, उस विश्वास के तहत बदायूं की जनता भी विश्वास से जुड़ते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को डॉ. संघमित्रा मौर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, कोरोना वायरस की वजह से सारे मुल्क में एक इमरजेंसी का माहौल है। जम्मू-कश्मीर से कोई 400 के करीब डिटेनीज़ हमारी मुख्तलिफ़ जेलों में बंद हैं। वे अम्बेडकर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, अम्बाला, संगरूर आदि में हैं। मेरी गुजारिश होगी कि उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, उनको रिवोक किया जाए। उनके वालदेन आकर उनसे मिल नहीं पाते हैं। अब चूंकि ट्रैफिक पर पाबंदी लगी है, तो अब उनको और भी मुश्किलात हो जाएगी उनसे मिलने के लिए, तो उनका डिटेंशन रिवोक किया जाए। जब तक वह रिवोक किया जाए तब तक उनको शिफ्ट किया जाए ताकि उनके रिश्तेदार और वालदेन आदि उनसे मिल सकें।

सर, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, वे तिहाड़ जेल और अन्य जगहों पर हैं। एक मेरी यह गुजारिश होगी कि 4जी चालू किया जाए, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी टूल सबसे बड़ा टूल है और अगर कश्मीर में वह टूल अवलेबल नहीं होगा तो यह मुतास्सिर होगा कि इस वायरस के खिलाफ जो हमारी जंग है।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): सर, मैं विदेश मंत्रालय की आभारी हूँ कि महाराष्ट्र के जिन-जिन बच्चों को दिक्कत हुई, वे उनको बड़ी हेल्प कर रहे हैं। दो-तीन चीजों के बारे में सरकार सोचे कि आज महाराष्ट्र में, अगर आप उदाहरण के तौर पर पूना डिस्ट्रिक्ट को लें तो वहाँ दुकानें, कॉलेज, ऑलमोस्ट पूरा शहर बंद होने को आया है। पहले भी इस देश में इकोनॉमी में दिक्कत है, सरकार ध्यान रखे कि आगे हम सबको, यह इमरजेंसी की जो स्थिति हो चुकी है, उसके आगे की भी प्लानिंग करे, क्योंकि पहले ही देश अड़चन में है। महाराष्ट्र की बहुत सारी पेमेंट्स केन्द्र सरकार में अटकी हुई हैं। जीएसटी का 15 हजार करोड़ रूपया पेन्डिंग है। हम सबको सोचकर थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, because it is a global crisis of the economy slowing down due to other reasons and now due to Covid-19. So, I urge the hon. Finance Minister and the External Affairs Minister to address all these issues. We are willing to work with the Central Government. We all must address these issues

together because these are going to be serious challenges before every State and the country.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to a matter of urgent pubic importance.

Odisha is a connectivity deficit State with overall tele-density of approximately 79.58 per cent and rural tele-density of approximately 61.60 per cent as against the national average, which is 81 per cent. About 10,000 villages are still not connected by wireless network in the State. A large number of unconnected villages come under the Left Wing Extremists area, which also include my Parliamentary Constituency where 153 villages are yet to be connected, and those villages, which are connected with wireless, only have 2G rather than 4G connectivity.

Under the Universal Services Obligation Fund, LWE-Phase II, the Central Government has approved installation of 158 towers only although the State Government had sent a list of 866 towers.

Hence, I would request the hon. Minister of Communications to kindly expedite the above project for augmenting mobile connectivity to bridge the digital divide in the State. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Hon. Speaker, Sir, I would to bring to the kind notice of the hon. Sports Minister that I represent Araku Parliamentary Constituency, which is a reserved Constituency in Andhra Pradesh. A majority of the people there belongs to the tribal community. Due to natural factors, there is a lot of potential for promising sportspersons in my Constituency, especially young school children and youth. However, there is no adequate training facilities especially, stadiums to practise.

In this regard, I would like to request the hon. Sports Minister to kindly sanction enough funds to our State Government of Andhra Pradesh so that good quality infrastructure can be created in the form of better stadiums for use of aspiring sportspersons in my Constituency. Thank you.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): सर, आज पूरे देश में अभी आठ बजे माननीय प्रधान मंत्री जी जनता के नाम संबोधन करने वाले हैं। सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, यह हम सब लोग जानते हैं। लेकिन, व्हाट्सएप्प के माध्यम से कई बार लोगों में भय भी फैलाया जाता है। आज ही मैंने अपने शहर सूरत के पुलिस कमिश्नर से बात की है क्योंकि ऐसे मैसेज वायरल हो रहे थे कि आठ बजे के बाद पूरा शटडाउन हो जाएगा। उसी का खंडन करते हुए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है।

गुजरात सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आज तक गुजरात में एक भी इसका केस नहीं है। सूरत कॉर्पोरेशन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। गुजरात सरकार ने तो बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया है, जिससे बच्चे पढ़ पाएं।

कई ऐसे देश हैं जहां पर फ्लाइट में बैठने के बाद लोगों को उतारा गया है, जैसे अगर इटली में कोई हनीमून कपल घूमने गया, कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने गया। पोलैंड और फिलीपीन्स के

बच्चों की सुबह ही बात हो चुकी है। वहां से निकल कर वे क्वालालम्पुर तक आ गए हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो लोग जहां पर हैं, वहीं पर रहें और उनका अच्छा बंदोबस्त हो जाए। अभी जो एडवाइजरी जारी हुई है, उसके अनुसार कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में नहीं आ सकेगी। इसलिए जो लोग जहां पर हैं, वहां उनकी सुरक्षा रहे। चौदह दिनों के बाद, जब माहौल अच्छा हो जाएगा, तभी उन्हें भारत लाने की व्यवस्था की जाए। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने किसानों की पीड़ा यहां रखने का मुझे समय दिया, आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र भिंड में चार विधान सभा क्षेत्र हैं। 29.02.2020 और 06.03.2020 ऐसे दिन थे, जिस दिन किसान पूरे खुशहाल थे। वहां पर सरसों और गेहूं की खेती इतनी अच्छी हो रही थी कि वहां के किसान सपने संजोकर रख रहे थे कि इस बार हम बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज पाएंगे, बिटिया की शादी करेंगे और जो कर्ज है, उसे भी चुका देंगे, लेकिन दो दिनों तक वहां इतनी बारिश हुई और केवल बारिश ही नहीं, वहां पर सूखे ओले पड़े। उस ओले से पूरा क्षेत्र, चाहे वहां की गोहद विधान सभा हो, चाहे मेहगांव हो, चाहे अटेर हो, चाहे भिंड हो, चारों विधान सभा क्षेत्रों के किसानों को भारी नुकसान हुआ। मैंने भी 7 तारीख से लगातार चार दिनों तक वहां का दौरा किया। वहां का प्रशासन भी मेरे साथ था। प्रशासन ने भी यह माना कि वहां पर सरसों और गेहूं की 100 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। कहीं-कहीं पर चने की खेती का भी नुकसान हुआ है।

वास्तव में मेरे पास जो आकलन आया है, उसके अनुसार ओलावृष्टि से 55,249 हेक्टेयर कुल रकबा किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूँ और सरसों के फसल का 100

प्रतिशत नुकसान हुआ है। हमारे जो किसान भाई-बहन हैं, उनकी कुल संख्या 77,591 है। लेकिन मैं मानती हूँ कि यह संख्या बहुत कम है। जब मैंने आकलन किया तो वहाँ इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि वहाँ जो किसान छूट चुके हैं, उनका सही तरह से आकलन हो और उनको मुआवजा मिले।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री सी.पी. जोशी को श्रीमती संध्या राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में 90 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर है। पिछले चार दिनों से अचानक बेमौसम बरसात हो रही है। भयानक ओलावृष्टि और चक्रवात से किसानों की संपूर्ण फसलें नष्ट हो गई हैं। यह जनपद के कृषकों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पूरे प्रयागराज जनपद में विशेष कर यमुनापार, करछना, बारा, सोरांव, शंकरगढ़ और गंगापार के एक बड़े हिस्से में ओलावृष्टि और चक्रवात हुआ है। इससे वहाँ की पूरी फसल तबाह और बर्बाद हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान का परीक्षण कराकर किसानों को यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति हेतु निर्देश देने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती केसरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, India's forests are currently governed by the National Forest Policy of 1988, an update to which is

the need of the hour. Key policies regarding forests and forest management are either missing, delayed or left open-ended as of date. For example, at present, there is no clear definition of forest that is accepted nationally and States are left to determine their definition of forests. There exists no clear rule regarding protection of untouched forests. This is the reason why, numerous plots of forest areas are lost. Several Government reports over the past five years have pushed for the involvement of the private sector in managing the forests, this is a huge threat to the tribal population. Even though the forest coverage area has increased since 2017, the same has decreased when seen in perspective of tribal inhabited areas.

Thus, I request the Minister to come up with a Forest Policy which will protect both, environment and people depending on forest produce as soon as possible. This will help in preventing the indiscriminate fall of trees.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। भारत सरकार ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। जितनी भी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, उन सब को बंद करने का काम किया गया है। पूरे भारत में यह कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। मेरे क्षेत्र में तीन ऐसे स्थान हैं, जहाँ मानव रहित रेल क्रॉसिंग बंद हो जाने से बच्चों का आवागमन और मुख्य मार्ग पर आने का रास्ता बंद हो गया है। वहाँ ग्रामवासियों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रेलवे विभाग तत्काल हमारे यहाँ तीन अण्डरपास बना दे। मांडा ब्लॉक में उमापुर गाँव में, उरवा ब्लॉक के सोनई गाँव में और कठौली गाँव के सामने जो क्रॉसिंग्स बंद हुई हैं, वहाँ अण्डरपास बनाकर लोगों को आवागमन के लिए सहूलियत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान लोकहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

महोदय, 217 किलोमीटर लंबा एन.एच.104 मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो शून्य किलोमीटर चकिया से शिवहर नगर – सीतामढ़ी – जयनगर होते हुए नरहरिया तक जाती है। ज्ञात हो कि उक्त सड़क के फतेहपुर गढ़ से शिवहर नगर के रशीदपुर तक काफी घनी बस्ती है। जहाँ बाईपास नहीं होने के कारण प्राय: जाम की समस्या बनी रहती है तथा आवागमन पूरी तरह से अवरूद्ध हो जाता है। इससे व्यापारियों और आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा बड़े वाहनों के परिचालन पर सुबह **8** बजे से रात 8 बजे तक रोक लगाये जाने के कारण दूर-दराज से आने वाली गाड़ियों की लाइन लग जाती है।

इसमें लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं के वाहन भी होते हैं। विदित है कि शिवहर एक जिला मुख्यालय है जहां कोई बाईपास सड़क नहीं है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि एनएच 104 के फतेहपुर गढ़ से शिवहर नगर के रशीदपुर तक लगभग पांच किलोमीटर लम्बे बाईपास का निर्माण कराया जाए जिससे कि 217 किलोमीटर लम्बी इस महत्वाकांक्षी सड़क से गाड़ियों का परिचालन निर्बाध रूप से सुचारू हो सके।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से पहले भी मांग की थी कि भावनगर से मुम्बई की प्रात:कालीन फ्लाइट चलाई जाए।

भावनगर और मुम्बई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यापारिक तरीके से ऐसे जुड़े हैं जैसे दोनों ट्विन सिटीज हैं। यहां एशिया का सबसे बड़ा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है। वेलवदर में नेशनल ब्लैकबक सैंचुरी है, पालीताणा जैनियों का बड़ा तीर्थ स्थल है, बगदाणा भी बहुत बड़ा पवित्र तीर्थस्थल है। इस वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग हर रोज मुम्बई आना-जाना करते हैं। यहां से एक फ्लाइट शाम को चालू है, लेकिन वह भी रेगुलर टाइम पर नहीं आती है और लोगों को परेशानी होती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि भावनगर से मुम्बई की प्रात:कालीन फ्लाइट जल्द से जल्द शुरू कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. भारतीबेन डी. श्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना वायरस सब जगह चल रहा है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, भारत में कुछ प्राब्लम नहीं है।

आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दामोदर वैली कार्पोरेशन पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों में है। इसका कोई परमानेंट चेयरमैन अभी तक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से पावर मिनिस्ट्री से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, दामोदर वैली का परमानेंट चेयरमैन बनाएं, क्योंकि यहां चोरी हो रही है और लेबर्स की पेमेंट नहीं हो रही है। यहां 20,000 वर्कर्स की जगह है जहां 6,000 पावर का पावर प्लांट है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली डीबीसी का चेयरमैन बनाया जाए, यह बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सौमित्र खान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*__SHRI MOHAMMAD SADIQUE (FARIDKOT):__ Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on a matter of urgent public importance.

Sir, I urge upon the Tourism Minister to kindly listen to my demand. I hail from a place that is home of respected Baba Farid. It is a historic tourist place. An annual fair is held here in the memory of Baba Farid. The Dussehra fair is also an important occasion here.

Sir, Punjab is the land of fairs. Punjabis throng these fairs in large numbes. They even come from abroad. Celebrated Punjabi poet Dhani Ram Chatrik has said :

> "People were very happy throughout the fair
> Full of zeal and zest, the Jat came to visit the fair."

Sir, a fort is also present here. It can be turned into a museum. Tourism should be developed here and the city should become a tourism hub. This will also give boost to the business and trade in the region. Thank you. Jai Hind.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak in the 'Zero Hour'.

Sir, I would like to bring to the notice of the Central Government that about 146 Indian students got stranded in Manila Airport in Philippines. Among the 146 students, 41 belong to the State of Andhra Pradesh and around 30-40 from the State of Telangana. Most of these students have gone to pursue MBBS course in Philippines and they have reached Manila Airport on the night of 17th of March to catch the scheduled flight to India on 18th, which is Air Asia AK-585, which suddenly got cancelled by the operator. Now, with no other flights to reach India, it has been informed that the Manila International Airport is also going to be closed by today midnight. All these students are panicking at the airport and their families are also in a very worried position.

Regarding this issue, our hon. leader Chandrababu Naidu Garu has also written a letter to the Minister of External Affairs. I request the Ministry to take immediate and necessary steps to bring back our people home during this troubled time. The special flight to Hyderabad, in addition to the one operating to Delhi, would also allow these people to reach their homes safely.

In regard to this, there are 53 other people who are stranded in Malaysia also. The Ministry of External Affairs is doing an excellent job. I would like to praise the Ministry, the aviation industry, the media industry and especially the doctors, nurses and everyone working in the hospitals. Once again, on behalf

of the House, I would like to thank all of them for their service in this troubled time. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और **डॉ**. कलानिधि वीरास्वामी को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय को उठाने की इजाजत दी है, इसके लिए धन्यवाद। बिहार राज्य में मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा से एन.एच.-107 महेशखूंट से पूर्णिया गुजरती है। मधेपुरा से सहरसा पथ 18 किलोमीटर काफी जर्जर है। मधेपुरा भी जिला मुख्यालय है और सहरसा भी जिला मुख्यालय है। लेकिन, वहां स्थिति इतनी खराब है कि उससे आवागमन नहीं के बराबर है। मैं इस विषय में माननीय मंत्री जी से मिला था और उन्होंने इसकी मरम्मती के लिए 9 करोड़ रुपये की मंजूरी अपने मंत्रालय से करवाई थी। लेकिन, दु:ख की बात है कि बड़ा कांट्रैक्टर गैमन इंडिया जो पहले से उसमें कार्य कर रहा है, फिर से इस काम को उसी को दिया गया और उसको 3 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है। भुगतान होने के बाद भी वह सड़क की मरम्मती नहीं कर रहा है। इससे आम लोग बहुत परेशान हैं। गाड़ियां गड्ढे में गिर जाती हैं, रोड जाम हो जाता है। इसलिए, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक पर सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द मधेपुरा से सहरसा तक, जो जिला मुख्यालय है, उसकी मरम्मती हो।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अभी राम मोहन नायडू जी ने जो विषय रखा है, लगभग वही समस्या मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ छात्रों की भी है। मनीला, फिलीपींस के अंदर जो पिनस सिटी मेट्रो है, वहा पर ये बच्चे फंसे हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के तेंदूखेड़ा शहर के सजल शर्मा और उसके अन्य मित्र, जो लगातार भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन, जैसा आप जानते हैं, सारे एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, सभी देशों ने लगभग अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी

हैं। मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि सजल शर्मा जैसे बच्चे जो विदेशों में फंसे हुए हैं, जब तक कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम वहां अपने दूतावास को इस हेतु आदेशित करें कि जो इंडियन कम्युनिटी के बच्चे वहां पर हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, उन बच्चों से सम्पर्क करके यथासंभव उनकी मदद करें तथा उनको ढाढस बंधाने का काम करें। आपके माध्यम से मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

18.43 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
15th Report

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का 15 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे बांग्ला भाषा में बोलने की परमिशन दी, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।

*Sir today, I take the floor to highlight a particular issue with regard to my state West Bengal and my constituency as well. In our state, people from the Kol tribe are found in various districts. But the Kols are not included in the Scheduled Tribe list of the Central Government as a result of which, these people are losing the essence of their culture and tradition. They are moving away from their cultural heritage. A survey was conducted by the Government of West Bengal, and on 7th November, 2017 a letter was sent to the Centre proposing their inclusion. The Memo No. of the letter is 4252BWMR105/12 dt. November 14, 2012. It was specifically requested through that letter that the Kol tribe may be incorporated in the ST list. So I urge upon Hon. Minister Shri Arjun Munda to acknowledge the proposal of the Government of West Bengal and include this tribe in the ST list at the earliest.

Thank you sir.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you, hon. Speaker, Sir, for allowing me to speak on the issue of Corona Virus. While I thank the Central Government for all the arrangements, I wish to bring this to the notice of the House that Lakshadweep is an isolated and far flung area. There are many issues in front of us. I have to miss these two sessions of the House and go back to Lakshadweep to have a discussion with the Administrator.

Sir, around 3000 students from my constituency are studying in institutes and colleges all across India. Now, when these institutes and colleges have been closed, we have to transport these students back to Lakshadweep.

Sir, the spreading of Corona Virus in Lakshadweep is only possible to reach from outside. So, we took a decision to stop all international and domestic tourists coming to Lakshadweep.

I have only one suggestion to give to the Government of India. We have three major ports where ship operation happens. These are Kochi, Calicut and Mangalore. On the one hand, we have a shortage of medical assistants for the thermal scanning and screening and on the other, there are many unscanned and unscreened cargo vessels filled with supplies of provisional items.

I would first urge the Central Government to extend medical assistance to Lakshadweep by sending medical teams and second to expand the bandwidth for better communication with the people. Thank you.

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो बैकवर्ड एरिया है। कालाहाण्डी, ओडिशा में चार केन्द्रीय विद्यालय हैं और तीन केन्द्रीय विद्यालय के लिए बिल्डिंग नहीं बनी है, जिसके कारण प्लस 2 क्लास नहीं चल पा रही है। इसी के साथ-साथ तीन विधान सभा क्षेत्र, नरला, लांजीगढ़ और जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रामपुर, जूनागढ़ और लांजीगढ़, जहां पर वेदान्ता एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, वहां पर तीन नए केन्द्रीय विद्यालय खुलवाए जाएं और जहां पर चार केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनमें से धर्मगढ़ को हार्ड स्टेशन घोषित किया जाए। नुआपड़ा, खड़िआल और धर्मगढ़ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और वहां पर प्लस 2 क्लास खोलने के लिए इजाजत दी जाए। मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर तुरंत कदम उठाया जाए।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Speaker, Sir, there are about 50 fishermen from Nagapattinam district employed in Iran for fishing activities. Due to spread of Corona Virus, the Government of Iran has not allowed them to return to India. They are struggling there without adequate food, water and shelter. All of them are very poor.

Through you, Sir, I would urge upon the Government to take immediate steps on a war-footing maner to bring these fishermen safely back to India. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री एम. सेल्वराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अहमदाबाद से अमृतसर के बीच कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। गुजरात में बनासकांठा, मेहसाणा और पाटन से यात्रा में जाने वाले जो यात्री हैं, उनको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है। वहां के सभी लोगों ने और हमारे पदाधिकारियों ने पत्राचार के माध्यम से ट्रेन नम्बर 19611/19612 और 19613/ 19614 को अजमेर से अमृतसर वाया अहमदाबाद चलाने के लिए आग्रह किया है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अत: मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये ट्रेन्स अमृतसर वाया अहमदाबाद होते हुए चलाई जाए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, आज मेरा एक प्रश्न था, लेकिन नहीं आ पाया। उसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैंने महानन्दा रिवर लिंकिंग के बारे में प्रश्न पूछा था। मेरे क्षेत्र में अक्सर फ्लड आता है और वहां ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। मैं आपके माध्यम से महानन्दा बेसिन को बनाने की रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे जल्द से जल्द वारफूटिंग पर किया जाए। जवाब में बताया गया था कि कोसी का पानी महानन्दा में कनेक्ट करके लाया जाएगा, लेकिन उससे फ्लड और आएगा। मेरा सवाल था कि महानन्दा का पानी कोसी के माध्यम से साउथ बिहार में दिया जाए, जहां पानी की किल्लत है। इससे वहां पानी भी हो जाएगा और हमारे यहां फ्लड की सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी। आपके माध्यम से मेरी यही डिमाण्ड है कि रिवर लिंकिंग इस तर्ज पर की जाए और महानन्दा बेसिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे हम फ्लड से बच सकें।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Tourism to the need to construct a Yatri Niwas at Anjanadri Hills which is the birthplace of Lord Hanuman in the State of Karnataka.

Sir, I belong to Koppal parliamentary constituency of North Karnataka. There are lot of world heritage centres and historical locations. Historical locations like sites of Western Chalukya, Rashtrakuta Dynasty, Kadamba Dynasty are some of the most visited tourist places in North Karnataka.

It is also noticed that three most important forts - Koppal Fort, Anegundi Fort and Kampli Fort – are situated in my Koppal parliamentary constituency which attracts lot of tourists. There is an urgent need of funds for the development of these three forts so that they can attract more tourists.

I would also like to mention that Hampi, the world tourism place, is situated in Bellary District which is very near to the Koppal District. Hampi, which is a historical place in India, is recognised by the World UNESCO also.

There is one tourist place called Anjanadri Hills which is situated in Gangavati Taluk near Anegundi and is the birthplace of Lord Hanuman. Thousands of people from different places, not only from India but also from foreign countries, visit this place daily to have darshan of Lord Hanuman, but these tourists are facing difficulties due to non-availability of a Yatri Niwas. There is an urgent need to construct a Yatri Niwas at this place.

Keeping in view the above, I urge upon the Union Government to take immediate action for the construction of a Yatri Niwas at Anjanadri Hills, which is the birthplace of Lord Hanuman in the State of Karnataka, for the benefit of tourists. Thank you.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे जिला सहारनपुर की तहसील बेहट के एक किसान, जिसका नाम वेदपाल, पुत्र मोहर सिंह है, ने आत्महत्या कर ली, जिसकी कुल उम्र 47 साल थी और उसके चार बच्चे हैं। उसने आत्महत्या पंजाब नेशनल बैंक के सामने की, उस बैंक के सिर्फ 11,000 रुपये, जो सूद के बनते थे, उस पर बाकी थे। मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए, उसके परिवार की सहायता की जाए और यदि उस पर कोई कर्ज है तो उसे माफ करने के लिए आप आदेश देने की कृपा करें।

इसके अलावा, जिला सहारनपुर के अंदर पिछले दिनों बारिश और ओले की वजह से फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। मेरी मांग है कि वहां के किसानों की सहायता की जाए और अगर कोई कर्ज है तो उनको माफ किया जाए। मैं इसके अलावा एक अन्य बात कहना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे जिले में गन्ने की बहुत पैदावार होती है, लेकिन वहां पर मिल्स एक-एक साल तक उनकी पेमेंट नहीं करती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको पेमेंट दिलाई जाए और साथ ही उनके सूद की अदायगी भी की जाए।

جناب حاجی فضل الرحمٰن صاحب (سہارنپور): جناب، اسپیکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے ضلع سہارنپورکی تحصیل بیہٹ کے ایک کسان جس کا نام ویدپال، پُتر موہر سنگھ ہے نے خودکشی کر لی، جس کی کُل عمر 47 سال تھی اور اس کے چار بچے ہیں۔ اس نے خودکشی پنجاب نیشنل بینک کے سامنے کی، اس بینک نے صرف 11000 روپئے جو سود کے بنتے تھے، اس پر باقی تھے۔ میری مانگ ہے کہ اس کی جانچ کرائے جائے، اس کی فیملی کی مدد کی جائے اور اگر اس پر کوئی قرض ہے تو اسے معاف کرنے کے لئے آپ حکم دینے کی مہربانی کریں۔

اس کے علاوہ ضلع سہارنپورپچھلے دنوں بارش اور اولے کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ میری مانگ ہے کہ وہاں کے کسانوں کی مدد کی جائے اور اگر کوئی قرض ہے تو اسے معاف کیا جائے۔ میں اس کے علاوہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔

جناب، میرے ضلع میں گنّے کی بہت پیداوار ہوتی ہے، لیکن وہاں پر مِلیں ایک۔ایک۔ سال تک ان کی پیمینٹ نہیں کرتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو پیمینٹ دلائی جائے اور ساتھ ہی ان کو سود کی ادائیگی بھی کی جائے۔ شکریہ...

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Sir, almost 30 years before 1857's First War of Independence, a unique saga of supreme courage and sacrifice manifested in the present districts of Bargarh, Jharsuguda and Sambalpur, which are parts of my constituency, and also in other areas of Odisha where so many members of one family dedicated their lives for the cause of the nation. Surendra Sai, his uncle Balaram Sai and brothers Udanta Sai and Medini Sai died in jail.

Another brother, Ujwal Sai was hanged and Chabila Sai was killed in the War. Both Dhrub Sai and son Mitrabhanu Sai though released after 12 years of imprisonment were debarred from entering the town. Madho Singh and his son Kunjal Singh of Village Ghess in the District of Bargarh were hanged. The history is very long.

My submission is that the hon. Minister of Culture and Tourism should take up this cause and give direction to re-write history and sanction funds for protection, renovation and construction of many such heritage centres in the District of Bargarh, Jharsuguda and Sambalpur.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Pujari.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Mr. Speaker, Sir, thank you.

I wish to bring to your notice that thousands of Indian students, including hundreds of them hailing from my State of Tamil Nadu, who are studying in medical colleges in Philippines, are unable to return to India. They are afraid of the Corona Virus attack. The Government of Philippines has already ordered them to move out of their country. The parents of those students are very much worried about their children getting stuck in Philippines.

Also, 70 more IT professionals and businessmen from Tamil Nadu are stranded in Kuala Lumpur Airport. They are able to neither enter Malaysia nor able to fly back to India. They are not allowed to enter into the aircraft as they are holding Indian passport. At this juncture I urge upon the Union Government to arrange for rescuing all those Indians, including students, from this critical situation.

Recently, a 20-year old boy from Uttar Pradesh who travelled from Delhi to Chennai was admitted and has tested positive for Corona Virus.

So, I urge upon the Government to increase the facilities for conducting scanning tests in all the railway stations. Thank you.

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak during 'Zero Hour'.

I would like to speak on the Corona Virus which is engulfing the whole world, including our country. The number of patients is increasing day by day. I would like to congratulate the Government for making the best efforts possible to control the spread of this virus. But as you can see, the number of patients is increasing every day and is putting a heavy burden on the Government machinery which is available in our country.

Through you, I would like to make a request to the Government to use the facilities of private medical colleges. For example, in my Ahmednagar Lok Sabha Constituency, there are two private medical colleges. I had a word with both of them. They are ready to offer 100 beds each for quarantine facility to the Government. If the Government makes it compulsory for the private medical colleges, which are 1000 bedded and are being monitored by the Board of Governors under the control of Government of India, I think, 5.000 beds would be available all over the country for quarantine.

I think it is the job of all of us to fight against this virus. It is not just the responsibility of the Government. Thank you so much.

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. सुजय विखे पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak during 'Zero Hour'.

The Coronation Bridge of North Bengal was constructed by the British rulers years back in 1937 over the Teesta River which connects a large part of Dooars with Terai. Thousands of people come to Siliguri this way. Siliguri, as we all know, is the nerve centre of North Bengal and North-Eastern region of India. Even the Bhutanese depend upon this age-old Bridge to maintain their link with our country.

Strategically also, this Bridge is of great importance because of its proximity to China. Age has worn out this Bridge and now it is in a very precarious condition. I wonder that it may collapse at any time.

Therefore, I would like to propose that an alternative bridge be constructed close-by this one. I request the Government to start the construction process without any further delay. The earlier the better.

19.00 hrs

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों का विषय महत्वपूर्ण है। क्या यह पर कोई बिना महत्वपूर्ण वाला विषय रखा जाता है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह अलग से महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज दुनिया कोरोना वायरस के दहशत से भयभीत है। इस तरह की कई संक्रामक बीमारियों का हमारा देश भारत और दुनिया सामना कर चुके हैं, चेचक, हैजा, प्लेग और टीबी। हम किसान हैं और अपने जीवन को प्राकृति से जोड़ कर रखते हैं। हमारे जीवन का संबंध आध्यात्मिक क्षेत्र से है। मैं अपने अनुभव के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि पंचगव्य के हवन करने से जो धुआं निकलता है, वह वातावरण के सारे विषैले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। यह वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हो चुका है। यह अंधविश्वास नहीं है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आपके माध्यम से यह संदेश जाना चाहिए कि देश का यह संसद भी हवन करे और सारे माननीय सांसद भी अपने क्षेत्र में हवन कराएं। कोई कोरोना वायरस किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं। मंडी गोविंदगढ़ में स्टील की बहुत इंडस्ट्रीज हैं, खन्ना में कैटल फीड की इंडस्ट्रीज हैं, साहनेवाल में साइकल का मेन हब है, वहां साइकल इंडस्ट्रीज हैं, प्लाईवुड इंडसट्रीज हैं। देश और दुनिया में स्लो डाउन है। कोरोना वायरस की वजह से न तो उनको माल मिल रहा है और न उसे कोई बेचने वाला मिल रहा है। सारी इंडस्ट्रीज कह रही हैं कि भारत सरकार से निवेदन करें कि कोई न कोई मदद करे। कई लोग कह रहे हैं कि उनके पास मजदूरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार कोई अच्छी पॉलिसी बनाए, जिससे उनकी मदद हो सके।

श्री देवजी पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है। आपको ज्ञात है कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं प्रधान मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अभी उन्होंने नर्मदा के लिए 155 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन डीआर, एफआर और ईआर प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए धन की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार हर जगह पर फेल हो रही है। हमें डीआर, एफआर और ईआर प्रोजेक्ट्स में जो कार्य करना है, उसके लिए वह पैसा नहीं दे रही है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार, प्रधान मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नर्मदा, बतीसा नाला बांध परियोजना और सालगांव डैम, तीनों के लिए हमें विशेष पैकेज मिलेगा तो वर्ष 2024 तक हमें हर घर को जल देना है, उस जल का सपना हम वहीं से स्रोत बना कर पूरा कर पाएंगे। साबरमती बेसिन से जवाई नदी का पुनर्भरण करना है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सड़क परिवहन और राजमार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग – 85, जो छपरा, सिवान और गोपालगंज को जोड़ती है, वह काफी प्रमुख सड़क है। यह सड़क पहले से बनी है, लेकिन अधूरी है।

मेरा आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी और सरकार से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि वहां एक आरओबी एकमा और आमदाढ़ी के बीच में बन रहा है, उसको तुरंत पूरा किया जाए।

सड़क के किनारे कोपा, एकमा दाऊदपुर और रसूलपुर में लाइटें लगाई गई हैं, वे करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक वे लाइटें काम नहीं कर रही हैं, वे जल नहीं रही हैं। ये दोनों कामों को शीघ्र पूरा किया जाए और उसके साथ ही जो कुछ अधूरे नाले हैं, उनको पूरा किया जाए। महोदय, आपके माध्यम से यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं यहां केन्द्र सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, खास कर एविएशन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कल शाम तक हमारे पास एक कम्प्लेंट आई कि कई लोग जो फिलिपिंस में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, वे सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसे हैं। वे 50 से ज्यादा बच्चे 24 घंटे के भीतर आज फ्लाइट में हैं और जल्द से जल्द मुंबई आने वाले हैं।

इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि कई डॉक्टर्स भी ताशकंद में फंसे हुए हैं। जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, सबसे पहले उनको लाना जरूरी है, क्योंकि वे वापस भी नहीं जा सकते और भारत भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भारत ने

एडवाइज़री जारी की है। इसलिए जिस प्रकार से, इन बच्चों को लाया गया है, वैसे ही अलग-अलग देशों में जो लोग फंसे हैं, जो ट्रांजिट में हैं, उनको प्रायरिटी देकर जल्द-से-जल्द लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय अध्यक्ष जी, देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ शहद उत्पादन नहीं होता हो। इन राज्यों के लगभग ढाई लाख से अधिक किसानों के अथक परिश्रम के कारण ही हमारे देश से वर्ष 2017-18 में 51,547 मीट्रिक टन शहद का निर्यात संभव हो पाया था। पिछले कुछ वर्षों से पड़ोसी देश चीन ने शहद बाज़ार में अपना वर्चस्व बनाए रखने की होड़ में नकली शहद के माध्यम से भारत के शहद बाज़ार में अपना हस्तक्षेप किया है। इस काम में भारत की नामी कम्पनियाँ भी चीन की मदद से नकली शहद बाज़ारों में बेच रही हैं। परिणामस्वरूप भारत के शहद उत्पादकों को अपने उत्पाद आधे मूल्य पर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देश की कुछ बड़ी कम्पनियाँ शहद में सीरप मिलाकर देश में ही नहीं अन्य देशों को भी निर्यात कर रही हैं। सीरप 40-42 रुपये किलो के भाव से खरीदकर शहद में मिलाया जाता है। देश में जो कम्पनियाँ सीरप को सप्लाई करती हैं, वे भी बिना बिल के करती हैं, क्योंकि उन पर 18 परसेंट जीएसटी नहीं लगता है। इसलिए सीरप पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए, क्योंकि काफी मात्रा में कई देशों से इसका आयात किया जाता है।

मैं सरकार का आभारी हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली 'निर्यात निरीक्षण परिषद्' ने अमेरिका, यूरोप तथा अन्य खाड़ी देशों में निर्यात होने वाले शहद में मिलावट को रोकने के लिए जाँच प्रणाली एनएमआर को 1 अगस्त, 2020 से अनिवार्य कर दिया है, जबकि इसे 1 अप्रैल, 2020 से ही लागू किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगस्त, 2020 तक तो शहद का सीजन ही समाप्त हो जाएगा और सारा शहद तब तक निर्यात हो जाएगा। अगर सरकार 1 अप्रैल,

2020 को जाँच की पुख्ता प्रणाली एनएमआर को लागू करने का आदेश देती है, तो देश के ईमानदार शहद उत्पादकों व मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को उचित लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, केवल एक मिनट के बाद आपका माइक बंद होने वाला है।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च को भगत सिंह जी का शहीदी दिवस आ रहा है। जब उन्होंने शहादत दी, तब उनकी आयु भी 23 साल थी। उन्होंने जेल में कहा था-

> "मैं रहूँ या न रहूँ, पर यह वादा है तुमसे,
> मेरे मरने के बाद वतन पे शहादत देने वालों का सैलाब आ जाएगा।"

बात इतनी है कि लोग इंडिविजुअल मरे या मार दिए जाएँ, लेकिन आइडिया जिन्दा रहता है, सोच जिन्दा रहती है, बड़े-बड़े एम्पायर खत्म हो गए, लेकिन सोच जिन्दा रही।

सर, मेरी दो माँगें हैं। एक, पाकिस्तान में उनको जिस रस्से से फांसी दी गई थी, वह रस्सा और आखिरी दिनों में उन्होंने जो किताबें पढ़ी थीं, उनको पाकिस्तान से मँगवाया जाए।

दूसरी बात, हरियाणा और पंजाब मान चुके हैं, श्री पुरी साहब यहाँ पर बैठे हैं, 23 तारीख को यह फैसला किया जाए। चंडीगढ़ के मोहाली में जो एयरपोर्ट है, उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला करें। हरियाणा और पंजाब के सदनों में शहीद भगत सिंह के नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम रखने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है।

इसलिए आपसे आग्रह है कि 23 तारीख को उस एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): माननीय स्पीकर सर, मैं जिस संसदीय क्षेत्र- झालावाड़-बारां से आता हूँ, वहाँ मुकुन्दा टाईगर रिज़र्व है। यह लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ तीन टाईगर आ चुके हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने इसे पर्यटन के लिए नहीं खोला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप केन्द्रीय मंत्री से बात करके, इसमें आपका क्षेत्र भी पड़ता है, कोटा, झालावाड़ और बारां में पर्यटन के लिए इसे खोला जाए, ताकि लोगों को काम मिले और इस क्षेत्र में काम हो।

इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि केन्द्रीय मंत्री से बात करके इसे खुलवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुष्यंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you, Sir.

Thank you for the opportunity.

Firstly, I would like to associate with Shri Ram Mohan Naidu, Dr. Shrikant Shinde and anyone who spoke about the students who are stranded at the airport in Philippines.

उनके लगेज भी चैक-इन हुए थे, बोर्डिंग पासेस भी मिले थे, लेकिन वापस कर दिए गए थे। I would say something else in a few minutes. दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के पास में ही, कनॉट प्लेस में मैं गाड़ी से गुज़र रहा था। वहां एक महिला थी। She was pregnant. उस महिला के साथ बाकी चार-पांच महिलाएं कुछ बच्चों को लेकर, they were begging. वे महिलाएं मेरी गाड़ी के पास आकर पैसे मांग रही थीं कि उनको अस्पताल जाना है। मैंने उनसे यह कहा कि आप

चाहे तो मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं या अस्पताल जाने के लिए मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। I am ready to provide any kind of help you need, लेकिन उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे।

सर, यह क्लियर बता रहा था कि बैगिंग एक पेशा बन चुका है। There is a big racket. सरकार को इसके लिए बहुत तरीके से सोचना चाहिए। They must come out with some laws for abolition of begging. इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है। ये लोग दूसरे के बच्चों को लाकर कहते हैं कि वे उनके बच्चे हैं, उनको लेकर धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं। इससे हमारे देश के बच्चों को बहुत खतरा है। I would request through you the Government of India and Treasury Benches कि वे इस विषय पर अपनी नज़र डालें। यह हमारे साथ दिल्ली में ही हो रहा है। आप लोग तो अपनी गाड़ियों में कॉरिडोर्स में जाते होंगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस विषय पर सरकार ध्यान दे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अनुभव मोहंती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SUBHAS SARKAR (BANKURA): Sir, I am grateful to you. People of Kolkata and West Bengal are in serious apprehension of Coronavirus. Why? It is because of State Government's negligence and also because of bureaucrats. On 15th March, the last Sunday, a young son of a bureaucrat came to Kolkata from London, with a history of Coronavirus positive. After that, on Monday, he was advised to get admitted in the designated Central Government hospital but he refused. …(*Interruptions*) He went everywhere in Kolkata including Nabanna…(*Interruptions*) According to my knowledge, Coronavirus kills two to three per cent of the affected people but how many people would be killed by the ill powered State Government and the

bureaucrats? My appeal to the Ministry of Health, through you, Sir, is that it should send a communication to the State Government seeking its explanation on this issue. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. सुभाष सरकार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनार्दन मिश्र जी – एक मिनट बाद आपका माइक बंद हो जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, देश कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कृतसंकल्पित है। स्कूल, कॉलेज बंद हैं, सामाजिक समारोह स्थगित किए जा रहे हैं, परंतु शाहीन बाग, दिल्ली में तथाकथित सीएए विरोधी आंदोलन जारी है। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि सीएए से किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाने वाली है।

अध्यक्ष जी, वास्तव में इन आंदोलनकारियों को इस बात की आशंका है कि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने वाले हैं, जिससे ग़ज़वा-ए-हिन्द का सिद्धांत मानने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर इस देश में इस्लामिक राज्य की योजना को अंजाम देना संभव नहीं हो पाएगा। इस संभावित कानून के डर के कारण यह आंदोलन चलाया जा रहा है।

अत: आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस आंदोलन को समाप्त कर केन्द्र सरकार जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अमरोहा-गढ़मुक्तेश्वर में किसान बहुत गन्ना पैदा करते हैं। मेरे यहां गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सिंभावली शुगर फैक्ट्री है, जिसकी चीनी आप अक्सर एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज वहां चीनी का उत्पादन तो बहुत है, उनके पास बहुत स्टॉक भी है, लेकिन किसानों को पिछले साल का, वर्ष 2019 के मार्च तक का पैसा भी नहीं मिला है, इस साल का तो छोड़ ही दीजिए। इससे किसान बहुत परेशान हैं।

ऐसी ही धनौरा में वेव फैक्ट्री है। वहां भी बकाया का पेमेंट नहीं हो रहा है। केन्द्र में जो बीजेपी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह कहा था कि वे किसानों का बकाया दिलाएंगे, लेकिन किसानों को उनके गन्ने का बकाया नहीं मिल रहा है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि वह इस दिशा में संबंधित विभाग को निर्देशित करे। धन्यवाद।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए मुझे मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मेरा जमशेदपुर लोक सभा बहुत बड़ी उद्योग नगरी है। वहां टाटा घराना है। मैं अपने क्षेत्र में दलभुमगढ़ एयरपोर्ट का विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर धालभूमगढ़ में जो एयरपोर्ट बनना है, वह पिछली जनवरी में तत्कालीन मुख्य मंत्री और तत्कालीन राज्य मंत्री आदरणीय जयंत सिन्हा ने एयरपोर्ट की भूमि का पूजन किया था। इसके लिए ए.आई. द्वारा 100 करोड़ रुपये आबंटन किए गए हैं, लेकिन वन पर्यावरण विभाग द्वारा अभी तक अनापत्ति सर्टिफिकेट न देने के कारण आज तक एयरपोर्ट का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि

जल्द से जल्द वन विभाग द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान करवाने की कृपा करें, ताकि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रधान मंत्री जी 8 बजे मन की बात करेंगे, उससे पहले आपने मुझे संसद में मान की बात सुनाने का मौका दिया। पंजाब अग्रेरियन स्टेट है, खेती प्रधान स्टेट है। जब देश अनाज के अभाव से प्रभावित था तो पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति के जरिये देश को अनाज में आत्मनिर्भर किया, लेकिन एफ.सी.आई. का एक फैसला आ रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम फसल खरीदने में 50 परसेंट की कमी करेंगे।

सर, पंजाब की फूड एजेंसीज हैं। जैसे, पनग्रेन और मार्कफैड एजेंसीज हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। जो प्राइवेट सेलर हैं, वे पहले ही कानून से दुखी हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए हमें और फसलों की एम.एस.पी. दी जाए, ताकि हमारा पानी बच सके और हमारा किसान भी आत्मनिर्भर हो सके।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, there are totally 8.5 lakh pharmacies in India under which more than 50 lakh employees are working and there are more than 2 crore people who are dependent upon such employment. Our country is going through a bad economic phase which is almost on the verge of recession. In this kind of a situation, all these online pharmacies and online marketing are going to create a greater problem of unemployment in the near future. I request the Government to consider banning of e-pharmacies and any kind of e-transactions so that employment can be generated where more people can be given jobs. With the prevalence of coronavirus, the economy is going to get even worse and our GDP may fall

by more than 20 or 30 per cent. Keeping this in mind, I request Government to consider this point and do the needful.

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पालघर के अंतर्गत जवाहर नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र राज्य के सहयोग से केन्द्र सरकार डहानू तालुका में स्थित वाढवन में वाणिज्यिक बंदरगाह बनाने जा रही है। वर्ष 2015 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके सरकार ने अडानी नामक व्यक्ति को देना तय किया है। यह 65 हजार करोड़ रुपये का बंदरगाह बनाने जा रही है। यह बंदरगाह लगभग **5** हजार एकड़ में समुद्र की तटीय बैल्ट में बनने जा रहा है। पालघर के जो मछुआरे हैं, उनका काफी नुकसान होगा और पर्यावरण का भी काफी नुकसान होगा। जब विधान सभा और जिलों का चुनाव था तो उन लोगों ने वहां बायकॉट किया। मेरा निवेदन है कि इस बंदरगाह को किसी अन्य क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाए।

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Sir, this is regarding selling medicines online. There is no doubt, medicines are essential not only to human beings but also animals and other species. I would like to stress upon the hazardous and potent drugs that fall under Schedule H, H1, narcotics & Psychotropic steroids generally used in the treatment of menstrual cycle of women which are prescribed by the specialist doctors after physical diagnosis of patients are being sold by e-pharmacies. In addition to this, spurious sexual drugs and abortion pills are also being sold by e-pharmacies without due certification and checks. It needs to be looked into and regulated.

I, therefore, request the hon. Minister of Health & Family Welfare through you, Sir, to look into this serious matter and take necessary steps.

*SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Many Members have spoken here in this august House about the safe return of Indians stranded abroad, particularly from Iran which is one of the most affected countries in the world as regards Coronavirus. Several Indians are stranded there. For the last 22 days or so they have been struggling there in Iran without food and drinking water. They did not get food at least one time a day. Moreover they were left with no option but to boil and drink some substandard water which can only be used for bathing purposes. These Indians are in constant touch with the Indian Embassy in Iran for getting help to return back to India at the earliest. Hon. External Affairs Minister while replying in this House today assured that all these Indians stranded in Iran will be brought back to India. But they are still languishing there. Many Indian students who were studying in Philippines are now stranded in Malaysia. Moreover fishermen belonging to Tamil Nadu, Gujarat and Kerala are still stranded there. I urge that Government should take immediate action to bring back all these stranded Indians to India safely very soon. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मेरा संसदीय क्षेत्र मछली शहर अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह लोक सभा क्षेत्र वाराणसी शहर का पिंडरा विधान सभा क्षेत्र, मेरे संसदीय क्षेत्र मछली शहर में आता है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के वाराणसी जिले में पिंडरा विधान सभा होने के नाते जनमानस को भरोसा है कि मछली शहर लोक सभा क्षेत्र का विकास होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मछली शहर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। दुर्घटना होने पर 120 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्राय: सुनने को मिलता है कि उक्त व्यक्ति का निधन हॉस्पिटल दूर होने के कारण रास्ते में ही हो गया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने लोक सभा क्षेत्र मछलीशहर की जनता की परेशानियों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में जनहित में अतिशीघ्र मछली शहर विधान या मड़ियाहूं में खोलने का कष्ट करें। धन्यवाद।

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Speaker, Sir, there are more than 400 confirmed Covid-19 cases in India. Lakhs of people are under observation in the country. We are facing a socioeconomic crisis in our country. Within a week, we are going to see a dangerous situation all around the world. Transportation facilities will be shut. Food material and essential commodities including medicines will be in short supply. In this situation, I strongly demand that the Central Government should announce a one-year moratorium on all loans, including all financial institutions like cooperative societies and banks.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज बहुत सारे सांसदों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कही है। मेरे पास सुबह से ही दूरभाष पर सैकड़ों लोगों के कॉल्स

आ रहे हैं, क्योंकि मेरे लोक सभा क्षेत्र के कुछ विद्यार्थी फिलीपींस में फंसे हुए हैं और वहां संस्थाओं की छुट्टी कर दी गई है। इधर, अपने यहां साधन नहीं मिल पा रहे हैं। माननीय विदेश मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था वहां पर कर दी जाए, क्योंकि उनके परिवार के लोग चिंतित हैं। इसी तरह से आर्मेनिया और कजाखस्तान में भी यही स्थिति है। मेरी लोक सभा क्षेत्र के ही 500 से अधिक छात्र इन देशों में मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। अत: मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस विषय में सहायता करें।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने देश में काफी दिक्कत हो रही हैं। खासतौर से लद्दाख से आए हुए स्टूडेंट्स, जो दिल्ली, बंगलुरु आदि शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 31 मार्च तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद होने के कारण हॉस्टल से भी उनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। तुरंत लद्दाख जाने के लिए एयर टिकट काफी महंगा हो गया है। स्टूडेंट्स को कंसेशन के लिए सात दिन पहले टिकट बुक करना पड़ता है, लेकिन अब वह सात दिनों बाद टिकट बुक करेंगे या बाहर कहीं बैठेंगे? इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल सिविल एवियेशन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जहां-जहां स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और उनके लिए जो कंसेशन है, उसे इमीजिएटली लागू करें, ताकि उन्हें सात दिनों तक इंतजार न करना पड़े।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जहां-जहां पढ़ते हैं, वहां हमारी शक्ल-सूरत को देखकर हमें चिंकी और नेपाली बोलते थे, अब कोरोना-कोरोना बोलते हैं। मेरा आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से निवेदन है कि रेशियल बेस्ड तंग न करें, हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। पहले भी भारतीय थे, अभी भी भारतीय हैं और आगे भी भारतीय रहेंगे।

श्री उपेन्द्र सिंह रावत (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन आपकी कृपा से हमें बोलने का मौका मिल गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को "खेलो इंडिया" के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस ओर ध्यान आकर्षित भी कराना चाहता हूं कि पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में इस तरह की प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जिनको मौका न मिलने की वजह से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाती हैं। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को कहना चाहता हूं कि अगर तैराकी की प्रतियोगिता को देखें तो मात्र 100 या 200 मीटर की तैराकी की प्रतियोगिता के लिए लोग आते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकते हैं। पूरा देश उन्हें देखता है, पूरी दुनिया उन्हें देखती है। लेकिन गांव में ऐसे असंख्य लोग भरे हुए हैं जो बरसात के समय में उफनती नदी में कूदकर इधर से उधर एक किलोमीटर की दूरी तय करने का काम करते हैं। उनको अगर प्रक्षिशण दिया जाए, उनको अगर मौका दिया जाए, अगर उनको ऑपर्च्यूनिटी मिले तो निश्चित रूप से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का काम करेंगे। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लिए भी कोई ऐसी योजना बनाएं कि नीचे से लोग ऊपर आ सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र बुंदेलखंड है और पूरा देश जानता है कि वहां के किसान बहुत कठिनाई में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को खेती करने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वे फसल बोते हैं। लेकिन हाल ही में ओलावृष्टि के कारण वहां बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सभी लोगों के नुकसान का आकलन करवाकर सभी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स को बोलकर उनको पैसे देने का काम किया है। मैं आपको एक मजदूर का दर्द बताना चाहता हूं। हमारे यहां के लोग खेती से पलायन करके दिल्ली और अन्य

जगहों पर मजदूरी करते हैं, उनमें से एक श्रमिक मेरे संसदीय क्षेत्र का आया और उसने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से भ्रम फैलाया जा रहा है। हम आज राशन खरीदने गए तो यहां कालाबाजारियों के कारण से, मैं आपको उस मजदूर की बात बता रहा हूं, मजदूर ने कहा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री पूरी दुनिया और देश की चिंता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन श्रमिकों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, जिन श्रमिकों को छुट्टी दी गयी है। उसने कहा है कि दिल्ली में हम दाल खरीदने या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं...(व्यवधान) मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कालाबाजारियों की सम्पत्ति को जब्त किया जाए और किसानों और मजदूरों को जो मुआवजा दिया जाता है, उसको भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के पूरा करे। धन्यवाद।

***SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. This is an important issue. Farmers have been waiting for long for the implementation of the recommendations found in the Report of the Committee led by Agricultural Scientist Prof. M. S. Swaminathan. I urge that these recommendations should be implemented by the Government soon. I request the BJP Government just to read their election manifesto once again. They have given an assurance that the agricultural inputs will not be under the ambit of tax. But now they have levied 5% GST on fertilizers and insecticides. I have learnt that this existing 5% GST may also increase to 12%. I therefore urge upon the Government that agricultural inputs like fertilizers and insecticides should be fully exempted from GST.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष जी,मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। हम इस क्षेत्र में किसानो का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब किसान अपने खेत में अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपने श्रम से अपनी पैदावार को बढ़ाता है और जब वह लहलहाती हुई फसलों को देखता है, तब उसको ऐसी प्रसन्नता होती है कि मानो वह आने पुत्र को देख रहा हो। लेकिन इस नेचुरल कैलेमिटी के कारण चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ओडिशा हो, या झारखण्ड हो, इतने बड़े पैमाने पर जो असामयिक बारिश हुई है, ओले गिरे है और तूफ़ान आया है , जिसकी वजह से उसकी आँखों का सपना टूट गया है। उसकी आँखों के सामने जो फसल खड़ी थी, वह लेट गयी है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि लैंड टू लैंड सर्वे होगा। वह लोगों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड से नहीं हो पायेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो वहां पर एक सेन्ट्रल टीम भेजी जाए। वहां पर क्राप का जो लॉस हुआ है, उसके डैमेज का आकलन किया जाए और यहां से उनकी मदद की जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आज जिन माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण अवसर नहीं मिल पाया है, मेरे पास उनके नामों की सूची है। मैं यह प्रयास करूंगा कि उन सभी माननीय सदस्यों को उस सूची के तहत बहुत जल्दी अवसर मिले।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2020 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.31 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday,March20, 2020/Phalguna 30, 1941(Saka).